चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

04 अगस्त–10 अगस्त 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

मोदी की यात्रा में अमेरिका बिछा रहा है कांटे

मोदी का साज़िश भरा स्वागत

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

एक पुरानी कहावत है, चोर से कहो, चोरी कर और साह से कहो, जागते रहो. खुद को दुनिया का दादा समझने वाला अमेरिका हमेशा से इसी नीति का पालन करता रहा है. ताज़ा मसला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा का है, जिसमें कड़वाहट पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसके लिए हथियार बनाया जा रहा है कश्मीर विवाद, ताकि मोदी की अमेरिका यात्रा कामयाब न होने पाए और उसका ठीकरा भारत के सिर पर फूटे. अमेरिका के इस दोहरेपन पर रोशनी डाल रही है चौथी दुनिया की यह स्पेशल रिपोर्ट...

प्रभात रंजन दीन

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरफ़ अमेरिका आने का न्यौता दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ उनके रास्ते में कश्मीर का कांटा बिछा रहे हैं. यह विरोधाभासी चरित्र अमेरिका अपने स्वभाव में ढोता आया है. वह कतई नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरें और रिश्तों की सबसे बड़ी बाधा कश्मीर मसले का कोई समाधान निकले. कश्मीर में स्थितियां बदलें और घाटी से भगाए गए नागरिकों को सम्मान के साथ उनके अपने घरों में बसाया जाए, यह भी अमेरिका नहीं चाहता. अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (एफबीआई) की रिपोर्ट की भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के अधिकारी जो समीक्षा कर रहे हैं, वह काफी चौंकाने वाली है. रॉ इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को ब्रीफ भी कर रही है.

दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी क़ाबिज न हो पाएं, इसके लिए अमेरिका ने काफ़ी कोशिशें कीं और काफ़ी पैसे भी ख़र्च किए, लेकिन आख़िरकार मोदी की लहरदार जीत के आगे अमेरिका ने घुटने टेक दिए. ऐसा दिखता तो है, लेकिन असलियत में ऐसा है नहीं. अमेरिका घुटने टेकने की बजाय लोमड़ी जैसी चालाकी दिखा रहा है. कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मंत्री की स्पष्ट विचारधारा और साफ़–साफ़ योजना किसी भी हाल में कारगर न हो पाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के पहले ही अमेरिका ने ख़तरनाक तैयारियां शुरू कर दी हैं. ये इतनी घातक हैं कि इन्हें आप जानेंगे, तो इसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम के बारे में आसानी से कल्पना कर लेंगे.

एफबीआई की रिपोर्ट बताती है कि जो शख़्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के एजेंट के बतौर काम करते हुए आतंकवाद फैलाने में आईएसआई की फंडिंग लेने और भारत के ख़िलाफ़ उसका इस्तेमाल करने के आरोप में अमेरिका के सख्त क़ानून के तहत गिरफ्तार किया जा चुका था, उसे रिहा कर दिया गया और मोदी के अमेरिका आगमन के पहले भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए उसे उकसाया जा रहा है, ताकि अमेरिका में मोदी की सार्वजनिक फ़ज़ीहत हो और कश्मीर मसले का एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीयकरण किया जा सके. मोदी की अमेरिका यात्रा के पहले कश्मीर को लेकर अमेरिका में भारत विरोधी माहौल फिर से बनाया जाने लगा है. अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी इन गतिविधियों का केंद्र बन रही है. रॉ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एफबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आईएसआई के इशारे पर अमेरिका में नियोजित तरीक़े से भारत विरोधी माहौल बनाने, आतंकवाद को बढ़ावा देने का जिसे आरोपी पाया गया था और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों एवं सरकार ने दस्तावेज़ों में यह स्वीकार किया था कि उसके संबंध ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जैसे कुख्यात आतंकवादी सरगनाओं से भी रहे हैं, उसे अचानक रिहा किया जाना बेहद आश्चर्यजनक है. अमेरिका की यह कार्रवाई आतंकवाद के ख़िलाफ़ साथी देशों का गिरोह बनाकर दुनिया भर में उत्पात मचाए घूमने की अमेरिकी असलियत का पर्दाफ़ाश भी है.

फई रिहा क्यों, ज़हीर मरा क्यों!

एफबीआई की रिपोर्ट के आधार पर रॉ के खुलासे में आप यह तो जान जाएंगे कि आईएसआई एजेंट के बतौर भारत के ख़िलाफ़ काम करने वाले किस व्यक्ति को अमेरिका ने रिहा कर दिया, लेकिन आप यह नहीं जान पाएंगे कि रिहा होने वाले सरगना के लिए काम करने वाले शख़्स जहीर अहमद की हत्या कैसे हो गई, किन लोगों ने उसकी हत्या की और वे कौन से महत्वपूर्ण सुराग थे, जिनके खुलने के डर से ज़हीर अहमद की हत्या कर दी गई? ज़हीर अहमद की रहस्यमय मौत पर अमेरिकी प्रशासन रहस्यमय चुप्पी साधे क्यों रह गया? उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? बाल की खाल निकालने में माहिर अमेरिका की इस हत्याकांड पर चुप्पी अपने आप ही कई सवालों के जवाब दे देती है.

इन सवालों के जवाब की तरफ़ हम आपको ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि अमेरिकी सरकार की पहल पर रिहा किए गए आईएसआई एजेंट का नाम गुलाम नबी फई है. आप सब उसका नाम और उसकी करतूतों के बारे में जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि गुलाम नबी फई और आईएसआई के बीच कड़ी का काम करने वाला ज़हीर अहमद ही वह शख़्स था, जो अलकायदा के हाथों तक परमाणु हथियार पहुंचाने की क़वायद कर रहा था. 9/11 की घटना के पहले ज़हीर अहमद ओसामा बिन लादेन और उसके ख़ास अयमान अल जवाहिरी से इस मसले पर मुलाक़ात कर चुका था. 9/11 जैसी तमाम घटनाओं के दोषी अलकायदा को परमाणु हथियार देने के लिए ज़हीर अहमद एवं पाकिस्तानी न्यूक्लियर वैज्ञानिक सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद की साठगांठ और लादेन से मुलाक़ातें कितनी गंभीर हैं, इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं. ध्यान देते चलें कि ज़हीर अहमद का रिकॉर्डेड बयान भी एजेंसी के पास उपलब्ध है, जिसमें उसने अपनी उक्त

एफबीआई की छानबीन में आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई और सीनेटर डैन बर्टन के गहरे नज़दीकी संबंधों की आधिकारिक पुष्टि हुई. फई ने ख़ुद अपने हाथों डैन बर्टन को 10,290 डॉलर दिए थे और फई की संस्था से जुड़े निदेशकों ने डैन बर्टन को अलग से 28,951 डॉलर दिए थे. इन निदेशकों ने सीनेटरों और प्रशासन को खुश करने के लिए 92,556 डॉलर ख़र्च किए थे.

गतिविधियों की स्वीकारोक्ति की है. ऐसी संवेदनशील गतिविधियों और सूचनाओं से भरे व्यक्ति की अचानक हत्या कई बातें खुद–ब–खुद साफ़ कर देती है. यह भी स्पष्ट करती है कि ज़हीर अहमद से जुड़े गुलाम नबी फई के भी न केवल आईएसआई, बल्कि अलकायदा से संबंध हैं, फिर भी उसे रिहा किया जाना विचित्र, किंतु सत्य है. और, ऐसे गंभीर मामलों में अमेरिका की चुप्पी आतंकवाद के ख़िलाफ़ वैश्विक संघर्ष के अमेरिकी ऐलान का असली चरित्र उजागर करती है. आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि ज़हीर अहमद की मौत सेरीब्रल हैमरेज से हुई, जबकि सारी स्थितियां कुछ और

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नॉर्वे को दर्द क्यों होता है!

यह भी समझना होगा कि भारत विरोधी सम्मेलन में अतिरिक्त सक्रियता और उत्साह से शरीक होने वाले नॉर्वे के सांसद लार्स राइज का क्या एजेंडा है? क्योंकि, राइज ने खुलेआम कहा कि वह फई के सम्मेलन में पहले भी आ चुके हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मज़बूती चाहते हैं और वह फई की मंशा के साथ हैं. आप याद करते चलें कि नॉर्वे ने ही मध्यस्थता के नाम पर भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में घुस कर तमिल मुक्ति चीतों (लिट्टे) और सरकार के बीच बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की थी और आख़िरकार श्रीलंका के राष्ट्रपति को ऐसे मध्यस्थों को देश से बाहर निकालने का आदेश देना पड़ा था.■

एफबीआई और सीआईए में ठनी

दुनिया भर के देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने, सत्ता पलट कराने, राजनीति में परोक्ष दख़लंदाज़ी करने और राजनीतिक हत्याएं कराने के लिए कुख्यात अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एवं फई के ख़िलाफ़ चल रही एफबीआई की जांच और कार्रवाई में हमेशा अड़ंगे डालती रही. एफबीआई ने कई बार गुलाम नबी फई को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, लेकिन सीआईए ने उसे नाक़ाम कर दिया. अमेरिका की बाह्य और आंतरिक खुफिया एजेंसियों के बीच का यह भयंकर विरोधाभास एफबीआई के दस्तावेज़ों से ही उजागर हुआ है. सीआईए कहती थी कि फई की गिरफ्तारी से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अनावश्यक तनाव बढ़ेगा. विडंबना यह है कि एफबीआई की छानबीन और रिपोर्ट पर गुलाम नबी फई ने अपने 26 पेज के इकबालिया बयान में सारे आरोप स्वीकार किए, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसकी गंभीरता इतनी ही समझी कि उसे सज़ा की अवधि के बीच में ही रिहा करा दिया. जबकि फई ने जिस तरह के कृत्य किए, उसकी अमेरिका में ही सज़ा आजीवन कारावास होती है. और तो और, अमेरिकी सरकार ने उन सीनेटरों की संदेहास्पद भूमिका की भी जांच नहीं कराई, जो दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ अंतरंग थे.■

मनमोहन सिंह ईमानदारी का सिर्फ मुखौटा है 03

दस सीटों पर उपचुनाव जो जीतेगा, वही सिकंदर 05

दिल्ली बन गई है राजनीति की पाठशाला 06

साई की महिमा 12

> प्रधानमंत्री की तरफ़ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखकर सफाई देने को कहा गया कि उन्होंने किस आधार पर दागी जज का नाम हटाया. अब यह समझने के लिए राकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि इस पत्र का मतलब क्या है. यह पत्र न्यायालय पर एक दबाव था. यह पत्र प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए एक भ्रष्ट जज की नियुक्ति की तरफ़दारी थी. सत्ता को ज़हर की संज्ञा देने वाली पार्टी का यह एक ऐसा जघन्य अपराध है, जो भले ही क़ानून की दृष्टि से ग़लत न हो, लेकिन राजनीतिक एवं प्रजातांत्रिक आदर्शों के नज़रिये से यह एक घिनौना कृत्य है, जिसने न्यायपालिका की आज़ादी और स्वायत्तता को तार-तार कर दिया.

मनमोहन सिंह ईमानदारी का सिर्फ़ मुखौटा हैं

यूपीए के दस सालों में देश ने इतिहास के सबसे बड़े घोटालों को देखा. अरबों-खरबों का घोटाला करने वाली सरकार ने अनैतिक काम भी किए. संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बनाया, साथ ही वह संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति को लेकर भी विवादों में रही. सारी अनैतिकता और घोटालों के बावजूद यह लगता था कि सिर्फ़ न्यायपालिका कांग्रेस के दानवी पंजे से बच गई. लेकिन, जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिससे भारतीय प्रजातंत्र शर्मसार हुआ और साथ ही कांग्रेस पार्टी के ईमानदारी के मुखौटे मनमोहन सिंह बेनकाब हो गए.

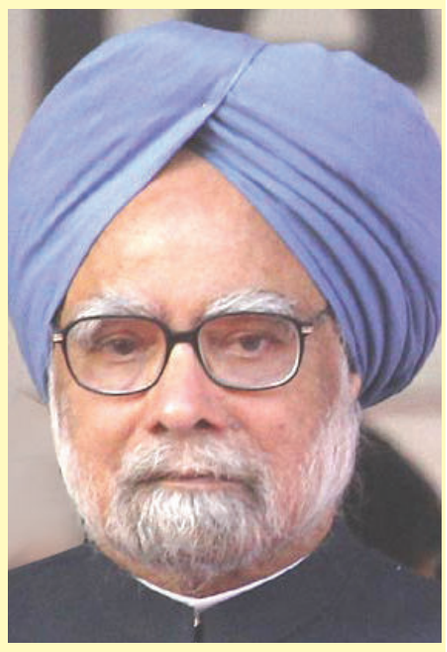

डॉ. मनीष कुमार

जिस तरह ख़तरनाक आंधी या भूकंप के बाद महामारी फैलती है, उसी तरह भारत की राजनीति में चुनाव के बाद महामारी का दौर है. ऐतिहासिक हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस पार्टी में विद्रोह का माहौल बन रहा है. कई लोग अपना हिसाब बराबर करने में लगे हैं. जिसे भी मौक़ा मिल रहा है, वह गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है. मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू और फिर कोयला सचिव के सी पारेख की कोयला घोटाले पर किताबें आईं, तो मनमोहन सिंह और उनकी सरकार की कलई खुल गई. भूतपूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की भी एक किताब बाज़ार में आने वाली है. यह ख़बर सुनते ही सोनिया गांधी एवं प्रियंका उनके घर पहुंचीं और उन्होंने नटवर सिंह को पुराने रिश्तों की दुहाई देकर किताब प्रकाशित न कराने की गुज़ारिश की. अब जब नटवर सिंह की किताब आएगी, तो कुछ और नए खुलासे होंगे. लेकिन फ़िलहाल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन एवं रिटायर्ड जज काटजू के खुलासे से कांग्रेस की किरकिरी हो गई.

यह बात 2005 की है. मद्रास हाईकोर्ट में एक जज की नियुक्ति का मामला उलझ गया. जज साहब पर भ्रष्टाचार के आरोप थे. काटजू हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे. उनसे कई लोगों ने शिकायत की. न्यायालय की गरिमा को ठेस न लगे, इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लाहौटी को फोन करके यह बताया कि जस्टिस अशोक कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसलिए बेहतर यह होगा कि आईबी से उनकी एक खुफिया जांच करा ली जाए. जस्टिस लाहौटी ने आईबी से जस्टिस अशोक कुमार की जांच कराई और आईबी की जांच रिपोर्ट जस्टिस अशोक कुमार के ख़िलाफ़ आई. जजों का चुनाव करने वाले कॉलेजियम में यह राय बनी कि वह (अशोक कुमार) अब हाईकोर्ट में जज नहीं बन सकते. कॉलेजियम ने अपनी यह राय केंद्र सरकार को भेज दी.

इसके बाद पता चला कि जस्टिस अशोक कुमार के लिए डीएमके ने मोर्चा खोल दिया और यह चेतावनी दी कि अगर उनकी नियुक्ति न हुई, तो डीएमके केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेगा. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह न्यूयॉर्क जा रहे थे और उन्हें डीएमके की इस धमकी का पता एयरपोर्ट पर चला. मनमोहन सिंह चिंतित हो उठे. उन्हें लगा कि अब क्या होगा. उनके साथ यूपीए के एक मंत्री भी थे. उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वह सब कुछ मैनेज कर देंगे. खुलासे के बाद पता चला कि वह मंत्री कोई और नहीं, बल्कि यूपीए-1 के विधि मंत्री हंसराज भारद्वाज थे. यह कांग्रेस की मुसीबतों का हल निकालने वाले मंत्रियों में से एक हैं. इन्हीं की योजना और आशीर्वाद से बोफोर्स घोटाले का आरोपी स्वर्गीय ओट्टाविया क्वात्रोची अर्जेंटीना में पकड़े जाने के बावजूद बच निकला और भारत ने उसके सारे बैंक खातों से पाबंदी भी हटा ली. कई सारे विवादों में घिरने के बाद भारद्वाज को गवर्नर बनाकर दिल्ली से दूर भेज दिया गया. जस्टिस अशोक कुमार की विवादास्पद नियुक्ति की ज़िम्मेदारी अब हंसराज भारद्वाज पर आ गई.

हंसराज भारद्वाज ने इस बात को माना कि कांग्रेस पार्टी पर डीएमके का दबाव था और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाक़ात भी की थी, लेकिन उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि जस्टिस अशोक कुमार की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं की गई. अगर गड़बड़ी नहीं हुई, तो यह कैसे हो गया कि आईबी की रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ करके एक दाग़ी जज की नियुक्ति हो गई. जिस जज की नियुक्ति को कॉलेजियम ने नकार दिया, तो फिर वह कुर्सी पर कैसे बैठ गया? यह मामला दिन के उजाले की तरह साफ़ है कि इस जज की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई. हंसराज भारद्वाज जब मीडिया और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगे थे, तभी प्रधानमंत्री कार्यालय की एक सीक्रेट रिपोर्ट सामने आ गई. प्रधानमंत्री की तरफ़ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखकर सफाई देने को कहा गया कि उन्होंने किस आधार पर दागी जज का नाम हटाया. अब यह समझने के लिए राकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि इस पत्र का मतलब क्या है. यह पत्र न्यायालय पर एक दबाव था. यह पत्र प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए एक भ्रष्ट जज की नियुक्ति की तरफ़दारी थी. सत्ता को ज़हर की संज्ञा देने वाली पार्टी का यह एक ऐसा जघन्य अपराध है, जो भले ही क़ानून की दृष्टि से ग़लत न हो, लेकिन राजनीतिक एवं प्रजातांत्रिक आदर्शों के नज़रिये से यह एक घिनौना कृत्य है, जिसने न्यायपालिका की आज़ादी और स्वायत्तता को तार-तार कर दिया.

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक बार फिर झांसा देने की कोशिश की. कांग्रेस की दलील है कि मनमोहन सरकार ने जो किया, वह क़ानून के मुताबिक़ ही किया. कांग्रेस ने यही दलील टूजी घोटाले और कोयला घोटाले में भी दी. हर घोटाले के पर्दाफ़ाश के बाद कांग्रेस यही कहती रही कि जो हुआ है, क़ानून के मुताबिक़ हुआ है. मनमोहन सिंह ने टूजी घोटाले के खुलासे के बाद तीन सालों तक यही कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है और जितने भी फ़ैसले हुए, वे सब क़ानून के मुताबिक़ लिए गए हैं. लेकिन आख़िर में हुआ क्या? इतिहास में पहली बार एक पदासीन केंद्रीय मंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी. यह और बात है कि हर बार कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह की ईमानदारी की दुहाई देकर लोगों को झांसा देने की कोशिश की. इसी तरह जब कोयला घोटाला सामने आया, तो ईमानदारी की मूर्ति बनकर मनमोहन सिंह ने यह ऐलान किया था कि अगर शक की सूई भी उन पर आई, तो वह राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे. शक की सूई तो क्या, नौबत यहां तक आ गई कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कोयला आवंटन की फाइलें ग़ायब होने लगीं. सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन मनमोहन सिंह पर उसका कोई असर नहीं हुआ. उन्होंने संन्यास नहीं लिया, तो जनता ने ही उन्हें और उनकी पार्टी को रिटायर कर दिया. लेकिन, इस बार मामला कुछ अलग है. यह अलग इसलिए है, क्योंकि जस्टिस काटजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो सवाल किए हैं, वे महज सवाल नहीं, बल्कि मनमोहन सिंह की कार्य पद्धति पर ज़ोरदार तमाचा है, मनमोहन सिंह की ईमानदार छवि पर आख़िरी कील है. पहले समझते हैं कि इन सवालों का मतलब क्या है?

जस्टिस काटजू ने पूछा है कि क्या यह सही नहीं है कि सबसे पहले मैंने उस भ्रष्ट जज की शिकायत जस्टिस लाहौटी को भेजी थी? मतलब यह कि जस्टिस अशोक कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप कोई मीडिया रिपोर्ट या सुनी-सुनाई बात नहीं है, बल्कि मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शिकायत की थी. जस्टिस काटजू के इस सवाल का खंडन नहीं किया गया, बल्कि तत्कालीन क़ानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने इसकी पुष्टि भी की. जस्टिस काटजू ने पूछा कि क्या यह सही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मामले की जांच आईबी से कराई? इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि कॉलेजियम के कहने पर जांच कराई गई. सबसे बड़ी बात यह कि जांच के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद फोन करके जस्टिस काटजू को बताया कि जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि अशोक कुमार पर लगाए गए आरोप सही हैं. अगला सवाल जस्टिस काटजू ने यह पूछा कि क्या यह सही नहीं कि कॉलेजियम ने उस जज का कार्यकाल बढ़ाने से इंकार किया था? कॉलेजियम में शामिल जजों ने इस बात की पुष्टि की है कि जस्टिस अशोक कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया गया था. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लाहौटी ने कॉलेजियम को बिना बताए ही जस्टिस अशोक कुमार का कार्यकाल बढ़ा दिया. अब सवाल यह है कि आईबी की प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद जस्टिस लाहौटी ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब जस्टिस लाहौटी के पास नहीं है. इन सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ़ इतना कहा कि हमने जो कुछ किया है, वह सब रिकॉर्ड है. वैसे भी जस्टिस लाहौटी से जवाब मांगने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यह पूरा खेल मनमोहन सिंह का है, कांग्रेस की सरकार का है.

कांग्रेस इन सवालों का जवाब देने की बजाय जस्टिस काटजू से ही सवाल पूछ रही है. कांग्रेस के ही सवालों को मीडिया के कुछ एडिटर और चैनल के एंकर पूछ रहे हैं. वे पूछ रहे हैं कि जस्टिस काटजू ने 2005 में क्यों नहीं कुछ बोला? उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था. वह अभी ही क्यों यह खुलासा कर रहे हैं? सवाल जस्टिस काटजू के टाइमिंग का नहीं है, बल्कि यह देश में प्रजातंत्र के भविष्य का सवाल है. क्या देश में भ्रष्ट लोगों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है और उसके लिए क्या सीधे प्रधानमंत्री की तरफ़ से दबाव डाला जा सकता है? क्या देश की जनता भ्रष्ट लोगों को जज बनाने के लिए सरकार चुनती है? सवाल केवल इतना है कि जो तथ्य जस्टिस काटजू ने दिए हैं, क्या वे सही हैं या गलत? अब तक इस मसले पर जितने भी तथ्य सामने आए हैं, उनसे यही लगता है कि जस्टिस काटजू की बातों में सच्चाई है. नई सरकार और मीडिया को अब पता करना चाहिए कि क्या यह अकेला मामला है या फिर कई और जजों तथा दूसरी संवैधानिक नियुक्तियों में भी धांधली हुई है? क्या मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुई नियुक्तियों में सरकार एवं नेताओं का हस्तक्षेप रहा?

जस्टिस काटजू का खुलासा मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर सबसे तीखा प्रहार है. कांग्रेस की वह दलील कि मनमोहन सिंह किसी भी शक से ऊपर हैं, भी ख़त्म हो गई. यह साबित हुआ कि कांग्रेस को सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को दांव लगाने में भी झिझक नहीं है. कांग्रेस ने पिछले दस सालों के दौरान कई सारी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा तहस-नहस की. ऐसा लगा था कि कांग्रेस की सत्तालोलुप राजनीति से न्यायपालिका बचने में कामयाब रही, लेकिन अब इस खुलासे के बाद कहना पड़ेगा कि पिछले दस सालों में यूपीए की मनमोहन सरकार भारत के प्रजातंत्र के लिए एक काला धब्बा साबित हुई. सरकार को इस मामले की छानबीन करानी चाहिए, दोषियों को दंड मिलना चाहिए और ऐसे प्रावधान बनाने की ज़रूरत है, जिससे भविष्य में ऐसी गलती होने की संभावना ख़त्म हो जाए. प्रजातंत्र को बचाने के लिए न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखना ज़रूरी है.■

manishbph244@gmail.com

किसने क्या कहा

> न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में आरोप लगते रहे हैं, लेकिन काटजू द्वारा लगाए गए ताज़ा आरोपों से एक बार फिर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की आवश्यकता दिखाई देती है. हमें इस बारे में जानकारी नहीं मिलती कि न्यायधीशों की नियुक्ति किस तरह होती है, किस तरह उनकी पदोन्नति होती है या किस तरह तबादला होता है, जबकि हमारे पास कॉलेजियम प्रणाली है. इसीलिए लोग इन चीजों पर सवाल उठा रहे हैं. मनमोहन सिंह और कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये आरोप सही हैं या नहीं.

डी राजा
भाकपा

> उस जज की नियुक्ति को लेकर एक प्रमुख राजनीतिक दल का दबाव था. इसके बावजूद मैंने दबाव में कोई फ़ैसला नहीं लिया. न्यायधीश को कोई अनुचित मदद नहीं दी गई, क्योंकि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था. जहां तक गठबंधन सरकार पर राजनीतिक दबाव की बात है, तो जजों की नियुक्तियों पर (घटक दलों की ओर से) हमेशा दबाव रहा, जिसके सामने मैं कभी नहीं झुका.

हंसराज भारद्वाज
पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री

रवि शंकर प्रसाद
केंद्रीय विधि मंत्री

> जजों की नियुक्ति की व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है. सरकार ऐसी नियुक्तियां करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करना चाहती है.

एम वीरप्पा मोइली
वरिष्ठ कांग्रेस नेता

> सभी मामलों में कॉलेजियम ही फ़ैसला ले रहा था. दस साल बाद इस मुद्दे को उठाने के पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा.

> यह मामला गंभीर है. अगर न्यायपालिका पर सवाल उठेंगे, तो किस पर भरोसा किया जाएगा.

नरेश अग्रवाल
समाजवादी पार्टी

कांग्रेस इन सवालों का जवाब देने की बजाय जस्टिस काटजू से ही सवाल पूछ रही है. कांग्रेस के ही सवालों को मीडिया के कुछ एडिटर और चैनल के एंकर पूछ रहे हैं. वे पूछ रहे हैं कि जस्टिस काटजू ने 2005 में क्यों नहीं कुछ बोला? उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था. वह अभी ही क्यों यह खुलासा कर रहे हैं? सवाल जस्टिस काटजू के टाइमिंग का नहीं है, बल्कि यह देश में प्रजातंत्र के भविष्य का सवाल है. क्या देश में भ्रष्ट लोगों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है और उसके लिए क्या सीधे प्रधानमंत्री की तरफ़ से दबाव डाला जा सकता है? क्या देश की जनता भ्रष्ट लोगों को जज बनाने के लिए सरकार चुनती है?

> मुलायम सिंह को ऐसे सारथी की आवश्यकता महसूस हो रही है. भले ही वह अपना दुखड़ा पार्टी के लोगों से सुनाने में हिचक रहे हों, लेकिन राजनीति के जानकार समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं मुलायम सिंह को अब एक लड़ाके की ज़रूरत है, जो उनके जज्बात समझे और साथ ही पार्टी का शुभचिंतक, चाणक्य बुद्धि वाला एवं दूरदर्शी भी हो. तब कहीं जाकर वह भाजपा जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं.

मुलायम को सारथी की तलाश

> लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह को अमर सिंह की याद भी आई थी, क्योंकि उनके साथ इस बार आजम खां एवं रेवती रमण सिंह के अलावा कोई अनुभवी नेता नहीं रह गया था. अमर सिंह मुलायम के दाहिने हाथ थे, ठीक उसी तरह, जैसे एक समय बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह के दाहिने हाथ समझे जाते थे. बेनी वर्मा, आजम खां एवं अमर सिंह की तिकड़ी मुलायम सिंह के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिससे हमेशा मुलायम सिंह को बल मिलता रहा.

दर्शन शर्मा

लोकसभा चुनाव में मात खाए सपा प्रमुख इन दिनों पसोपेश में हैं कि वह अब अकेले हैं. पिछली लोकसभा में उनके साथ मोहन सिंह जैसे प्रखर नेता मौजूद थे, जो कहीं न कहीं पार्टी में जामवंत की भूमिका निभाते थे और गाहे-बगाहे सामने आने वाली विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देते थे. पहली और दूसरी संप्रग सरकार में मुलायम सिंह के पास सदन में सांसदों की संख्या मतलब भर थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें बहू-भतीजों सहित चार सीटें मिलीं. दो सीटों पर जीते मुलायम सिंह ने अपनी आजमगढ़ सीट बरकरार रखते हुए मैनपुरी सीट इसलिए छोड़ रखी है कि इस सीट पर वह कोई ऐसा योद्धा लड़ाएंगे, जो सदन के अंदर मुकाबला करने के दौरान उनकी मदद करे. मुलायम सिंह को ऐसे सारथी की आवश्यकता महसूस हो रही है. भले ही वह अपना दुखड़ा पार्टी के लोगों से सुनाने में हिचक रहे हों, लेकिन राजनीति के जानकार समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं मुलायम सिंह को अब एक लड़ाके की ज़रूरत है, जो उनके जज्बात समझे और साथ ही पार्टी का शुभचिंतक, चाणक्य बुद्धि वाला एवं दूरदर्शी भी हो. तब कहीं जाकर वह भाजपा जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ऐसे ही प्रखर विद्वान सांसद प्रत्याशी की खोज पार्टी के दिग्गज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से ऐसी कोई ख़बर नहीं आ रही है कि आख़िर मैनपुरी सीट से उम्मीदवार के रूप में कौन-सा शख्स सामने आएगा, जो जिताऊ हो, साथ ही हीरे की परख रखने वाला जौहरी भी. दरअसल यह काम थोड़ा दुरुह है, क्योंकि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सपा के महाभटों को अपने जादुई बाण से एक ही बार में किनारे लगा दिया है.

यह तो गनीमत रही कि मुलायम सिंह के बहू-भतीजे किसी तरह बच गए, जिसके लिए सपा ईश्वर का लाख-लाख शुक्रिया अदा कर रही है. मुलायम सिंह तो यहां तक सोच चुके हैं कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए. एक समय मुलायम सिंह के साथ मोहन सिंह एवं जनेश्वर मिश्र जैसे प्रखर नेता मौजूद थे, जो पार्टी की विभिन्न समस्याओं का समाधान समाजवादी विचारधारा के माध्यम से कर दिया करते थे. वे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं विदेश नीति सहित सभी मामलों में अपनी राय बड़े तार्किक ढंग से बेबाकी और निडरता के साथ रखते थे. अपने व्यक्तित्व, विचार शक्ति एवं संघर्ष क्षमता के बल पर वे मुलायम सिंह के बेड़े के कामयाब संचालक रहे. समाजवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण की भावना उनके रोम-रोम में थी, जिसे मुलायम सिंह आज भी याद करते हैं. यही कारण है सपा सरकार ने इन बड़े नेताओं की याद में लोहिया पार्क एवं जनेश्वर मिश्र पार्क जैसे स्मारक बनवाए हैं. सपा प्रमुख को अपने जीवनकाल में ऐसा पहली बार देखने को मिला, जबकि उनके मंसूबों के अनुसार सफलता नहीं मिल पाई. ऐसा तब हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में सपा की प्रचंड बहुमत की सरकार थी. खैर, मुलायम सिंह दो जगहों यानी आजमगढ़ और मैनपुरी से जीते. फिरोजाबाद, कन्नौज एवं बदायूं संसदीय सीटें भी सपा के खाते में दर्ज हुईं.

लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह को अमर सिंह की याद भी आई थी, क्योंकि उनके साथ इस बार आजम खां एवं रेवती रमण सिंह के अलावा कोई अनुभवी नेता नहीं रह गया था. अमर सिंह मुलायम के दाहिने हाथ थे, ठीक उसी तरह, जैसे एक समय बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह के दाहिने हाथ समझे जाते थे. बेनी वर्मा, आजम खां एवं अमर सिंह की तिकड़ी मुलायम सिंह के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिससे हमेशा मुलायम सिंह को बल मिलता रहा. उन्हें कभी भी परवाह नहीं रहती थी. सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुलायम सिंह को अमर सिंह से मिला, जिनकी वजह से मुलायम सिंह फिल्मी हस्तियों के साथ-साथ उद्योगपतियों का भी समर्थन पाते रहे. यह वही अमर सिंह थे, जिन्होंने 2008 में यूपीए सरकार को विश्वास मत दिलाने के अभियान में केंद्रीय भूमिका निभाई थी. ग़ौरतलब है कि 9 जुलाई, 2008 को वामपंथी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और उसी समय यूपीए सरकार को परमाणु करार के लिए संसद का समर्थन हासिल करना था. अमर सिंह की इस मेहरबानी के पीछे एक अहम कारण यह भी बताया जाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हुए अरबों रुपये के खाद्यान्न घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जिसमें सपा प्रमुख की गर्दन फंसती नज़र आ रही थी.

ऐसे में, अमर सिंह ने मुलायम को बचाने के लिए सांसदों के खरीद-फरोख्त में प्रमुख भूमिका निभाई. यूपीए को मुलायम के 39 सांसदों की ज़रूरत थी, जो अमर सिंह ने पूरी कर दी. जिन अमर सिंह ने आय से अधिक संपत्ति और खाद्यान्न घोटाले के लिए सरकार से सौदा करके मुलायम सिंह को बचाया था, उन्हें ही मुलायम ने पार्टी से निकाल दिया. अमर सिंह इन दिनों राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजित सिंह के साथ हैं, जो मुलायम सिंह के प्रबल विरोधी हैं. बहरहाल, मुलायम सिंह अपना इकबाल बरकरार रखने के लिए आज भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. उन्होंने वोट हासिल करने के लिए जहां दस्यु सरगनाओं एवं दस्यु सुंदरियों को सांसद-विधायक बनाया, वहीं बड़े-बड़े धन्ना सेठों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक धरती भी खूब सींची. भले ही समय-समय पर कई लोग उनसे अलग हो गए. कई ऐसे नेता भी रहे, जिनके बल पर मुलायम सिंह की साख सधी रही, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. आज लोकसभा में अलग-थलग पड़े मुलायम सिंह को उन सभी की बहुत याद आ रही है. इसलिए वह मैनपुरी से चुनाव लड़ाने के लिए किसी ऐसे योद्धा की तलाश कर रहे हैं, जो इस मौक़े पर उनका सहारा बनकर सामने आए. ऐसी किसी बैसाखी की उन्हें सख्त ज़रूरत है. मुलायम को लोकसभा में अपने लिए एक सारथी चाहिए, जिसकी खोज लगातार जारी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विवादित बयानों पर बवाल

संजय सक्सेना

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के विवादित बयानों ने उत्तर प्रदेश सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया है. यह बात भले ही सपा नेता सार्वजनिक मंच पर स्वीकार नहीं करते, लेकिन इसकी सुगबुगाहट पार्टी के भीतर सुनाई और दिखाई पड़ने लगी है. हालांकि इसका मुखर विरोध नहीं हो रहा है. खासकर, महिलाओं को लेकर मुलायम सिं का तंग नज़रिया नई सोच के समाजवादियों को रास नहीं आता है. अनजाने में ही सही, नेता जी अपने विवादित बयानों से विरोधी दलों को सपा के ख़िलाफ़ जहर उगलने का मौक़ा दे देते हैं. सपा के कुछ नेताओं ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि मुलायम सिंह के बयानों के कारण ही लोकसभा चुनाव में पार्टी को महिला वोटरों से हाथ धोना पड़ा. महिला वोटरों की बेरुखी की वजह मुलायम सिंह का मुजफ्फनगर में दिया गया वह बयान था, जिसमें उन्होंने मुंबई गैंगरेप के आरोपियों के प्रति नरम रुख अपनाते हुए कहा था, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इसका मतलब यह थोड़ी है कि उन्हें (गैंगरेप के आरोपियों) फांसी पर लटका दिया जाए.

उम्मीद थी कि इस विवादित बयान के बाद नेता जी को सबक मिल गया होगा, लेकिन लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में कथित गैंगरेप और हत्या की घटना के बाद मुलायम सिंह का एक और विवादित बयान सामने आया, जिसमें वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कहते दिखाई पड़े कि उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से दुराचार की वारदातें कम होती हैं. मुलायम सिंह के इस बयान ने विस्फोटक का काम किया. महिला संगठन आग बबूला हो गए. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डैमेज कंट्रोल के तहत महिला के दोनों बच्चों के नाम पर दस-दस लाख रुपये की एफडी और उनकी इंटर तक की मुफ्त पढ़ाई की घोषणा तो कर दी, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा. जानकार कहते हैं कि महिलाएं ही नहीं, चुनाव के दौरान अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने के चक्कर में दिए गए नेता जी के कुछ विवादित बयानों के चलते हिंदू वोटर, जिनमें बड़ी संख्या यादवों की थी और जो हमेशा मुलायम का आंख मूंद कर समर्थन करते थे, उनसे दूर चले गए. मुलायम के स्वभाव में आए बदलाव से उन्हें क़रीब से जानने वाले भी हैरान हैं. अब वह (मुलायम) चुनावी समर में रणवीर की तरह खड़े नहीं दिखते, बल्कि याचक (अखिलेश को सीएम बना दिया, मुझे भी पीएम बना दो) की भूमिका में नज़र आते हैं. मुलायम की गंभीरता कहीं खो गई है.

एक समय था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव कभी अपने विरोधियों के बारे में या फिर जनता के बीच बोलते समय असंसदीय नहीं हुआ करते थे, वह काफी सोच-समझ कर भाषा का चयन करते थे और राजनीतिक मतभेदों को उन्होंने कभी व्यक्तिगत जीवन पर हावी नहीं होने दिया. शायद इसी वजह से सभी दलों में उनके शुभचिंतक मिल जाते हैं. यहां तक कि अपनी धुर विरोधी बसपा प्रमुख मायावती की मुंहफट बयानबाजी को भी नेता जी सहज पचा जाते थे, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने सभी मर्यादाएं भुलाते हुए मायावती पर विवादित टिप्पणी यह कहकर कर दी, हम मायावती को क्या कहें, श्रीमती या कुंवारी बेटी या बहन. मुलायम के इस बयान के बाद बसपा ने खूब खरी-खोटी सुनाई थी. उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि नेता जी ने कुछ गलत कहा था. उल्टे वह आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार और जनता के विरुद्ध इन दिनों सुनियोजित ढंग से दुष्प्रचार हो रहा है. प्रदेश में क़ानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर तमाम तरह की भ्रामक बातें प्रचारित की जा रही हैं. बसपा तो खैर सत्ता खोने के दिन से ही बौखलाई हुई है और उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम समाजवादी सरकार को बदनाम करना और उसे बर्खास्त कराना रह गया है. वह कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से भाजपा अपने होश खो बैठी है और जल्द से जल्द सत्ता हथिया लेने का स्वप्न देखने लगी है. कांग्रेस सब कुछ गंवाने के बाद और कोई रास्ता न सूझने के कारण भाजपा-बसपा के साथ सुर-ताल मिला रही है.

> सपा नेता चौधरी कहते हैं कि समाजवादी सरकार द्वारा क़ानून व्यवस्था के प्रति पूर्ण सतर्कता बरती जाती है. इस पर भी झूठे आंकड़ों के सहारे अनर्गल बयानबाजी करके जनता को बरगलाने की साजिशें चल रही हैं. सपा नेताओं के बयानों को तोड़-मरोड़ कर और संदर्भ से अलग पेश करके माहौल खराब किया जाता है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बयानों को इधर कुछ ज़्यादा ही गलत ढंग से प्रचारित किया गया.

सपा नेता चौधरी कहते हैं कि समाजवादी सरकार द्वारा क़ानून व्यवस्था के प्रति पूर्ण सतर्कता बरती जाती है. इस पर भी झूठे आंकड़ों के सहारे अनर्गल बयानबाजी करके जनता को बरगलाने की साजिशें चल रही हैं. सपा नेताओं के बयानों को तोड़-मरोड़ कर और संदर्भ से अलग पेश करके माहौल खराब किया जाता है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बयानों को इधर कुछ ज़्यादा ही गलत ढंग से प्रचारित किया गया. मुलायम सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर, विवेकशील एवं संतुलित विचारधारा वाले जननेता के रूप में शुमार किया जाता है. महिलाओं को वह अत्यधिक सम्मान देते हैं. दुष्कर्म की शिकार महिलाओं को त्वरित न्याय मिले, इसके वह पक्षधर हैं. उनके किसी बयान का आशय न तो किसी अपराध को कमतर बताना है और न नारी जगत के प्रति अवमानना दिखाना है. भाजपा के कई नेता बसपा नेताओं की तरह क़ानून व्यवस्था के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं और उनके बयानों में धमकी का पुट रहता है.

दरअसल, सच तो यह है कि नेता जी यानी मुलायम सिंह की वाणी पर कोई लगाम नहीं लगा सकता. वजह साफ़ है कि आज भी सपा का मतलब मुलायम सिंह और मुलायम सिंह का मतलब समाजवादी पार्टी है. फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नेता जी के बयानों के प्रति असहमति जताना इसलिए भी मुश्किल है, क्योंकि दोनों के बीच सिर्फ़ राजनीतिक नहीं, पारिवारिक संबंध भी है. वर्ना कोई मुख्यमंत्री यह थोड़े सुन सकता है कि वह चाटुकारों से घिरा हुआ है. अखिलेश के पास नेता जी के बयानों को मुस्कुरा कर टाल देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. वह (अखिलेश) ऐसा कई बार कर भी चुके हैं. वैसे, समाजवादी पार्टी में नेता जी अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं, जो विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं. राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, आजम खां एवं राजेंद्र चौधरी जैसे नेता भी अपने विवादित बयानों के कारण समय-समय पर सुर्खियां बटोरते रहते हैं. आजम खां का भारत माता को डायन कहने वाला बयान हो या फिर नरेश अग्रवाल का मोदी को लेकर दिया गया बयान कि एक चाय वाला पीएम नहीं बन सकता, ने सपा को लोकसभा चुनाव में काफी नुक़सान पहुंचाया. सपा के एक अन्य नेता राम गोपाल यादव बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि के लिए टीवी में दिखाई जाने वाली अश्लीलता और हिंसा को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. सपा नेता एवं अखिलेश कैबिनेट के मंत्री शिवपाल पाल यादव को लगता है कि इसके लिए मीडिया ज़िम्मेदार है. महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी इस्लाम का हवाला देते हुए बलात्कारी को फांसी की सजा दिए जाने की बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की शिकायत रहती है कि सिर्फ़ पुरुषों को सजा क्यों दी जाती है, महिलाओं का कुछ नहीं होता है.

कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरना नेताओं का हथकंडा बन गया है. अगर ऐसा न होता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बलात्कार की घटनाओं के संदर्भ में अपने नेताओं को यह नसीहत न देनी पड़ती कि वे ऐसी घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की बजाय अपना मुंह बंद रखें. मोदी ने यह बात संसद में कही. उनका संदेश सिर्फ़ भाजपा नहीं, बल्कि सभी दलों के नेताओं के लिए था. इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि एक तरफ़ तो संसद एवं विधानसभाएं महिलाओं की बेहतरी और सुरक्षा के लिए नित नए-नए क़ानून बना रही हैं, वहीं उसके नुमाइंदे महिलाओं को लेकर उल्टे-सीधे बयान देते हैं. कभी उनके पहनावे पर उंगली उठाई जाती है, तो कभी उनकी आज़ादी पर सवाल खड़े किए जाते हैं. अफ़सोस की बात यह है कि कई मौक़ों पर महिलाओं के बारे में अदालतों का नज़रिया भी काफी संकुचित दिखता है. मुंबई हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कुछ समय पूर्व तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान यहां तक कह दिया कि महिलाओं को सीता की तरह हर हाल में पति का साथ देना चाहिए. वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट की एक जज ने पारिवारिक झगड़े के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पुरुष अपनी स्त्री को मारता है, तो उसकी शिकायत महिला को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आख़िर वह (पुरुष) उसकी सभी ज़रूरतें भी तो पूरी करता है.

महिलाओं के प्रति नेताओं एवं अदालतों की ऐसी विवादित टिप्पणियों से ही खाकी वर्दी वालों के हौसले बुलंद रहते हैं. महिलाएं अपने उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए पुलिस के पास जाने में कतराती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि पुलिस बलात्कार जैसी घटनाओं, जिनमें पीड़ित का सब कुछ तबाह हो जाता है, को लेकर इसलिए गंभीर नहीं हो सकती, क्योंकि वह बलात्कार को रूटीन की घटना मानती है. ऐसी सोच रखने वाला अगर पुलिस का हाकिम हो, तो उसका असर पूरी खाकी कौम पर पड़ता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

इस बेमौसम यात्रा को लेकर मीडिया में भी रामदेव की खूब किरकिरी हुई. मीडिया ने इस यात्रा पर जितने भी सवाल उठाए, सब पर बाबा बगलें झांकते दिखे. उत्तरकाशी में पत्रकार वार्ता के दौरान बाबा रामदेव ने सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया और कहा कि हम हिमालय यात्रा के प्रति लोगों में बैठे डर को निकालने के लिए निकले हैं और मीडिया हमें बेवजह विवादों में घसीट रही है. जिस समय रामदेव उत्तरकाशी के कैलाश आश्रम में मीडिया से मिल रहे थे, उसी समय हरिद्वार में बालकृष्ण बाबा रामदेव की गंगा सेवा यात्रा की सफलता पर संतोष जता रहे थे.

दस सीटों पर उपचुनाव

जो जीतेगा, वही सिकंदर

सरोज सिंह

ऐलान-ए-जंग हो चुका है, अपनी-अपनी सेनाओं को सजाने और मैदान में उतारने से पहले कील-कांटे दुरुस्त करने की कवायद हर खेमे में जारी है. भ्रम की स्थिति साफ़ करते हुए नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया है कि वह राजद के साथ ही चुनावी अखाड़े में उतरेंगे और भाजपा को चारों खाने चित्त कर देंगे. भाजपा ने भी देर नहीं की और सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जंगलराज पार्ट-2 का आगाज करने वाले हैं, लेकिन बिहार की जनता जंगलराज दोबारा पनपने नहीं देगी, क्योंकि यहां तो सिर्फ़ सुशासन ही विकल्प है. लोजपा एवं रालोसपा ने भी साफ़ कर दिया है कि वे उपचुनाव में राजद-जदयू गठबंधन को सभी दस सीटों पर धूल चटा देंगी. कांग्रेस भी अपना अलग रास्ता अख्तियार कर सकती है.

ग़ौरतलब है कि नरकटियागंज, राजनगर, जाले, छपरा, हाजीपुर, मोहिउद्दीनगर, परवत्ता, भागलपुर, बांका एवं मोहनिया में आगामी 21 अगस्त को मतदान होगा. बिहार यूं भी राजनीतिक प्रयोग की धरती रहा है. इस उपचुनाव के बहाने यहां एक बार फिर प्रयोग किया जा रहा है. लगभग डेढ़ दशकों से लालू प्रसाद का हर स्तर पर विरोध करने वाले नीतीश कुमार इस उपचुनाव में उनके साथ एक बार फिर गलबहियां कर रहे हैं. ऐसा इसलिए हो रहा कि सूबे के दोनों बड़े नेता यह मानकर चल रहे हैं कि अकेले लड़ने से भाजपा का मुकाबला करना असंभव है. दोनों को यह गणित भा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पड़े वोट मिला दिए जाएं, तो वह कुल वोटों का 45 फ़ीसद हो जाता है. यानी साथ लड़ा जाए, तो विधानसभा चुनाव में जीत तय.

उधर सुशील मोदी कहते हैं कि राजनीति का अंकगणित इतना भी आसान नहीं है, इसमें दो और दो का जोड़ हमेशा चार नहीं होता, बल्कि कभी शून्य भी हो जाता है, तो कभी 22 भी. लेकिन, नीतीश कुमार ने अपनी लाइन साफ़ कर दी है. वह चाहते हैं कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में मुसलमान, अति पिछड़े एवं पिछड़े वोटों का बंटवारा न हो, इसलिए इस गठबंधन में कांग्रेस को भी समेटने का प्रयास चल रहा है. अगर उपचुनाव में बात न भी बने, तो भविष्य के चुनाव में विकल्प खुला रखा जाएगा. नीतीश कुमार कहते हैं कि जो भी भाजपा के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनका गठबंधन में स्वागत है. लालू प्रसाद ने भी इस गठबंधन को विजयी गठबंधन करार देना शुरू कर दिया है. वह कहते हैं कि पूरा बिहार हमारे साथ है, भाजपा का कोई नामलेवा नहीं मिलेगा और उपचुनाव की सभी दस सीटों पर उनकी जीत तय है.

आख़िर ऐसी क्या बात है कि हर कोई इस उपचुनाव को इतनी तवज्जो दे रहा है. देखा जाए, तो यह बिहार विधानसभा चुनाव के पहले का सबसे बड़ा उपचुनाव है. बिहार के ज़्यादातर इलाकों में उपचुनाव की इन दस सीटों का फैलाव है. कहने का अर्थ यह है कि इस उपचुनाव के नतीजों से लगभग पूरे बिहार की जनता का मिजाज समझने में सहूलियत होगी. किस दल की ताकत और तैयारी कैसी थी, इसका भी अनुमान लग जाएगा. सबसे बड़ी बात यह होगी कि सभी दलों को आगे की रणनीति तैयार करने का एक रोडमैप मिल जाएगा. अगर इस उपचुनाव में जदयू एवं राजद की दोस्ती को जनता ने नकार दिया, तो फिर विधानसभा चुनाव की लड़ाई की तस्वीर ही बिल्कुल अलग हो जाएगी.

अगर भाजपा गठबंधन को जनता ने तवज्जो नहीं दी, तो फिर भाजपा के अंदर ही विरोध का नया खेल खुलकर शुरू हो जाएगा. लोकसभा चुनाव तो भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर निकाल लिया, लेकिन उपचुनाव में उसे अपने भरोसे ही ज़्यादातर रास्ते तय करने हैं. अब प्रदेश भाजपा कौन सा रास्ता बनाती है और उसे कैसे तय करती है, यह देखना दिलचस्प साबित होने वाला है. अगर सब कुछ सही रहा, तो फिर सुशील मोदी भाजपा में सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरेंगे और उन्हें चुनौती देने की हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक इसी तरह अगर राजद एवं जदयू गठबंधन नाकाम हो गया, तो दोनों ही दलों में आंतरिक कलह बहुत बढ़ सकती है. संभव है, कलह इतनी बढ़ जाए कि उसे रोकने में दोनों दलों के वरिष्ठ नेता कामयाब न हो पाएं. यह उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए बेहद अहम हैं, इसलिए दोनों तरफ़ से हर क़दम फूंक-फूंक कर रखा जा रहा है. ज़मीनी स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है और गठबंधन के लिए दिल बड़ा किया जा रहा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि सारा फोकस सीट निकालने पर है, ताकि आगे का रास्ता तय किया जा सके. अगर उपचुनाव गड़बड़ा गया, तो फिर आगे की राह बेहद कठिन हो जाएगी और यदि उपचुनाव सही रहा, तो फिर बिहार का अगला सिकंदर बनने का रास्ता खुद-ब-खुद बन जाएगा. ■

चुनाव कार्यक्रम

अधिसूचना	: 26 जुलाई
नामांकन की अंतिम तिथि	: 02 अगस्त
नामांकन पत्रों की जांच	: 04 अगस्त
नाम वापसी की अंतिम तिथि	: 06 अगस्त
मतदान	: 21 अगस्त
मतगणना	: 25 अगस्त

वोटों का ट्रेंड

लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक, बांका, मोहिउद्दीनगर, मोहनियां एवं नरकटियागंज में जदयू और राजद के सम्मिलित वोट भाजपा को मिले वोटों से अधिक हैं. वहीं भागलपुर, छपरा, हाजीपुर, जाले, राजनगर एवं परवत्ता में भाजपा को राजद और जदयू के सम्मिलित वोटों से अधिक वोट प्राप्त हुए.

लोकसभा चुनाव-2014 में किसे कितने वोट

दल	फ़ीसद
जदयू	15.8
राजद	20.1
भाजपा	29.4
भाकपा	01.2
लोजपा	06.4
रालोसपा	03.0

विधानसभा क्षेत्र /राजद /जदयू /राजद-जदयू के कुल वोट /भाजपा

नरकटियागंज	50,970	7,732	58,702	38,753
मोहनियां	56,995	8,653	65,648	54,376
भागलपुर	46,926	17,101	64,027	79,301
छपरा	43,035	16,034	59,069	81,291
हाजीपुर	39,932	12,499	52,431	96,736
जाले	55,757	5,926	61,683	63,380
मोहिउद्दीनगर	43,689	14,085	57,774	52,291
राजनगर	40,579	15,828	56,407	65,528
परवत्ता	47,674	21,453	69,127	73,983
बांका	42,614	29,804	72,418	47,498

गत चुनाव में छह सीटों पर जीती थी भाजपा

क्षेत्र	विजयी	पराजित
नरकटियागंज	सतीश चंद्र दुबे (भाजपा)	अशोक कुमार वर्मा (कांग्रेस)
राजनगर	राम लखन राम रमण (राजद)	रामपृत पासवान (भाजपा)
जाले	विजय कुमार मिश्र (भाजपा)	राम निवास प्रसाद (राजद)
छपरा	जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (भाजपा)	प्रेमेंद्र रंजन सिंह (राजद)
हाजीपुर	नित्यानंद राय (भाजपा)	राजेंद्र राय (लोजपा)
मोहिउद्दीनगर	राणा गंगेश्वर सिंह (भाजपा)	अजय कु. बुलगानीन (राजद)
परवत्ता	सम्राट चौधरी (राजद)	रामानंद प्रसाद सिंह (जदयू)
भागलपुर	अश्विनी कुमार चौबे (भाजपा)	अजीत शर्मा (कांग्रेस)
बांका	जावेद इकबाल अंसारी (राजद)	राम नारायण मंडल (भाजपा)
मेहनियां	छेदी पासवान (जदयू)	निरंजन राम (राजद)

रामदेव की गंगा सेवा यात्रा

कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना

राजकुमार शर्मा

योग गुरु बाबा रामदेव ने गंगा के नाम पर राजनीति करने का मन बना लिया है. उनकी हरिद्वार से लेकर गंगोत्री (गोमुख) तक की गंगा यात्रा पूरी तरह विवादों में घिर गई. बाबा रामदेव ने अपने 400 स्वयंसेवकों, जिनमें क़रीब चार दर्जन महिलाएं-युवतियां भी शामिल थीं, के साथ 15 वर्ष बाद गंगोत्री की यात्रा शुरू की. रामदेव ने जिस तरह देशकाल-परिस्थितियों का आकलन किए बगैर अपनी हिमालय-गंगा यात्रा शुरू की, वह पूरी तरह उनके हठयोग से प्रेरित रही. उनके अहं के चलते राज्य सरकार के माथे पर पसीना छलछला गया. जिस समय यात्रा शुरू हुई, उस समय उत्तरकाशी से लेकर गोमुख तक घनघोर बारिश के साथ-साथ भूस्खलन भी हो रहा था. उत्तरकाशी में रेड अलर्ट घोषित करने के साथ ही यात्रियों से कहा गया था कि वे गंगोत्री सहित चार धाम की यात्रा पर न जाएं. रामदेव इन सब बातों की परवाह किए बगैर गंगा यात्रा के लिए दर्जन भर लक्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ निकले, लेकिन गंगोत्री में उनका काफिला संकट में फंस गया. जिस ज़िला प्रशासन को आपदा में फंसी जनता की मदद करनी थी, उसने अपनी पूरी ताकत बाबा के काफिले को सुरक्षित बचाने और निकालने में झोंक दी. चार दिनों तक पूरा प्रशासन जनहित भूलकर बाबा बचाओ-हरिद्वार पहुंचाओ अभियान में जुटा रहा. वहीं काफिले में शामिल लोग गोमुख से उत्तरकाशी तक सारे नियम-क़ानून नजरअंदाज कर सावनी बहार का मजा लूटते रहे.

योग गुरु रामदेव ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय हर्षिल एवं गंगोत्री में व्यतीत करके योग ज्ञान हासिल किया. इसीलिए वह गंगोत्री को अपनी आध्यात्मिक जन्मस्थली बताते हैं. रामदेव इन दिनों स्वयं की राजनीतिक साधना के लिए पूरे मनोयोग से जुट गए हैं. अपनी महत्वाकांक्षा को आकार देने के लिए उन्होंने गंगा यात्रा को भावी राजनीतिक यात्रा का आगाज माना है. बाबा रामदेव सनातन धर्म में संतों की चतुर्मास में यात्रा निषेध परंपरा को नकार कर अपनी राजनीतिक गंगा यात्रा पर निकले, जो उनके अविवेक के चलते विवादों में घिर गई. 400 लोगों को साथ लेकर बाबा का गंगोत्री पहुंचना प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया. काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने उपचुनाव का तनाव था ही, उस पर बाबा रामदेव की नासमझी ने उन्हें और भी परेशानी में डाल दिया. रामदेव एवं उनके काफिले को गंगोत्री से निकालने की मुहिम की ज़िम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री ने संभाली. जब प्रशासन ने रामदेव एवं उनके काफिले को सुरक्षित हरिद्वार पहुंचा दिया, तब जाकर राज्य सरकार ने चैन की सांस ली.

इस बेमौसम यात्रा को लेकर मीडिया में भी रामदेव की खूब किरकिरी हुई. मीडिया ने इस यात्रा पर जितने भी सवाल उठाए, सब पर बाबा बगलें झांकते दिखे. उत्तरकाशी में पत्रकार वार्ता के दौरान बाबा रामदेव ने सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया और कहा कि हम हिमालय यात्रा के प्रति लोगों में बैठे डर को निकालने के लिए निकले हैं और मीडिया हमें बेवजह विवादों में घसीट रही है. जिस समय रामदेव उत्तरकाशी के कैलाश आश्रम में मीडिया से मिल रहे थे, उसी समय हरिद्वार में बालकृष्ण बाबा रामदेव की गंगा सेवा यात्रा की सफलता पर संतोष जता रहे थे. उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव गंगा के किनारे आपदा का दंश झेल रहे लोगों का दर्द हरने गए हैं. इसके ठीक उलट रामदेव ने अपनी यात्रा के दौरान पायलट बाबा के उत्तरकाशी (भटवाड़ी) आश्रम में ठहर कर रात बिताई. ग़ौरतलब है कि पायलट बाबा को स्थानीय लोग जरा भी पसंद नहीं करते. पायलट बाबा अपने आश्रम में विदेशी लड़कियों को अवैध रूप से ठहराने, बेरोज़गारों का शोषण करने और वन भूमि पर अवैध निर्माण के चलते खंडूड़ी सरकार के निशाने पर रहे हैं. रामदेव का पायलट बाबा से दोस्ती गांठना लोगों को रास नहीं आया.

गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक दैवीय आपदा से तबाह हुई जनता की खोज ख़बर न लेना भी रामदेव के लिए नुक़सानदायक साबित हुआ. वैसे, रामदेव का मानना है कि जब काशी बुलाकर गंगा नरेंद्र मोदी का बेड़ा पार कर सकती हैं, तो उनका क्यों नहीं? वह कहते हैं कि गंगोत्री तो उनकी आध्यात्मिक कर्मस्थली रही है, तो फिर गंगा की कृपा उन पर क्यों नहीं होगी? रामदेव की गंगा यात्रा भविष्य में क्या गुल खिलाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल उनके मंसूबे साफ़ नज़र आ रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली बन गई है राजनीति की पाठशाला

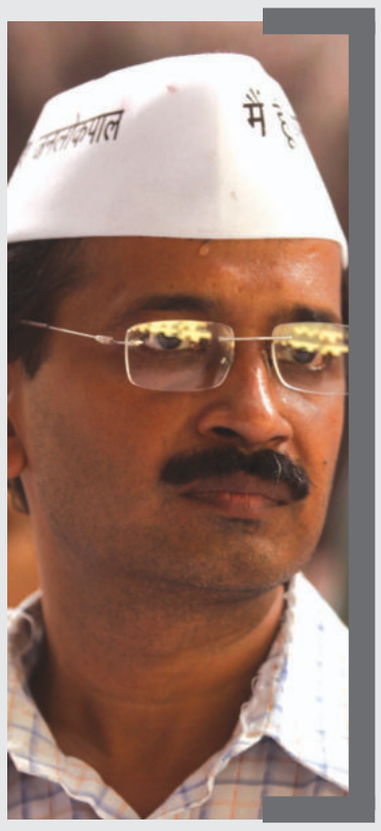

सभी फोटो–**प्रभात पाण्डेय**

अभी दिल्ली में निश्चित तौर पर भाजपा बनाम आप के बीच फिफ्टी-फिफ्टी का मामला है और उसमें भी आप का पलड़ा भारी होता दिख रहा है. वजह यह कि पिछले दो माह में केंद्र में भाजपा सरकार के रहते जिस तरह रेल किराये, चीनी, टमाटर, प्याज एवं पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि हुई, उससे दिल्ली की जनता और खासकर वह मध्य वर्ग, जो आम आदमी पार्टी से छिटका था, निराश हो सकता है.

शशि शेखर

भारतीय राजनीति की चाल, चरित्र और चेहरे को समझना हो, तो लोकसभा चुनाव के बाद से दिल्ली (राज्य) में सरकार बनाने को लेकर चल रही रस्साकशी और आरोप-प्रत्यारोप पर ध्यान देने की ज़रूरत है. यहां राजनीति के सारे रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं. हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप, विधायकों के टूटने-बिखरने की ख़बरें, बंद दरवाजों के पीछे चलने वाली बैठकों के दौर आदि-आदि. कोई भी ऐसी पार्टी नहीं, जिसे इस कवायद से अलग देखा गया हो. भले ही कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि न करे, लेकिन यह ख़बर पक्की है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों ने सरकार बनाने की कोशिश की. भाजपा की बात करें, तो खुद भाजपा ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक उसके संपर्क में हैं और इस दावे में काफी हद तक सच्चाई भी है. दूसरी तरफ़, आम आदमी पार्टी ने भी खुद यह कहा कि भाजपा उसके विधायकों को 20 करोड़ रुपये का ऑफर दे रही है. कुछ ऐसा ही दावा कांग्रेस के विधायकों ने भी किया कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए उनसे समर्थन मांग रही है.

कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों का पूरा घटनाक्रम आपको भारतीय राजनीति के कई रंगों से रूबरू कराता है. आम चुनाव में भारी जीत हासिल करने वाली भाजपा अपने ही द्वारा बनाए गए उच्च नैतिक मानदंडों की वजह से खुलकर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल नहीं खेल पाई. सब कुछ पर्दे के पीछे चलता रहा. उसे यह उम्मीद थी कि आप के नए विधायक आसानी से उसके साथ आकर मिल जाएंगे और इस तरह सरकार बन जाएगी तथा उसकी नैतिकता की दीवार भी ढहने से बच जाएगी. लेकिन, अरविंद केजरीवाल ने हॉर्स ट्रेडिंग की बात जमकर उछाली, जिससे खुलेआम विधायकों में तोड़-फोड़ का खेल संभव नहीं हो पाया. न भाजपा ऐसा कर पाई और न खुद आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी पार्टी से अलग होने का साहस दिखा सके.

भाजपा के राज्यस्तरीय नेता तो सरकार बनाने की बात से इंकार नहीं कर रहे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस का जोर फिर से चुनाव कराने पर है और वह नहीं चाहता कि लोकसभा में इतनी जबरदस्त जीत के बाद जनता के बीच यह संकेत जाए कि भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने के लिए किसी भी तरह का तिकड़म अपना सकती है. दूसरी तरफ़, आम आदमी पार्टी को भी अब यह एहसास हो चुका है कि उसे कांग्रेस से मदद नहीं मिलने वाली है और अगर भाजपा ने दिल्ली (राज्य) में सरकार बना ली, तो उसके लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. इस वजह से अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव कराने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर राष्ट्रपति तक से मिल रहे हैं.

वैसे, इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनाव ही बेहतर विकल्प साबित होगा. बहरहाल, अब इस पर ग़ौर करना दिलचस्प होगा कि अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं, तो क्या तस्वीर निकल कर सामने आएगी. आम धारणा के मुताबिक, दिल्ली के दंगल में अब सिर्फ़ दो ही खिलाड़ी बचे हुए हैं यानी भाजपा और आम आदमी पार्टी. कांग्रेस को अब लोग इस खेल से बाहर मान रहे हैं. वैसे, किसी राजनीतिक दल की भविष्यवाणी करना हमेशा ख़तरों से खेलने जैसा होता है. यह सही है कि पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम और खासकर दिल्ली का परिणाम बताता है कि कांग्रेस की हालत आज एक क्षेत्रीय दल से भी बदतर हो गई है. लेकिन, इसी के साथ यह भी याद रखना दिलचस्प होगा कि बीते लोकसभा चुनाव ने कई ऐसे राजनीतिक दलों को फिर से स्थापित कर दिया है, जिनकी कल तक ओबेचुअरी (शोक संदेश) लिखी जा रही थी. मतलब यह कि भारतीय क्रिकेट और भारतीय राजनीति, दोनों का ताल्लुक भविष्यवाणी विज्ञान से नहीं है, फिर भी मौजूदा तस्वीर यही दिखाती है कि कांग्रेस अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी वर्तमान स्थिति को भी बरकरार रख ले, तो उसके लिए बड़ी बात होगी. और, कहीं अगर वह 8 से 10 पर पहुंच जाती है, तो फिर उसके लिए जश्न मनाने का मौक़ा होगा.

दिसंबर 2013 में भाजपा के पास जश्न मनाने के तमाम मौक़े मौजूद थे. दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी बस सामने ही थी, लेकिन 32 सीटें पाने के बावजूद भाजपा के सामने से वह कुर्सी ओझल हो गई. वजह, आम आदमी पार्टी द्वारा 28 सीटें जीतना. अब लोकसभा में अकेले दम पर 282 एवं दिल्ली की सभी सातों सीटों पर कब्जा जमाने वाली भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह से तैयार है. उसे उम्मीद है कि दिल्ली की सत्ता आसानी से मिल जाएगी. लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में आई कमी के चलते उसे खुद को कोई चुनौती मिलती नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा उसके अति-आत्मविश्वास की वजह से भी हो सकता है. दिल्ली की सात सीटों पर भले ही आम आदमी पार्टी हार गई हो, लेकिन वह सभी सीटों पर बढ़े हुए मत प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रही. दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी निवासियों, छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वाले लोगों और ऑटो-रिक्शा चालकों के बीच अभी भी इस पार्टी की विश्वसनीयता बरकरार है. बातचीत के दौरान ऐसे लोग बेहिचक कहते हैं कि केजरीवाल की 49 दिनों की सरकार में पुलिस ने उनसे रिश्वत लेनी बंद कर दी थी. आरटीओ एवं अन्य सरकारी दफ्तरों से दलाल गायब हो गए थे. बिजली-पानी की राजनीति और उसमें अंतर्निहित दांव-पेंच चाहे जो भी हों, लेकिन दिल्ली का एक बड़ा तबका ऐसा है, जिसे 3 महीने के लिए ही सही, भारी-भरकम बिजली-पानी के बिल से मुक्ति मिली. ये सारे तथ्य ऐसे हैं, जिनकी जांच आप सरेराह चलते हुए दिल्ली की सड़कों पर लोगों से बातचीत द्वारा कर सकते हैं.

> **यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में अंतिम समय तक भाजपा के उम्मीदवार विजय गोयल थे, लेकिन शायद यह अरविंद केजरीवाल की मॉरल अथॉरिटी का ही कमाल था कि भाजपा को गोयल की जगह ईमानदार छवि वाले हर्षवर्धन को सामने लाना पड़ा. कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि अभी दिल्ली में निश्चित तौर पर भाजपा बनाम आप के बीच फिफ्टी-फिफ्टी का मामला है और उसमें भी आप का पलड़ा भारी होता दिख रहा है.**

इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भाजपा की दिल्ली इकाई डॉ. हर्षवर्धन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद एक मजबूत लीडरशिप की कमी से जूझ रही है. अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, तो दिल्ली भाजपा अपना मुख्यमंत्री किसे प्रोजेक्ट करे, इस पर भी काफी संशय है. उसके पास फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे सके. यह चुनौती राजनीतिक तौर पर कम, व्यक्तिगत ईमानदारी, नैतिकता और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले एक शख्स के तौर पर ज़्यादा है. यानी विभिन्न मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल की आलोचना तो हो सकती है, लेकिन एक मॉरल अथॉरिटी, जो उनके पास है, उसके मुकाबले अभी भाजपा के पास कोई उम्मीदवार नहीं है. यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में अंतिम समय तक भाजपा के उम्मीदवार विजय गोयल थे, लेकिन शायद यह अरविंद केजरीवाल की मॉरल अथॉरिटी का ही कमाल था कि भाजपा को गोयल की जगह ईमानदार छवि वाले हर्षवर्धन को सामने लाना पड़ा.

कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि अभी दिल्ली में निश्चित तौर पर भाजपा बनाम आप के बीच फिफ्टी-फिफ्टी का मामला है और उसमें भी आप का पलड़ा भारी होता दिख रहा है. वजह यह कि पिछले दो माह में केंद्र में भाजपा सरकार के रहते जिस तरह रेल किराये, चीनी, टमाटर, प्याज एवं पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि हुई, उससे दिल्ली की जनता और खासकर वह मध्य वर्ग, जो आम आदमी पार्टी से छिटका था, निराश हो सकता है. यह निराशा इस वर्ग को एक बार फिर केजरीवाल के पास पहुंचा सकती है. और, अगर ऐसा हुआ, तो संभव है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर भाजपा के हाथ से निकल जाए. वैसे, यह भी एक राजनीतिक भविष्यवाणी है, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि भारतीय राजनीति और क्रिकेट के लिए भविष्यवाणी करना हमेशा ख़तरों से खेलने जैसा होता है.■

shashishekhar@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया ने आयोजित की इफ़्तार पार्टी

बीते 23 जुलाई को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चौथी दुनिया परिवार की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न समुदायों, धर्मों एवं राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने शिरकत की. पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मोरारका और चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने अतिथियों का स्वागत किया. इफ्तार पार्टी को कई प्रसिद्ध हस्तियों ने संबोधित भी किया, जिनमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, विदेश राज्यमंत्री जनरल वी के सिंह, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एवं प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काट्जू, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी, जगदीश टाइटलर, मौलाना कल्बे रूशैद रिजवी और आचार्य प्रमोद कृष्णन आदि शामिल थे.

भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने इस मौक़े पर कहा कि इस इफ्तार पार्टी और पाकिस्तान में जिन इफ्तार पार्टियों में वह जाते हैं, कोई अंतर नहीं है. मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते और सुधरेंगे. इफ्तार पार्टी में विभिन्न वर्गों के लोगों ने शिरकत की, जिनमें भाजपा सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, कांग्रेस नेता आस्कर फर्नांडीज, सुनील शास्त्री, सीपीआई के वरिष्ठ नेता ए बी बर्धन, जद (यू) सांसद के सी त्यागी, झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी, एनसीपी नेता डी पी त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैय्यर, सेराज पारचा, एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जगमोहन सिंह राजपूत, जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व वाइस चांसलर शाहिद मेहंदी और आल इंडिया लिंग्विस्टिक कमीशन के प्रो. अख्तरुल वासे प्रमुख रूप से शामिल थे.

चौथी दुनिया पिछले कई सालों से इफ्तार पार्टी का आयोजन करता आ रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना होता है. ■

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

प्रधानमंत्री का खुद चीन के साथ अच्छा संबंध हो गया है और वह जापान जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया के मामलों में भारत की पहले जो श्रेष्ठ स्थिति थी, अब उसमें कमी आ रही है. बेशक, वह समय याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब भारत अपेक्षाकृत एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था था, लेकिन जवाहर लाल नेहरू के दिनों में ऐसे मामलों में भी, जिनसे भारत का संबंध नहीं था, उनकी सलाह संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा ली जाती थी. वे दिन लद गए हैं.

समान विचारधारा वाले लोग एकजुट हों

नई सरकार को अब लगभग दो महीने हो गए हैं. नियमित प्रशासन चल रहा है. वास्तव में कोई यह अंतर नहीं बता सकता, किसकी सरकार चल रही है. सरकार नौकरशाहों द्वारा चलाई जा रही है, पुलिस सिस्टम द्वारा चलाई जा रही है. सिस्टम चलता जा रहा है. सरकार की पहली नीति का संकेत बजट में किए गए दावों से मिलता है. सामान्य धारणा यही है कि यह पिछली सरकारों के बजट से ज़्यादा अलग बजट नहीं है. हालांकि, इस पूरे वर्ष के दौरान इस सबको और विभिन्न योजनाओं को कैसे लागू किया जाता है, उसी से पता चलेगा कि ज़मीन पर कोई बदलाव आता है या नहीं. अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी.

हालांकि, एक सामान्य राजनीतिक परिदृश्य के लिए ध्यान देने योग्य दो बातें हैं. जहां तक सरकार का सवाल है, तो यह अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर बहुत निष्क्रिय है. अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कुछ चल रहा है, उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं. राज्यसभा में विदेश मंत्री ने एक चौंकाने वाला बयान दिया और कहा कि चूंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी चाहिए. हमें उनमें से किसी के भी प्रति अभद्र नहीं होना चाहिए. बयान में अभद्र जैसा शब्द संसद में ज़ुबान फिसलने से निकला हो, यह संभव नहीं है. मेरे मुताबिक इसमें कोई असभ्यता नहीं है, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं. हमारी संसद लोकतांत्रिक है और उसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए.

कुछ सदस्य ऐसे होंगे, जो फिलिस्तीन के लिए शांति चाहते हैं और कुछ सदस्य ऐसे होंगे, जो इजराइल के पक्ष में होंगे. चर्चा के बाद बहुत संभव है कि एक निष्पक्ष विचार सामने आए और एक प्रस्ताव पारित हो. सरकार इससे दूर क्यों चली गई, यह एक रहस्य है. लेकिन, एक अलग मुद्दा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन करने के लिए एक मजबूत फॉरेन ऑफिस की ज़रूरत है. प्रधानमंत्री का खुद चीन के साथ अच्छा संबंध हो गया है और वह जापान जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया के मामलों में भारत की पहले जो श्रेष्ठ स्थिति थी, अब उसमें कमी आ रही है. बेशक, वह समय याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब भारत अपेक्षाकृत एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था था, लेकिन जवाहर लाल नेहरू के दिनों में ऐसे मामलों में भी, जिनसे भारत का संबंध नहीं था, उनकी सलाह संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा ली जाती थी. वे दिन लद गए हैं. अभी भी भारत के पास एक महत्वपूर्ण भूमिका बाकी है. हम दुनिया की आबादी का छठवां हिस्सा हैं. हम एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश हैं. बेशक, नए प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स में अच्छी पहल की है, एक नए विकास बैंक के रूप में इस पहल का नतीजा भी देखने को मिला है, लेकिन विदेश नीति के मामलों में हमारे दृष्टिकोण को मजबूत बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए.

अब विपक्ष को देखिए! यह वास्तव में दु:खद है कि सौ साल पुरानी पार्टी कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि नेता विपक्ष का पद उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि सदन की शक्ति की 10 फ़ीसद संख्या भी उसके पास नहीं है. मैं यह सुनकर हैरान हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि अगर उन्हें नेता विपक्ष का दर्जा नहीं मिलता है, तो वे अदालत में जाएंगे. यह एक मजाक है. संसद संप्रभु है, अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. संसद के अधिकारों को मजबूत करने की बजाय कांग्रेस पार्टी अदालत में जाकर उसे कमजोर करना चाहती है. अदालत इस पर हंसेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे कि देखिए, हम आप लोगों की तुलना में अधिक समझदार हैं. यह सब एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है. एक बिंदु कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है. पहले विपक्ष के नेता के लिए कुछ सामान्य भूमिका थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई निदेशक, सीवीसी के चयन में विपक्ष के नेता से परामर्श किया जाना चाहिए. अब क्या होगा, अगर विपक्ष का कोई नेता नहीं है? एक सीमित मुद्दे के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के पास तीन विकल्प हैं, या तो कोई भी विपक्ष का रोल नहीं निभाएगा या राज्यसभा में नेता विपक्ष लोकसभा में भी विपक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे या फिर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता विपक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा. इसमें कोई कठिनाई नहीं है. यह एक बहुत छोटी-सी बात है, जिसे बिना किसी कठिनाई के हल किया जा सकता है, लेकिन नेता विपक्ष का पद अपने अधिकार के तौर पर मांगना एक अच्छी बात नहीं है. यह एक गलत परंपरा है. यह एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा और संसद की लाचारी इससे सामने आएगी.

संसद से अलग बात करें, तो मुझे ग़ैर कांग्रेस-ग़ैर भाजपा दलों को अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ न करते देखकर आश्चर्य हो रहा है. मुझे लगता है कि उन सबको एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए. नीतीश और लालू बिहार में एक साथ आ रहे हैं, यह एक अच्छा संकेत है. अभी मैंने पढ़ा है कि कांग्रेस उनके साथ शामिल होना चाहती है, यह भी एक अच्छा संकेत है. चुनाव आया और चला गया, फिर पांच साल के बाद चुनाव होंगे. अभी राज्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए पहल शुरू करनी चाहिए. आख़िरकार, भारत में इतने राज्य हैं, जहां विभिन्न दलों द्वारा शासन चलाया जा रहा है. नैतिक रूप से कमजोर होने की ज़रूरत नहीं है.

संसद से अलग बात करें, तो मुझे ग़ैर कांग्रेस-ग़ैर भाजपा दलों को अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ न करते देखकर आश्चर्य हो रहा है. मुझे लगता है कि उन सबको एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए. नीतीश और लालू बिहार में एक साथ आ रहे हैं, यह एक अच्छा संकेत है. अभी मैंने पढ़ा है कि कांग्रेस उनके साथ शामिल होना चाहती है, यह भी एक अच्छा संकेत है. चुनाव आया और चला गया, फिर पांच साल के बाद चुनाव होंगे. अभी राज्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए पहल शुरू करनी चाहिए. आख़िरकार, भारत में इतने राज्य हैं, जहां विभिन्न दलों द्वारा शासन चलाया जा रहा है. नैतिक रूप से कमजोर होने की ज़रूरत नहीं है. उन सभी लोगों को, जो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी मूल्यों में विश्वास रखते हैं, एक साथ मिलना चाहिए और एक नीति दस्तावेज बनाकर जनता के लिए एक विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए. आख़िर सरकार बहुत बड़े-बड़े वादों के साथ सत्ता में आई है. कोई भी अपने द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं कर सकता है. भाजपा अभी अपनी अधिकतम ऊंचाई पर है. अगले पांच साल में यह इससे अधिक नहीं, बल्कि कम अंक ही हासिल करने जा रही है. लेकिन, अन्य राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस को सिर्फ़ 44 सीटें मिलीं, इसके लिए उसे इतना मनोबल गिराने की ज़रूरत नहीं है.

अन्य दल और भी छोटे हैं. वामदलों के पास भारत की राजनीति में खेलने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है. यहां तक कि भाकपा और माकपा को अपने विलय के बारे में सोचना चाहिए. वामपंथ को खुद को मजबूत करना चाहिए. भारतीय राजनीति अभी मंथन की स्थिति में है. दु:खद यह होगा अगर कोई अपने प्रयास छोड़ देता है, जैसे आज लोगों ने इस नव-उदारवादी आर्थिक नीति को स्वीकार कर लिया है. अगर धर्मनिरपेक्षता को हानि पहुंचती है, तो देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. यह एक दु:खद दिन होगा. इसलिए सही सोच वाले लोगों और बड़ी-छोटी पार्टियों को एक साथ एक दिशा में आगे आना होगा और ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जो समाज के बड़े तबके को स्वीकार्य हों. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

अब देर करना बहुत घातक होगा

वैसे तो समय काफी पहले आ चुका है, जब संपूर्ण व्यवस्था के बारे में बात हो. बात पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि व्यवस्था के जितने महत्वपूर्ण अंग हैं, वे काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन कामों का उद्देश्य या परिणाम जनता के सुख की जगह दु:ख में निकल रहा है. अब अगर कहें कि व्यवस्था के अंगों के बीच में ज़िम्मेदारी का अभाव बढ़ रहा है और फ़ैसला लेने का मनमाना तरीका विकसित हो रहा है, तो कतई गलत नहीं होगा. और, अभी अगर हमने बातचीत नहीं की, तो फिर मौजूदा व्यवस्था संकट में पड़ जाएगी.

व्यवस्था से मतलब लोकतंत्र को चलाने वाले चार प्रमुख अंगों से है यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया. इनमें तीन अंग घोषित हैं और चौथे के रूप में लोकतंत्र में माना जाता है कि इन घोषित तीनों अंगों के बीच जब अंतर्विरोध पैदा हो जाए, तो मीडिया उनके बारे में उन अंतर्विरोधों को सफाई के साथ जनता के सामने रखे, बल्कि उस असंतुलन को दूर करने की कोशिश भी करे. कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज का तरीका देश में हर साल बिगड़ता गया और अब जब हम 2014 में हैं, नए चुनाव हो चुके हैं, उसके बावजूद कार्यपालिका और विधायिका ज़िम्मेदारी के एहसास से कोसों दूर हैं. उन्हें लगता है कि जो पिछले साठ सालों से हो रहा है, वही होते रहना चाहिए. कार्यपालिका और विधायिका एक तरीके से हाथ में हाथ डालकर जनता की तकलीफें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहीं.

इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका है. न्यायपालिका की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि एक स्तर तक आंखों के आगे खुलेआम किसी भी जगह भ्रष्टाचार के कई नमूने देखे जा सकते हैं. अदालतों ने अवमानना का डर इतना बैठा रखा है कि उनका स्टिंग ऑपरेशन करने की कोई सोच नहीं रहा, लेकिन अगर स्टिंग ऑपरेशन हो, तो हम देखेंगे कि एक स्तर तक क्या-क्या गुल खिलाए जाते हैं. यह सही है कि अदालतों का दुरुपयोग भी ज़्यादा होने लगा है. जहां सही ढंग से हस्तक्षेप की गुजारिश की जाती है, वहीं बहुत सारे ऐसे निहित स्वार्थ हैं, जो सही फ़ैसले को रोकने के लिए अदालतों का दुरुपयोग करते हैं और इसकी वजह से इतने मुकदमे अदालतों में लंबित पड़े हैं कि जिसके ऊपर सचमुच अन्याय हो रहा है, उसकी मदद अदालतों से हो ही नहीं पाती. न्याय इतना महंगा हो गया है कि भारत की जेलों में 30 से 40 प्रतिशत ऐसे लोग बंद हैं, जो न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय तक जा ही नहीं पाते. पर यह तो इसका एक पहलू है.

न्यायपालिका का दूसरा पहलू अभी देश की सर्वोच्च अदालत में देखने को मिला. देश के एक प्रमुख उद्योगपति सुब्रत रॉय का उदाहरण काफी होगा. सुब्रत रॉय के ऊपर एक अनजान आदमी ने मुकदमा किया और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाद-विवाद हुआ. माननीय न्यायधीशों ने सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया और आदेश दिया कि वह 20 हज़ार करोड़ रुपये नकद अदालत में जमा करें, तब उन्हें जमानत मिलेगी. यह शायद दुनिया के इतिहास का पहला मुकदमा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 20 हज़ार करोड़ रुपये नकद जमा करने की शर्त रखी. जो इस कारोबार का मुखिया है, जिसे वे 20 हज़ार करोड़ रुपये जमा करने हैं, जिसकी राय के बिना, मदद के बिना और फ़ैसला लिए बिना न रुपये इकट्ठे हो सकते हैं, न निकाले जा सकते हैं, न संपत्ति बेची जा सकती है, वह व्यक्ति जेल में बंद है.

उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों से अदालत में जब यह कहा गया कि आख़िर सुब्रत रॉय को किस जुर्म में जेल में रखा गया है, क्या कुछ साबित हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वह जेल में कहां हैं? अंग्रेजी में उन्होंने कहा, ही इज इन अवर कस्टडी. यह वक्तव्य भारतीय लोकतंत्र की भावना के कितना अनुकूल है, इसके बारे में बात होनी चाहिए. यह व्यवस्था के एक अंग के काम करने के तरीके के ऊपर संदेह पैदा करता है. सर्वोच्च न्यायालय पुलिस-दारोगा की तरह व्यवहार करे, यह समझ से परे है. हमारे देश की न्याय व्यवस्था लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

अगर सरकार या कार्यपालिका किसी के मौलिक अधिकारों पर हस्तक्षेप करती है या काम करने में बाधा डालती है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय या हमारी न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी और जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसे सहूलियत देगी. पर हम जिस उदाहरण की बात कर रहे हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायधीशों के फ़ैसले को स्वीकार करते हुए, सम्मान करते हुए यह सवाल दिमाग में बार-बार कौंध रहा है कि आख़िर वे कौन से आधार हैं, जिन पर एक व्यक्ति, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फ़ैसले पर अमल कराना है, वह खुद जेल में है. सर्वोच्च न्यायालय कोई बात सुनने को तैयार नहीं है. और, अब तो एक नया ऑब्जर्वेशन सामने आया है कि अगर सुब्रत रॉय को किसी सौदे या ज़मीन बेचने या 20 हज़ार करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कुछ करना है, तो वह जेल से बाहर आएं, बातचीत करें और उस एक-दो घंटे के बाद फिर जेल में चले जाएं. हमारा आग्रह सर्वोच्च न्यायालय से नहीं है, हमारा आग्रह इस देश में लोकतंत्र बचाए रखने का ज़िम्मा लिए हुए संविधान से है. चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका, उसे संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए. जहां कोई अपनी सीमा लांघे, उसे अपने आप ब्रेक लगा देना चाहिए. इस अपेक्षा के तहत हम यह सवाल उठाते हैं कि अब अगर बातचीत नहीं होगी, तो कोई भी अंग कभी भी निरंकुश हो सकता है और दूसरे की बात नहीं मान सकता है.

सर्वोच्च न्यायालय के न केवल जनहित याचिकाओं, बल्कि दूसरी तरह के मुकदमों में दिए गए आदेश का पालन नहीं हो पाया है और सर्वोच्च न्यायालय को इसकी चिंता नहीं है. दूसरी विडंबना यह है कि खुद लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने की ज़िम्मेदार राजनीतिक पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद पाने के लिए लोकसभा के नियमों का भी उल्लंघन कर रही है और हठधर्मिता से कह रही है कि वह इस मुद्दे को लेकर अदालत में जाएगी. लोकसभा में एक बार बहुत बड़ी बहस हो चुकी है कि सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है या लोकसभा बड़ी है. लोकसभा क़ानून बनाती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, इसलिए सर्वसम्मति से यह माना गया कि लोकसभा या संसद का स्थान सर्वोच्च है, पर उस स्थान को ही प्रश्नवाचक दायरे में लाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है. शायद सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायधीश सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे कि इस राजनीतिक पार्टी के महान ज्ञानी लोगों को एक बार न्यायालय में आने दीजिए, फिर देखिए, हम उनका कैसा मखौल उड़ाते हैं.

मीडिया इस तरह के सवालों को उठाने की बजाय चापलूसी, चमचागीरी और अज्ञानता का उदाहरण हर जगह पेश कर रहा है. मीडिया जनता के सवालों से दूर है, जनता की तकलीफों से दूर है, देश के विकास से दूर है. मीडिया देश में पैदा हो रहे जल संकट, पर्यावरण संकट, बेरोज़गारी संकट, भ्रष्टाचार के संकट और महंगाई के संकट को अपना विषय नहीं बनाता. वह हर उस विषय को अपने हाथ में लेता है, जिसका नतीजा जनता की तकलीफों से जनता का ध्यान भटकाना होता है. हम मीडिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, हम न्यायपालिका के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, पर हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि सुब्रत रॉय के मामले को ध्यान में रखकर यह बहस तो होनी ही चाहिए कि हमारी व्यवस्था के चारों अंग क्या सचमुच सही काम कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़े दिनों में अंतर्विरोध उस जगह पर पहुंच जाएं, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली शक्तियां लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था से ज़्यादा शक्तिशाली रूप में सामने खड़ी दिखाई देंगी, इस चिंता को समझने का समय आ गया है. ■

editor@chauthiduniya.com

नई सोच और नई उम्र के संपादक

एस पी ने तो बंबई में एक पूरा दल बना लिया था, जो हर महीने अपने वेतन से आपातकाल के ख़िलाफ़ लड़ाई में मदद करता था. उन दिनों बंबई से आठ पेज का पर्चा निकलता था आवाज़, जिसके प्रकाशन में लगने वाली रकम का इंतज़ाम एस पी करते थे. गणेश मंत्री उसके वैचारिक पक्ष में अपना योगदान देते थे. फिल्म फेयर के संपादक विक्रम सिंह भी उन लोगों में से थे, जो नियमित आर्थिक मदद देते थे. जब एस पी को इस बात का पता चला, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह विक्रम सिंह को सरकार परस्त मानते थे. बाद में एस पी और विक्रम सिंह ने मिलकर कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा, जो उस समय सरकार में ही बड़े पदों पर थे. प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर ने इसके छपने का इंतज़ाम कराया था. उनके दोस्त एवं पॉपुलर पब्लिशिंग हाउस के मालिक स्वर्गीय रामदास भटकल अपने प्रेस में उस पर्चे को छपवाते थे. सेंटर फॉर परफार्मिंग आर्ट की रजनी पटेल, प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग एवं अमोल पालेकर भी इस टीम के सदस्य थे. प्रिया तेंदुलकर अब नहीं रहीं, पर उन्होंने भी काफी मदद की थी. श्याम बेनेगल एवं मणि कौल आपातकाल के विरोधियों को, जितनी भी मदद हो सकती थी, देते थे.

ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि इनसे इस बात का आभास तो होता है कि यदि पत्रकार के मन में खुद आग न हो, तो वह लोगों को झिंझोड़ने वाली पत्रकारिता नहीं कर सकता. उसे सही-गलत की पहचान होनी ही चाहिए. आपातकाल में घटने वाली घटनाओं से एस पी के भीतर का पत्रकार शायद बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा होगा. इसीलिए जब उन्हें रविवार संभालने का मौक़ा मिला, तो उन्होंने वह सब किया, जो उन्हें धर्मयुग में करने का मौक़ा नहीं मिला था. गणेश शंकर विद्यार्थी एवं गांधी जी ऐसे पत्रकार थे, जो घटना के सच वाले पहलू के साथ खड़े होते थे. एस पी को यही धारा पसंद थी. उन्हें उस दौर की पत्रकारिता से चिढ़ थी, जिसमें बातें साफ़-साफ़ नहीं कही जाती थीं. धर्मयुग उन्हें इसका उदाहरण लगता था. वह कुछ कर नहीं सकते थे, पर अपने दोस्तों से इस बावत बात अवश्य करते रहते थे. लेकिन एस पी ने डॉ. धर्मवीर भारती एवं गणेश मंत्री को अपने गुरु के रूप में स्वीकारा और उनकी प्रतिभा को हमेशा याद किया.

कुछ इसी तरह की सोच अकबर की भी थी. सबसे पहले वह वीकली से निकले और आनंद बाज़ार ग्रुप की साप्ताहिक पत्रिका संडे के संपादक बने. अकबर संडे के पहले संपादक थे तथा उन्होंने संडे की कल्पना ही ऐसी की थी, जिसने अंग्रेजी में भी नई पत्रकारिता की शुरुआत की. लेकिन अकबर को इतिहास इसलिए ज़्यादा याद करेगा कि उन्होंने हिंदी में रविवार की कल्पना की और उसके लिए उन्होंने सुरेंद्र प्रताप सिंह को कप्तान के रूप में चुना. अकबर को इतिहास इस बात के लिए भी याद करेगा कि उन्होंने आनंद बाज़ार पत्रिका के मालिक अवीक सरकार को हिंदी पत्रिका निकालने के लिए तैयार किया. अक्सर बंगाली भाषा के लोग बंगला के बाद अंग्रेजी को ही तरजीह देते हैं, पर हिंदी की पत्रिका को महत्व मिले, यह कभी-कभी ही होता है. अकबर ने ही अवीक सरकार को इस बात के लिए राजी किया कि रविवार स्वतंत्र साप्ताहिक के रूप में निकले, न कि संडे के अनुवाद के रूप में. उन दिनों ऐसे वरिष्ठ हिंदी पत्रकारों की संख्या काफी थी, जो एस पी को न केवल अपने से छोटा मानते थे, बल्कि यह दावा भी करते थे कि सुरेंद्र को तो उन्होंने ही बनाया है. पर जब रविवार के लिए संपादक चुनने का सवाल आया, तो अकबर के मन में कोई संशय था ही नहीं. उन्होंने एस पी को ही चुना. अकबर साफ़ कहते थे कि उन्हें एस पी ही चाहिए, क्योंकि जिस पत्रकारिता की शुरुआत वह करना चाहते थे, उसके लिए अंग्रेजी में वह स्वयं को और हिंदी में एस पी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे. इस तरह इस बात का सेहरा अकबर, जिन्हें उनके मित्र प्यार से एम जे कहकर बुलाते हैं, के सिर बंधा कि पहली बार हिंदी पत्रकारिता में नेतृत्व का ज़िम्मा यानी संपादक की कुर्सी पच्चीस साल के नौज़वान को मिली. यह बात अंग्रेजी के लिए भी लागू हुई, क्योंकि अकबर स्वयं एस पी के हमउम्र थे.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं. ■

जब रविवार प्रारंभ हुआ, तो उसके संपादक के रूप में एम जे अकबर का नाम छपा, पर जल्दी ही उस जगह अकबर की राय पर सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम छपने लगा. दोनों ने मिलकर अंग्रेजी और हिंदी में खोजी पत्रकारिता का वह अध्याय शुरू किया, जो पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णकाल की ख्याति प्राप्त कर गया. रविवार की जिन दिनों कल्पना हो रही थी, वे दिन भारतीय इतिहास व भारतीय पत्रकारिता के दमन के दिन थे. यह संयोग ही था कि एक ओर आपातकाल समाप्त हो रहा था, तो दूसरी ओर रविवार की कल्पना साकार रूप ले रही थी.

जब रविवार प्रारंभ हुआ, तो उसके संपादक के रूप में एम जे अकबर का नाम छपा, पर जल्दी ही उस जगह अकबर की राय पर सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम छपने लगा. दोनों ने मिलकर अंग्रेजी और हिंदी में खोजी पत्रकारिता का वह अध्याय शुरू किया, जो पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णकाल की ख्याति प्राप्त कर गया. रविवार की जिन दिनों कल्पना हो रही थी, वे दिन भारतीय इतिहास व भारतीय पत्रकारिता के दमन के दिन थे. यह संयोग ही था कि एक ओर आपातकाल समाप्त हो रहा था, तो दूसरी ओर रविवार की कल्पना साकार रूप ले रही थी. 28 अगस्त, 1977 को रविवार का पहला अंक निकला और उसके कुछ महीने पहले मोरारजी देसाई की सरकार शपथ ले चुकी थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

इतिहास लेखन में ऐसा करना एक राजनीतिक विचारधारा की एकरूपता थी. धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों के बीच भी कई विभेद थे, जो अब खुलकर सामने आ गए हैं. आख़िर क्यों एक इतिहासकार अपने लेखन के दौरान महाभारत को एक गंभीर विषय के रूप में व्याख्यायित नहीं कर सकता? निश्चित रूप से यह महाकाव्य एक कहानी है और पौराणिक भी. इसके बहुत से संस्करण हैं, लेकिन इसके मूल में खूनी लड़ाई है, जिसमें नरसंहार के भी लक्षण हैं. अगर आप इस युद्ध का उदाहरण लें, तो 18 अक्षौणी सेनाओं के बीच 18 दिनों तक चले इस युद्ध के अंत में सिर्फ़ 10 लोग जीवित बचे थे. अगर यह महाकाव्य बताता है कि उत्तरी भारत के सभी क्षत्रिय युवा इस युद्ध में मार दिए गए थे, तो हमें इस बात की जांच करनी चाहिए.

महाभारत पर वैचारिक महाभारत

डॉक्टर जेम्स अशर बाइबिल के विद्वान थे. जेनेसिस के अध्यायों के अध्ययन के दौरान गणना करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर ने दुनिया की रचना 4004 बीसी में की थी. वह बाइबिल की गणना के अनुसार तो सही थे, लेकिन ऐतिहासिक रूप से गलत थे. आज भी डारविन को नकारने वाले अशर की गणना का उदाहरण देते हैं. बाइबिल एक धार्मिक किताब है, जिसमें ऐतिहासिक तथ्य और मिथक कथाएं दोनों ही हैं. लेकिन, कई जगहों पर खुदाई के दौरान कुछ ऐसे तथ्य भी मिले हैं, जो बाइबिल में अंकित हैं. इलियड और ओडिसी को भी पुरातन ग्रीक सभ्यता के शुरुआती दिनों का सच जानने के लिए खंगाला जाता रहा है. इन महाकाव्यों के कुछ हिस्से दंतकथा हैं और कुछ ऐतिहासिक.

इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए चेयरमैन डॉक्टर वाई एस राव महाभारत की ऐतिहासिक किताब के रूप में जांच कराए जाने के इच्छुक हैं. जब भी कोई इस तरह की बात करता है, तो इसे लेकर धर्मनिरपेक्ष विद्वानों की तरफ़ से गुस्से का इजहार किया जाता है. ये विद्वान ऐसा महसूस कर रहे हैं कि राव को नई सरकार द्वारा इतिहासकारों पर हिंदुत्व के एजेंट के रूप में थोपा जा रहा है. वैसे, इतिहासकारों के बीच मतभेद और कलह दुनिया के हर कोने में देखने को मिलते हैं. ब्रिटिश इतिहासकार गृहयुद्ध पर चार सौ वर्षों तक बहस करने के बाद भी राजी नहीं होंगे, लेकिन वे साक्ष्यों पर राजी हो जाएंगे. इसके विपरीत अमेरिकी इतिहासकार उनके देश में गृहयुद्ध के कारणों को लेकर राजी ही नहीं होंगे.

भारत में भी इतिहासकारों के बीच मतभेद रहे हैं. भारतीय विद्या भवन ने हिंदू नज़रिये से छह खंडों में भारतीय इतिहास की किताब छापी थी, लेकिन वह नेहरू के उदारवादी दिन हुआ करते थे. उसके बाद इंदिरा गांधी का समय आया. अच्छे इतिहासकार सिर्फ़ समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोग ही हुआ करते थे, उन्हें संरक्षण दिया जाता था. जो भी उनके सोचने के तरीके से अलग होता था, वह या तो दक्षिणपंथी करार दिया जाता था या फिर कभी-कभी सांप्रदायिकतावादी भी. मैं यह बात अपने एक अनुभव से कह रहा हूं, जिसे मैंने कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया लिखने में भागीदारी के दौरान हासिल किया था. डॉक्टर धर्मा कुमार, जिनका मैं असिस्टेंट था, जैसी विदुषी को हमेशा साम्राज्यवाद की समर्थक के तौर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आधुनिक इतिहास के लिए कभी वामपंथ के नज़रिये को सही नहीं माना. वह यह नहीं मानती थीं कि 200 वर्षों का ब्रिटिश शासन पूरी तरह से त्रासदी था. वह अपने आलोचकों पर हंसा करती थीं.

इतिहास लेखन में ऐसा करना एक राजनीतिक विचारधारा की एकरूपता थी. धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों के बीच भी कई विभेद थे, जो अब खुलकर सामने आ गए हैं. आख़िर क्यों एक इतिहासकार अपने लेखन के दौरान महाभारत को एक गंभीर विषय के रूप में व्याख्यायित नहीं कर सकता? निश्चित रूप से यह महाकाव्य एक कहानी है और पौराणिक भी. इसके बहुत से संस्करण हैं, लेकिन इसके मूल में खूनी लड़ाई है, जिसमें नरसंहार के भी लक्षण हैं. अगर आप इस युद्ध का उदाहरण लें, तो 18 अक्षौणी सेनाओं के बीच 18 दिनों तक चले इस युद्ध के अंत में सिर्फ़ 10 लोग जीवित बचे थे. अगर यह महाकाव्य बताता है कि उत्तरी भारत के सभी क्षत्रिय युवा इस युद्ध में मार दिए गए थे, तो हमें इस बात की जांच करनी चाहिए. विद्वान इतिहासकार डी डी कोसांबी का अनुमान है कि उस समय की प्राचीन भारतीय संस्कृति के पास पर्याप्त मिनिरल रिसोर्सेज, तकनीक आदि नहीं थे, इसी वजह से इतना बड़ा युद्ध समायोजित नहीं किया जा सका. उनके अनुसार, इसमें लगभग 50 लाख लोगों की मौत हुई थी.

लेकिन, मान लीजिए कि सिर्फ़ 50 हज़ार लोगों की मौत हुई थी, तो भी क्या यह इतिहासकारों या किसी एक इतिहासकार के लिए जांच का विषय नहीं है? अगर ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई रामचंद्र थे, तो क्या उसकी जांच नहीं की जानी चाहिए? इतिहासकारों की वास्तविक आपत्ति यह नहीं है कि राव ने यह इच्छा जाहिर की है कि वह महाभारत की एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में जांच करेंगे, बल्कि इतिहासकार इसलिए नाराज हैं, क्योंकि वह आईसीएचआर के चेयरमैन हैं.

आख़िरकार वे इस विषय पर अपना शोध कर रहे हैं. मेरे लिए दिक्कत यह है कि किसी भी पार्टी की सरकार आईसीएचआर के चेयरमैन के चुनाव में क्यों उपस्थित रहती है? आख़िर क्यों इतिहासकार ही अपने चेयरमैन का चयन नहीं करते? यह सच है कि सरकार ही रिसर्च के लिए अनुदान देती है, इस वजह से इसके पीछे उसका होना लाजिमी है. इस समय जो इतिहासकार शिकायत कर रहे हैं, वे भी राजनीतिक रूप से पसंदीदा ही हैं. बेहतर रिसर्च के लिए फोर्ड की तर्ज पर ऐसे रिसर्च फाउंडेशन होने चाहिए, जो बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडे के इतिहास लिखें. समय आ गया है कि भारत में रिसर्च फंडिंग को गंभीरता से लिया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

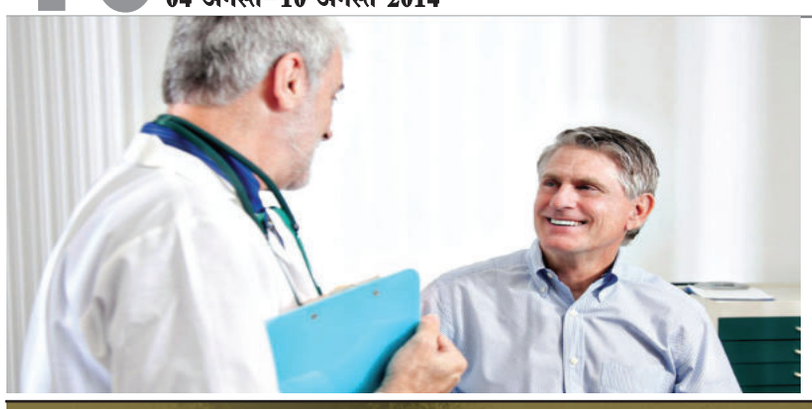

रेडियोथेरेपी का उपयोग प्रोस्टेट कैंसर के प्राथमिक उपचार के तौर पर किया जाता है. इस पद्धत्ति में सुई के जरिया अल्ट्रासाउंड की मदद से रेडिएशन, प्रोस्टेट में दाखिल किया जाता है. रेडिएशन का इस्तेमाल उस वक़्त भी होता है जब सर्जरी के जरिया कैंसर ग्रस्त उतकों को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है.

प्रोस्टेट कैंसर

इलाज के बाद सामान्य जीवन संभव है

- तेजी से बढ़ रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के मामले
- प्रोस्टेट के आकार में असामान्य बढ़त की वजह से होता है
- प्रारंभिक चरण में यह प्रोस्टेट तक सीमित रहता है
- इस स्थिति में यह ज्यादा घातक नहीं होता है

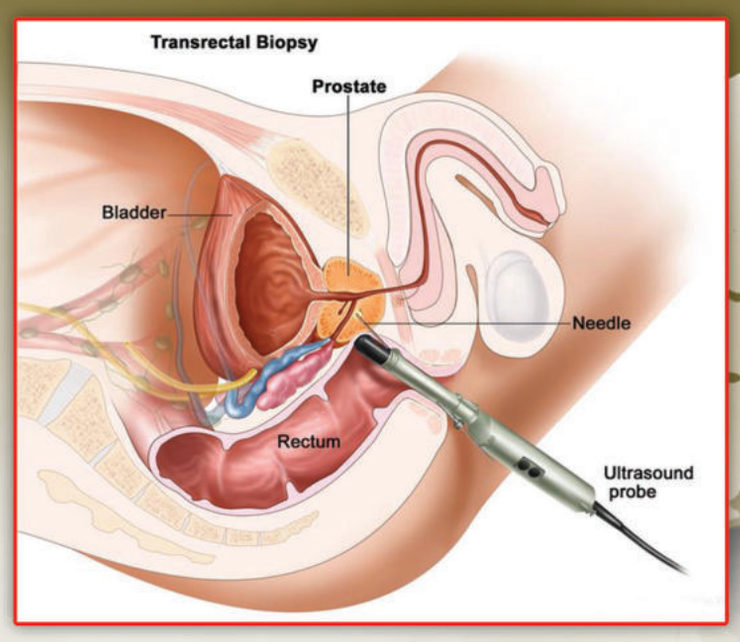

शफीक आलम

वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड इंटरनेशनल के मुताबिक वर्ष 2012 में वैश्विक स्तर पर प्रोस्टेट कैंसर के 11 लाख मामले दर्ज किए गए. चूंकि इस तरह का कैंसर उम्र के आखिरी पड़ाव में होता है इसलिए इस तरह के ज्यादातर मामले उन देशों में देखने को मिलते हैं जहां पर लोगों की जीवन प्रत्याशा(लाइफ एक्सपेक्टेंसी) अधिक होती है. चूंकी भारत में भी लोगों की औसत उम्र तकरीबन 63 वर्ष है इसलिए प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में यहां भी तेजी से बढ़ रहे हैं. नेशनल कैंसर रजिस्टरी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस इस रोग की वृद्धिदर सालाना एक फीसदी है. दूसरे तरह की तुलना में प्रोस्टेट कैंसर की पहचान प्राथमिक अवस्था में हो जाती है इसलिए इसका इलाज संभव हो जाता है, और इलाज के बाद मरीज सामान्य तरह जीवन जी सकता है.

प्रोस्टेट, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में प्रोस्टेट अखरोट के आकर की एक ग्रंथि(ग्लैंड) होती है. यह उम्र के साथ बढ़ती जाती है. इस ग्रंथि के आकार में वृद्धि पुरुषों में पाए जाने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करती है. यह ग्रंथि पुरुषों के जननांग से जुड़ी होती है. प्रजनन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह ग्रंथि में शुक्राणुओं को पोषण देने और वीर्य को तरल रखने का काम करती है. प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख संक्रमण होता है. प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट ग्रंथि में उम्र के साथ होने वाली असामान्य वृद्धि से संबंधित होता है, जिसे बीएचपी (बेनाईन हाईपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट) कहते हैं. बीएचपी कैंसर नहीं होता बल्कि इसका संबंध पेशाब में तकलीफ से होता है. इस वृद्धि के कारण पेशाब की नली दब जाती है, इस वजह से पेशाब करने में परेशानी होने लगती है. इसका ईलाज दवाईयों या सर्जरी के जरिया किया जा सकता है.

क्या है प्रोस्टेट कैंसर?

प्रोस्टेट कैंसर को प्रोस्टेट का कार्सिनोमा कहते हैं. यह कैंसर प्रोस्टेटाइटिस या बीपीएच की तरह प्रोस्टेट में उम्र के साथ होने वाली वृद्धि में असामान्य तेज़ी की वजह से होता है. आम तौर पर यह कैंसर धीरे–धीरे बढ़ता है और प्रारंभिक चरण में यह केवल प्रोस्टेट तक ही सीमित रहता है इस स्थिति में यह ज्यादा घातक नहीं होता है. यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाए तो यह आक्रामक रुख अख्तियार कर लेता है, और तेजी से शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचने लगता है. नतीजतन रोगी को बहुत ज्यादा दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ता है. अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है.

किसे हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर ?

चालीस वर्ष से कम आयु के लोगों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कम या कहें या कहें नहीं के बराबर देखने को मिलता है. लेकिन उम्र का पचासवां पड़ाव पार करते ही इस बीमारी का खतरा लगातार बढ़ता जाता है. क्योंकि इस कैंसर के तकरीबन 70 प्रतिशत मामले 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में पाए गए हैं. हालांकि अभी तक हो रहे शोध के बावजूद यह मालूम नहीं हो सका है कि वृद्धावस्था में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा क्यों बढ़ जाता है. लेकिन शोध यह जरुर बताते हैं कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर किसी न किसी रूप में ज़रूर पाया जाता है. जो लोग अपने खाने में फल–सब्जियों की बजाए लाल मांस और उच्च वसा वाले डेयरी उत्पादों का ज्यादा सेवन करते हैं उनको इस रोग से ग्रसित होने का खतरा ज्यादा होता है. मोटापा भी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ाता है. अनुवांशिक कारणों की वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है, यानी जिस परिवार में इस बीमारी की हिस्ट्री रही हो, उस परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस बीमारी से ग्रसित होने का खतरा रहता है. रिसर्च से यह साबित हुआ है अनुवांशिक जीन म्युटेशन भी इसका कारण हो सकता है. कुछ मामलों में इसे बहुत पुराने प्रोस्टेटाइटिस, संक्रमित व्यकित के साथ यौन संबंध बनाने, धुम्रपान और शराबनोशी से भी जोड़ कर देखा जाता है.

प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण

पेशाब में जलन, रात में बार–बार पेशाब लगना, सामान्य से ज्यादा पेशाब होना, पेशाब करने में कठिनाई होना, पेशाब रोकने मेंहद से ज्यादा तक़लीफ होना, पेशाब का रुक–रुक कर आना, पेशाब में खून आना, वीर्य में भी खून आना आदि इसके लक्षण हैं. शरीर में, विशेष कर हड्डियों में लगातार दर्द का रहना, कमर के निचले हिस्से खासकर कुल्हे और जांघों में जकड़न रहना आदि इसके अन्य लक्षण हैं.

जांच और पहचान

ज्यादातर मामलों में प्रोस्टेट कैंसर की पहचान बीमारी के पहले ही चरण में कर ली जाती है. नियमित रेक्टल टेस्ट और सीरम पीएसए (प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन) इसकी पहचान करने का सबसे सबसे कारगर तरीका है. पीएसए का काम ट्यूमर की पहचान करना होता है. इसकी पुष्टि के लिए रोगी की बायोप्सी की जाती है. आमतौर पर यह एक दर्द रहित प्रक्रिया होती है जो यूरोलोजिस्ट द्वारा लोकल एनेस्थीशिया और अल्ट्रासाउंड के जरिया की जाती है. इस दौरान निडिल की मदद से प्रोस्टेट के एक छोटे से हिस्से को निकाला जाता है. इसके बाद इसकी जांच की जाती है. जांच परिणाम सकारात्मक होने की स्थिति में शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने की जांच की जाती है कि इससे शरीर का कौन सा अंग किस स्थिति तक प्रभावित हुआ है. इस के लिया पेल्विक एरिया(कूल्हे के आस–पास) की एमआरआई जांच की जाती है. अगर चिकित्सक को इसके छाती और पेट तक फैलने की आशंका हो तो इसकी जांच के लिए वह एक्स–रे और अल्ट्रासाउंड की मदद लेता है. यह बहुत ही अच्छी बात है कि बात है कि प्रोस्टेट कैंसर के ज्यादातर मामलों की पहचान रोग के पहले चरण में ही हो जाती है. ज्यादातर मामलों में यह संक्रामक नहीं होता है और शरीर के दूसरे हिस्सों को अपनी चपेट में नहीं लेता है, और सिर्फ प्रोस्टेट तक ही सिमित रहता है.

क्या है उपचार

इस कैंसर का विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट होता है. यूरोलॉजिस्ट ही यह निर्णय लेता है कि मरीज़ का इलाज कैसे किया जाए. इसके लिए वह मरीज़ की उम्र, उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी अन्य बीमारियों, कैंसर की अवस्था और बायोप्सी के परिणामों के आधार पर लेता है. आम तौर पर अत्याधिक वृद्ध रोगियों का सक्रिय उपचार नहीं किया जाता है. चिकित्सक ऐसे रोगियों के लिए वैट एन्ड वाच(रुको और प्रतीक्षा करो) की निति अपनाते हैं. एक निश्चित और छोटे अंतराल पर रोगी की जांच की जाती है और यह पता किया जाता है कि कैंसर किस अवस्था में है और इसमें क्या तब्दीली आई है. सामान्य तौर पर प्रोस्टेट कैंसर का ईलाज ऑपरेशन के जरिया किया जाता है और कैंसर ग्रस्त ऊतकों को शरीर से अलग कर दिया जाता है. इस ऑपरेशन को रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी कहते हैं. मरीज़ की दशा, तकनीक और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन की पद्धति का चयन किया जाता है, कई मामले में एक लम्बा चीरा लगा कर ऑपरेशन किया जाता है और कुछ मामलों में लेप्रोस्कोपिक विधि (की–होल सर्जरी) के जरिया ऑपरेशन किया जाता है. इसे दुरबीन प्रणाली भी कहते हैं देश के कुछ चुनिंदा अस्पतालों में रोबोट की सहायता से भी ऑपरेशन किया जाता है. सर्जरी के जरिए ईलाज की सफलता दर बेहद अच्छी है लेकिन इसके कुछ साइड–इफेक्ट भी हैं, जैसे कि नपुंसकता, पेशाब करने में तकलीफ आदि. कई एडवांस स्टेज के मामलों में वृषण (फोते) को निकाल देने की सलाह दी जाती है ताकि कैंसर को फैलने से रोका जा सके.

रेडियोथेरेपी का उपयोग प्रोस्टेट कैंसर के प्राथमिक उपचार के तौर पर किया जाता है. इस पद्धत्ति में सुई के जरिया अल्ट्रासाउंड की मदद से रेडिएशन, प्रोस्टेट में दाखिल किया जाता है. रेडिएशन का इस्तेमाल उस वक़्त भी होता है जब सर्जरी के जरिया कैंसर ग्रस्त उतकों को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है. उसी तरह हारमोन थेरेपी का उपयोग टेस्टेस्टोरोन के स्तर को दबाने के लिए किया जाता है. हारमोनथेरेपी पहले चरण और अंतिम चरण दोनों अवस्था में उपयोगी होता है.कीमोथेरेपी का प्रयोग विकसित अवस्था के कैंसर में होता है जब हारमोनल उपचार से प्रोस्टेट कैंसर का इलाज संभव नहीं हो सकता है. जिस में कैंसर ग्रस्त उत्तकों को मारने और इस के शरीर के दूसरे अंगों में फैलने से रोकने के लिए ताक़तवर दवाओं का उपयोग किया जाता है. क्रायोथेरेपी, रेडियोफ्रिक्वेंसी, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड का उपयोग प्राथमिक अवस्था के रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है. इन पद्धत्तियों का उपयोग उन रोगियों के लिए भी किया जाता है जिनकी उम्र या किसी और कारण से बड़ी सर्जरी नहीं की जा सकती. उपचार में उपरोक्त पद्धतियों का इस्तेमाल कैसे हो इस का फैसला यूरोलोजिस्ट ही करता है. खून की जांच और पीएसए स्तर और अल्ट्रासाउंड के जरिया इस रोग के दोबारा उत्पन्न होने की संभावना को रोकने के लिए किया जाता है. उपचार के जो तरीके हैं उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं लेकिन उन्नत सर्जिकल तकनीक, हार्मोनल थेरेपी, रेडिएशनथेरेपी और कीमोथेरेपी के उपयोग से साइड इफ़ेक्ट को बहुत हद तक कम कर लिया गया है. प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के बाद एक सामान्य ज़िन्दगी गुज़ारना मुमकिन है.

गरीबों के और वंचितों के लिए उपचार

कैंसर का उपचार बहुत ही महंगा है. इसके इलाज का बोझ गरीब आदमी नहीं उठा सकता. ऐसी बहुत सी संस्थाएं है जो गरीब कैंसर मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं. इंडियन कैंसर सोसाइटी उनमें से एक संस्था है जो गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों के कैंसर के उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, इसके लिए उसने कैंसर क्योर फंड स्थापित किया है. कैंसर फंड सालाना 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को कैंसर के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देता है. इसकी अधिक जानकारी और सहायता के लिए http://www.indiancancersociety.org पर संपर्क कर सकते हैं. और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के एक फंड जिसे एचएमडीजी कहा जाता है इसके अंतर्गत 75 हजार कम आय वर्ग के परिवारों को कैंसर के उपचार के लिए 50 हजार से एक लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, इसी तरह राज्य सरकारों की गरीबों के लिए कैंसर के ईलाज के लिए योजनाएं एवं फंड हैं, जैसे पश्चिम बंगाल सरकार कैंसर के उपचार के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है.

अस्पतालों के नाम

बैंगलोर के श्री शंकर हॉस्पीटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर में 200 में से 100 बेड गरीबों के मुफ्त ईलाज के लिए सुरक्षित रखा गया है. टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल, मुंबई, श्री राम कृष्ण कैंसर हास्पीटल, सहारनपुर और एम्स, नई दिल्ली, महावीस कैंसर संस्थान पटना जैसे अस्पतालों में मुफ्त और सस्ता इलाज उपलब्ध है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अगला सीरिया बन जाएगा यूक्रेन

यह बात सुनने मे थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है लेकिन यह सच है. मलेशियाई विमान हादसे के बाद की जो परिस्थितियां बन रही हैं उन्हें देखकर कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है. बीते तीन सालों में हमने सीरिया में रूस और अमेरिका के अहम की जंग में एक देश को बर्बाद होते हुए देखा है. क्रीमिया के मुद्दे पर अगर एक बार फिर अमेरिका और रूस आमने–सामने आ गए तो यूक्रेन ही दोनों के बीच का कुरुक्षेत्र बनेगा और ऐसी अवस्था में उसका हाल भी सीरिया जैसा होने से कोई नहीं रोक सकता है.

अरुण तिवारी

विमान हादसे अक्सर होते रहते हैं. अमूमन इन हादसों में सभी यात्रियों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है. हादसों के पीछे कई तरह के कारण बताए जाते हैं लेकिन मामला ज्यादा गंभीर तब हो जाता है जब राजनीतिक कारणों के लिए यात्री विमान मार गिराए जाएं. ऐसा ही कुछ मलेशियाई विमान एम एच 17 के यात्रियों के साथ हुआ है. यूक्रेन में मार गिराए गए इस हादसे के पीछे क्रिमीयाई विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है. लेकिन असल सवाल यह है क्या ये अप्रशिक्षित विद्रोही लगभग साढ़े तीन किलोमीटर ऊंचाई पर साढ़े सात सौ किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रहे विमान को मार सकने में बिना रूसी सहायता के सक्षम थे? जिस बक मिसाइल सिस्टम के जरिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वह उनके पास कहां से आया? समाजवाद के प्रणेता रूस के इस समाजवाद में साम्राज्यवाद ही दिखता है. यह रूस का घिनौना रूप है.

अमेरिका भी इसके लिए रूस को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानता है. उसका कहना है इस घटना के पीछे रूस के अपने आंतरिक कारण जिम्मेदार हैं जिसके लिए वह विदेशी नागरिकों को भी अपना निशाना बनाने से बाज़ नहीं आया. अमेरिका ने धमकी दी है कि वह इस मामले की जांच कराएगा और इस घटना के पीछे रूस का हाथ सामने आया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए. अमेरिका ने कहा है कि सिर्फ इस दुर्घटना के लिए ही नहीं यूक्रेन में हो रही सभी घटनाओं के लिए सीधे तौर रूस ही जिम्मेदार है. अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन के रूस समर्थक अलगाववादी पुतिन और रूस सरकार की शह के बिना मलेशियाई विमान पर हमला नहीं कर सकते थे. अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मैरी हर्फ ने बताया कि जांचकर्ता अब भी यह पता करने की कोशिश में लगे हैं कि हमलावरों का असल उद्देश्य क्या था. उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम कि उनका इरादा क्या है? जांचकर्ता यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कटघरे में ला सकें.

अमेरिकी खुफिया विभाग के अधिकारियों ने हालांकि इस घटना में सीधे तौर पर रूस की संलिप्तता के सबूत नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस कारण भी मलेशियाई विमान यूक्रेन में गिरा, उसके हालात उत्पन्न करने के लिए रूस ही जिम्मेदार है.

हर्फ ने यह भी कहा कि विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में जांचकर्ताओं को घटनास्थल पर पहुंचने दिया जा रहा है. अमेरिका ने रूस से सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पूर्वी यूक्रेन में आतंकवादी जांचकर्ताओं के काम में बाधा न डालें.

कुछ इसी तरह रूस में ब्रिटेन के राजदूत ने भी इस घटना के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं. इस घटना के तुरंत बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेन्को ने इसे आतंकी साजिश करार दिया था. उन्होंने यह तत्काल यह आशंका जाहिर की थी कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है. यूक्रेन गृहमंत्रालय के सलाहकार ने कहा था कि यूक्रेन की सीमा से आतंकवादियों ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली बक का इस्तेमाल कर विमान को मार गिराया.

क्या है बक मिसाइल

मिसाइल छोडने के लिए बक लांचर सिस्टम काइस्ते माल किया जाता है. इसे 9 के 37 बक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है. इसे सोवियत यूनियन ने शीत युद्ध के समय 1979 में बनाया गया था. बक लांचर से छोड़ी जाने वाली मिसाइल 72 हजार फीट की उंचाई तक मार कर सकती है. इससे एक साथ तीन मिसाइल छोड़ी जा सकती हैं. इस कारण लक्ष्य को भेदने की संभावना काफी ज्याादा होती है. बक मिसाइल सिस्टम को क्रूज मिसाइलों और यूएवी पर हमलों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था. मिसाइल बनाने का काम 12 जनवरी 1972 को शुरू हुआ था. रक्षा उपकरण विशेषज्ञों के अनुसार बक मिसाइल सिस्टम रूस में निर्मित मध्यम रेंज का जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम है. बक मिसाइल सिस्टम अपने पिछले संस्करण एसए 6 से उन्नत है. बक मिसाइल सिस्टम पर मिसाइलों की दिशा निर्धारित करने के लिए रडार प्रणाली भी होती है. एक अन्य रॉकेट पर लक्ष्य बताने वाला स्नोड्रिफ्ट रडार भी मौजूद होता है. मिसाइल लांचर के आधुनिक मॉडल के जरिए ड्रोन विमानों को भी निशाना बनाया जा सकता है.

लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये सारे देश रूस को धमकी दे रहे हैं. दरअसल इस घटना के दूरगामी परिणाम यूरोप और एशिया के कई हिस्सों को एक बार फिर काफी मुश्किलों में डाल सकते हैं. अमेरिका और सोवियत के बीच शीत युद्ध का एक लंबा दौर दुनिया ने देखा है. तकरीबन 45 सालों तक ये दोनो देश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक–दूसरे के विरुद्ध चालें चलते रहे. परिणाम भी सबके सामने है कि सोवियत टूट कर बिखर गया. लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान पुतिन की अगुआई वाले रूस ने एक बार फिर ऐसे कदम उठाए हैं जो सीधे अमरिकी विरोध में होते हैं. सीरिया में हम इसे पिछले तीन सालों से देख रहे हैं.

असल चिंता यह नहीं है कि ये दोनों देश एक बार फिर आमने–सामने आ जाएंगे दिक्कत यह है कि अगर ऐसा होता है तो विश्व के कई देश सीरिया न बन जाएं. जिस तरह से सीरिया के मसले पर रूस वहां की सरकार का समर्थन करता रहा है और अमेरिका विद्रोहियों का, परिणम स्वरूप पूरा देश तबाह हो चुका है. कुछ वैसा ही दूसरी जगहों पर भी हो सकता है. लीबिया के मामले में रूस इकलौता देश था जो गद्दाफी का समर्थन कर रहा था. अब यूक्रेन के साथ रूस के रिश्ते खराब होते ही जा रहे हैं. ऐसे में इस घटना के बाद अमेरिका सीधे तौर पर न सिर्फ रूस पर कार्रवाई कर सकता है बल्कि यूक्रेन को सीधे तौर पर मदद भी पहुंचा सकता है. इसलिए आम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए कि क्रीमिया विश्व का अगला दमिश्क और अलेप्पोह शहर बन सकता है जहां सिवाय बर्बादी और आहों के कुछ और नजर नहीं आएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्कूली बच्चों को निशाना बना रहा इजरायल

बीते एक पखवाड़े से गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र तो जैसे मूकदर्शक बना हुआ उसके सारे कुकृत्य देख रहा है. सैंकड़ों फलस्तीनी उसके हमलों में मारे जा चुके हैं. हजारों घायल हैं, अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं. इस कड़ी में इजरायल ने एक बार फिर स्कू लों को निशाना बनाया है. गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल पर इजरायली सेना के हमले में 16 की मौत हो गई थी.

इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून का वही रटा रटाया बयान सामने आया कि हम इस हमले की निंदा करते हैं. क्या सिर्फ इस तरह की घटनाओं की निंदा करने से ही संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का काम पूरा हो जाता है.

इस घटना पर सबसे ज्यादा हास्यास्पद बयान इजरायल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने दिया. उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में हमास आतंकियों पर इजरायल सेना लगातार रॉकेट हमले कर रही है. इस दौरान यह स्कूल रॉकेट का निशाना बन गया होगा लेकिन हमें अभी भी इस पर विश्वास नहीं है. हम जांच कर रहे हैं. किंतु इस घटना के बारे में वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इजरायली सेना द्वारा छोड़े गए रॉकेट की वजह से स्कूल पूरी तरह तबाह हो गया. स्कूल के कमरों में और अन्य जगहों पर सिर्फ बच्चों के शव और खून नजर आ रहा था.

दरअसल हमलों से बचने के लिए फलस्तीनी लोग स्कूलों में भी शरण लेते है. इसी कारण कई परिवार भी इन हमलों का शिकार बन जाते हैं. हमले की प्रत्यक्षदर्शी महिला लैला अल शिनबरी ने कहती हैं कि हम सभी एक ही जगह छिपे हुए थे कि तभी चार रॉकेट सीधे हमारे सिर के ऊपर स्कूल की छत से टकराए. कुछ ही देर में हर ओर लाशें और खून बिखरा हुआ था और लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी. मेरे बेटे की मौत हो गई है और मेरे सभी रिश्तेदार बुरी तरह घायल हो गए. गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रवक्ता अशरफ अल–किदरा ने बताया कि इजरायली रॉकेट हमले में करीब 16 मारे गए और 200 से ज्यादा बुरी तरह घायल हुए हैं.

शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर

इजरायल–गाजा के बीच जारी संघर्ष में लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है. इजरायली अत्याचार की वजह से इन लोगों को कैंपों की शरण लेनी पड़ रही है. ज्यादातर फलस्तीनियों ने यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के शेल्टर होम्स में शरण ली है. यह संस्था अपने प्रयासों के जरिए इस बात की कोशिश रही है इजरायली सेना, हमास एवं अन्य सहयोगी आतंकी संगठन इस क्षेत्र में रॉकेट हमले कर से बचें. इस संस्था के प्रवक्ता क्रिस गुनीस कहते हैं कि दुनिया के अन्य देशों की तरह यहां भी दो देशों के बीच सबसे ज्यादा कीमत आम जनता को ही चुकानी पड़ रही है. यहां के हालात बेहद गंभीर और खराब हो चुके हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक निरीह लोगों को बचा सकें. इसके लिए हम दोनों ही पक्षों से अपील कर रहे हैं .

विवाद की प्रमुख वजहें

फलस्तीन और इजरायल के बीच सीमा विवाद एंव कई अन्य वजहें हैं जिसकी वजह से दोनों के बीच विवाद होता रहता है. इनमें गाजा में एयरपोर्ट, समुद्री बंदरगाह यहां तक कि रेलवे स्टेशन भी सुविधा नहीं है जिसकी गाजा वासी गाजा छोड़कर इसलिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है. वहीं, इजरायल भी उन्हें चेक पोस्ट के पार जाने की अनुमति नहीं देता. यूएन ने कई बार ऐसी अपील की है कि इजरायल गाजा पर अपना दावा छोड़ दे लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता. गाजा में इजरायल के कई चेक प्वाइंट हैं, जहां उस पार खाद्य सामग्री, दूध और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं. लेकिन यहां पहुंचने के लिए गाजा के लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है. कभी गाजा पट्टी, मिस्र का हिस्सा हुआ करता था. गाजा की आबादी भी काफी घनी है. हमास के आतंकी यहीं छिपकर इजरायल पर रॉकेट दागते हैं और इसका खामियाजा निरीह लोगों को भुगतना पड़ता है. साल 2005 तक इजरायल ने गाजा पर कब्जा बरकरार रखा था किंतु तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन के एक कदम ने पूरी इजरायली राजनीति में भूचाल ला दिया. शेरोन ने गाजा छोड़ने की बात कह दी. इसी के बाद हमास गुट ने गाजा पर नियंत्रण पा लिया. यह कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच विवाद थम नहीं रहा है. लेकिन इजरायली तौर तरीकों को गौर से देखा जाए तो इतने मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार एक ज्यादा ताकतवर देश होने के नाते इजरायल को ही ठहराया जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

हेमाड पंत बोले, बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं. अभी तक मैंने शिरडी के बाज़ार के दर्शन भी नहीं किए और आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाज़ार नहीं गया. फिर आप ही बताइए कि मैं ये चने भला कैसे खरीदता और जब मैंने खरीदे ही नहीं, तब इन्हें खाने की बात तो दूर की है.

दया के सागर साई बाबा

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा दु:ख दूर करने वाले हैं. वह भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखते हैं. पहले हम साई बाबा के चरणों में प्रणाम करें, उनकी कृपादृष्टि मात्र से ही समस्त पाप भस्म होकर नष्ट हो जाएंगे. वह अपने मन में किसी के लिए कोई भेद नहीं रखते. उनके लिए सभी बराबर हैं. भेदभाव उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होता. साई बाबा मूलत: निराकार थे, लेकिन भक्तों के प्रेमवश ही वह साकार रूप में प्रगट हुए. शिरडी में जब आरती समाप्त हो जाती थी, तब साई बाबा मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा एवं प्रेम के साथ भक्तों को उदी वितरित करते थे. बाबा के भक्त भी उनके समक्ष खड़े होकर चरण छूते और उदी वृष्टि का आनंद लेते थे. बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगाते थे. बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था. वह भक्तों को प्रेम से संबोधित करते, ओ भाऊ, अब जाओ, भोजन करो. इसी प्रकार वह प्रत्येक भक्त से संभाषण करते और उन्हें घर लौटाया करते थे.

जब तक अहंकार गुरु–चरणों में अर्पित न कर दिया जाए, तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है. यदि हम निर्भीक हो जाएं, तो सफलता प्राप्त होना निश्चित है. साई बाबा की भक्ति करने से आध्यात्म की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त करके शांति एवं सुख की प्राप्ति हो जाती है. साई बाबा की लीलाओं का श्रवण करके उनका मनन करें. यदि आप इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे, तो उन्हें अपने जीवन–ध्येय और परमानंद की सहज प्राप्ति हो जाएगी. सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, लेकिन हास्य का पात्र स्वयं कोई नहीं बनना चाहता. इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी. जब वह भावनापूर्ण होती, तो अति मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होती थी. इसीलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था, तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति नहीं होती थी.

शिरडी में प्रत्येक रविवार को बाज़ार लगता है. निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहां रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते हैं. मध्यान्ह के समय मस्जिद लोगों से भर जाती थी, लेकिन रविवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती थी कि प्राय: दम ही घुटने लगता था. एक रविवार हेमाड पंत साई बाबा की चरण–सेवा कर रहे थे. शामा बाबा के बाई ओर एवं वामनराव बाबा के दाहिनी ओर थे. इस अवसर पर बाबा के भक्त बूटी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे. भक्त शामा ने हंसकर अण्णा साहेब से कहा, देखो, तुम्हारे कोट की बांह पर कुछ चने लगे हुए–से प्रतीत होते हैं.

ऐसा कहकर शामा ने उनकी बांह स्पर्श की, जहां कुछ चने के दाने मिले. जब हेमाड पंत ने अपनी बाई कुहनी सीधी की, तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने बीनकर उठाए. भक्तों को हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति–भांति के अनुमान लगाने लगे, लेकिन कोई भी यह नहीं जान सका कि चने के दाने वहां आए कहां से और इतने समय तक उसमें कैसे रहे? इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, लेकिन इस रहस्य का भेद जानने के लिए प्रत्येक भक्त उत्सुक था. तब बाबा कहने लगे, इन महाशय (अण्णा साहेब) को एकांत में खाने की बुरी आदत है. आज बाज़ार का दिन है और यह चने चबाते हुए यहां आए हैं. मैं तो इनकी आदतों से भलीभांति परिचित हूं और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं. इसमें आश्चर्य की बात क्या है.

हेमाड पंत बोले, बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं. अभी तक मैंने शिरडी के बाज़ार के दर्शन भी नहीं किए और आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाज़ार नहीं गया. फिर आप ही बताइए कि मैं ये चने भला कैसे खरीदता और जब मैंने खरीदे ही नहीं, तब इन्हें खाने की बात तो दूर की है. भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं, उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी ग्रहण नहीं करता. बाबा, तुम्हारा कथन सत्य है, लेकिन जब तुम्हारे समीप ही कोई न हो, तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं. अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है, क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूं, क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो?

साई बाबा के प्रश्नों का अण्णा साहब ने उत्तर दिया और फिर उनके चरणों पर गिर पड़े. साई बाबा सब कुछ जान लेते थे. जिन भक्तों ने बाबा के उपदेशों का पूर्णत: पालन किया, वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए. साई बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान–चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा देने में समर्थ हैं. झविषय–वासनाओं से आसक्ति नष्ट करके वह भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान एवं वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है. यह सब केवल उसी समय संभव है, जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो और सेवा के पश्चात हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकें. वह हमें कष्टों एवं दु:खों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं. यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो स्वयं ईश्वर के प्रतीक हैं. इसीलिए हमें सद्गुरु के सानिध्य में सदैव रहना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1-जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2-चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3-त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4-मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5-मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6-मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7-जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8-भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9-आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10-मुझमें तीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11-धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सेना में भ्रष्टाचार!

कवर स्टोरी–सेना में भ्रष्टाचार का बोलबाला: मुंह खोलने वाला पागल घोषित होगा (14 जुलाई–20 जुलाई) पढ़ा. प्रभात रंजन दीन के इस आलेख से पता चलता है कि हमारी भारतीय सेना में भी किस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और पदक पाने के लिए किस तरह से फर्जी मुठभेड़ों को अंजाम दिया जा रहा है. चाहे हेलिकॉप्टरों की खरीद का मामला हो अथवा तोपों की खरीद का, कमीशनखोरी ने देश का दीवाला निकाल दिया है. लेखक ने सही कहा कि जब हमारी सेना के अंदर ही इतने विरोधाभास हैं, तो वह चीन या पाकिस्तान के साथ आख़िर कैसे लड़ेगी? सेना के अंदर सक्रिय भ्रष्टाचारी सेना के हथियार और खाने–पीने वाली चीजें बाहर बेच रहे हैं. सरकार को चाहिए कि वह इस मामले की वृहद स्तर पर जांच कराए और दोषी लोगों को जल्द–जल्द पकड़ कर सेना से बाहर किया जाए.

–रविशंकर पांडेय, *गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.*

महंगाई का कारण

आलेख–वायदा कारोबार: जो महंगाई बढ़ाने का वायदा करता है (14 जुलाई–20 जुलाई) में शशि शेखर ने सही कहा है कि महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वायदा कोरबार है. यह सच्चाई है कि इन बढ़ती क़ीमतों का लाभ किसानों को नहीं मिलता. बढ़ती महंगाई का फ़ायदा यदि किसी को होता है, तो केवल बिचौलियों एवं जमाखोरों को. बिचौलिए किसानों से सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री खरीदते हैं और फिर बाज़ार में उसे दोगुने–तिगुने दामों पर बेचते हैं. जमाखोर बाज़ार में खाद्य सामग्री के अभाव की अफवाह फैलाकर महंगाई बढ़ाने का काम करते हैं. इस समय प्याज और आलू के साथ यही हो रहा है. प्याज और आलू दोनों की पैदावार कम नहीं हुई, लेकिन इन दोनों के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं. इसलिए सरकार को बिचौलियों एवं जमाखोरों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

–अंकुर सिंह, *आरा, बिहार.*

मोदी सरकार की चुनौती

आलेख–क्यों पड़ती है महंगाई की मार? (14 जुलाई–20 जुलाई) काफी विचारोत्तेजक है. शफीक आलम सही कहते हैं कि महंगाई बढ़ने का कोई अप्राकृतिक कारण नहीं है, लेकिन महंगाई पर काबू पाना मोदी सरकार के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार. मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान महंगाई का मुद्दा खूब उठाया था. यह बात सही है कि महंगाई आर्थिक स्थिति और बाज़ार में मांग और उपलब्धता पर निर्भर करती है, लेकिन महंगाई बढ़ने का केवल यही कारण नहीं है. बाज़ार में कई ऐसे खाद्य पदार्थों, जिनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी भी क़ीमतें आसमान छू रही हैं. तेल और कई अन्य पदार्थों की क़ीमतें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार पर निर्भर करती हैं, लेकिन वे भी अक्सर आम लोगों की पहुंच से बाहर दिखने लगते हैं. जनता को महंगाई से राहत मिले, इसके लिए सरकार को ठोस क़दम उठाने की ज़रूरत है.

–नरेंद्र कुमार, *रीवा, मध्य प्रदेश.*

गलत नीतियां

आलेख–गलत नीतियों ने बढ़ाई महंगाई (14 जुलाई–20 जुलाई) जानकारीपरक है. वास्तव में यूपीए सरकार का दस साल का कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा. 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रूप में भारत को एक अर्थशास्त्री मिला था, लेकिन मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री होते हुए भी महंगाई रोकने में नाकाम रहे. यूपीए सरकार के इन दस सालों के दौरान महंगाई ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया. मंत्रियों और खुद प्रधानमंत्री ने महंगाई बढ़ने के नए–नए कारण बताए. इस महंगाई के अलग–अलग पैमाने भी गढ़े गए. नई मोदी सरकार और उसके मंत्री भी यूपीए सरकार की नीतियों को गलत मान रहे हैं, लेकिन अब मोदी सरकार का भी कोई बहाना नहीं चलेगा. मोदी महंगाई कम करने के वादे के साथ सत्ता पर काबिज हुए हैं. भाजपा विपक्ष में रहने के दौरान यूपीए की गलत नीतियों को महंगाई का कारण मानती रही है, तो अब उसे सही नीतियां लागू करनी चाहिए और अपने वादे पर अमल करते हुए जनता को महंगाई से निजात दिलानी चाहिए.

–विकास यादव, *गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.*

खुले में शौच की मजबूरी

भारत में आज भी बड़ी संख्या में लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं. गांवों में आज भी महिलाएं अंधेरे में शौच के लिए जाती हैं, जिसके चलते कई बार उन्हें यौन प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है. अभी हाल में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिनमें शौच के लिए गई महिलाओं–युवतियों के साथ बलात्कार हुआ. चुनाव प्रचार के दौरान शौचालय बनाम देवालय संबंधी बयान के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित धर्मगुरुओं की आलोचना का भी शिकार होना पड़ा था. जबकि उनका कहना सही था कि देश को देवालयों से ज़्यादा शौचालयों की ज़रूरत है. बदायूं में शौच के लिए खेतों में गईं दो बहनों के साथ दुष्कर्म और फिर उनकी हत्या के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. भारत सरकार निर्मल भारत अभियान के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन आज भी लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते. रूढ़िवादी एवं संकीर्ण मानसिकता वाले लोग आज भी खुले में शौच को हितकारी मानते हैं. उनका मत है कि खुले में शौच के लिए जाने से मन में ताजगी का एहसास होता है. लेकिन ऐसे लोग इस बात से अंजान हैं कि वे इस बहाने न जाने कितनी बीमारियों को दावत दे रहे हैं. पंचायत स्तर पर शौचालय निर्माण में सरकारी मदद की घोषणा के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है. इसके पीछे प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त ग़रीबी, अशिक्षा और जागरूकता का अभाव है. यदि सरकारी स्तर पर लोगों को जागरूक करके उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया जाए और आर्थिक सहायता दी जाए, तो स्थिति बदलते देर नहीं लगेगी.

–सुधीर कुमार, *गोंडा, उत्तर प्रदेश.*

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

कहानी

वृद्धा का सबक

एक बार की बात है, छत्रपति शिवा जी मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे. एक दिन रात को वह थके–मांदे एक वनवासी बुढ़िया की झोंपड़ी में जा पहुंचे और उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा. बुढ़िया के घर में केवल चावल था, सो उसने प्रेमपूर्वक भात पकाया और उसे ही परोस दिया. शिवा जी बहुत भूखे थे, सो झट से भात खाने की आतुरता में उनकी उंगलियां जल गईं. हाथ की जलन शांत करने के लिए वह फूंकने लगे. यह देखकर बुढ़िया ने उनके चेहरे की ओर गौर से देखा और बोली, सिपाही, तेरी सूरत शिवा जी जैसी लगती है और साथ ही यह भी लगता है कि तू उसी की तरह मूर्ख है. शिवा जी स्तब्ध रह गए. उन्होंने बुढ़िया से पूछा, भला शिवा जी की मूर्खता तो बताओ और साथ ही मेरी भी.

बुढ़िया ने उत्तर दिया, तूने किनारे–किनारे से थोड़ा–थोड़ा ठंडा भात खाने की अपेक्षा बीच के सारे भात में हाथ डाला और उंगलियां जला लीं. यही मूर्खता शिवा जी करता है. वह दूर किनारों पर बसे छोटे–छोटे किलों को आसानी से जीतते हुए शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा बड़े किलों पर धावा बोलता है और हार जाता है. शिवा जी को अपनी रणनीति की विफलता का कारण विदित हो गया. उन्होंने बुढ़िया की सीख मानी और पहले छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने की रीति–नीति अपनाई. इस प्रकार उनकी शक्ति बढ़ी और अंतत: वह बड़ी विजय पाने में समर्थ हुए. शुरुआत हमेशा छोटे–छोटे संकल्पों से होती है, तभी बड़े संकल्प पूरे करने का आत्मविश्वास जागृत होता है.

शिक्षा–बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए पहले छोटे–छोटे संकल्प पूरे करें.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

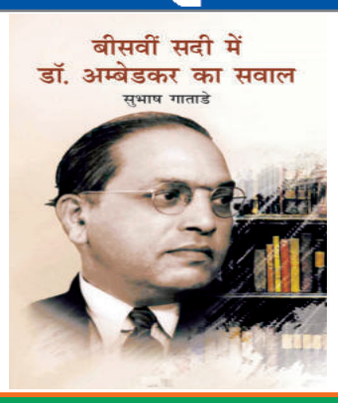

> अंबेडकर पहले नायक हैं जिन्हें अपने को अपने लोगों के बीच स्थापित होने के लिए किसी तरह के प्रचार की आवश्यकता नहीं हुई. उनके लोगों ने खुद उन्हें चुना. वे कहीं भी अपने लोगों पर अपने को थोपते नहीं हैं. इसका कारण है कि वह अपनी जिंदगी अपने समाज के लिए लगाते हैं. उनके विचारों से लोगों का जीवन बदला और उन्होंने समाज को बदला. मार्क्सवाद मजदूर से बाहर नहीं आ पाया. वह कभी जाति के प्रश्न पर विचार करता ही नहीं, क्यों?

विधा का सन्नाटा तोड़ती किताब

अनंत विजय

हिंदी में पाठकों की कमी का रोना दशकों से रोया जा रहा है, छाती कूटी जा रही है, लेकिन कभी वजह ढूंढने की कोशिश नहीं हुई. हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य रहा कि पिछले कई दशकों से रचनात्मकता पर आरोपित वैचारिक आग्रह हावी रहे, जिनके पीछे एक खास राजनीतिक उद्देश्य होता था. उन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जीवन की सच्चाई के नाम पर लिखी गई रचनाओं को उसी वैचारिक आग्रह के आलोचकों ने आगे बढ़ाया और उससे इतर लेखन करने वालों को कलावादी, जनविरोधी कहकर खारिज करते रहे. आलोचक के लिए सबसे ज़रूरी शर्त होती है कि वह किसी भी रचना का बारीकी से अध्ययन करे और फिर उसकी विशेषताओं को रेखांकित करे, लेकिन हिंदी साहित्य के एक लंबे कालखंड में ऐसा नहीं हुआ. लेखक के नाम और उसकी ज्ञात वैचारिक प्रतिबद्धता की कसौटी पर उसकी रचनाओं को कसा गया और सतही तौर पर ऐसी बातें कही गईं, जो लेखकों को अच्छी लगें, चाहे पाठकों के लिए कोई अर्थ निकले या न निकले. रचनाश्रयी आलोचना की जगह विचारधारा की आलोचना ने ली. हर तरह की रचना की आलोचना के लिए एक ही तरह के औजार का इस्तेमाल किया गया. इससे आतंकित लेखकों ने स्वीकार्यता के लिए खास किस्म की रचना लिखनी शुरू कर दी, जो एक खास विचार और धारा को बढ़ावा देने लगी. शिल्पगत नवीनता, वस्तु की नवीनता आदि के आधार पर यथार्थ की नई ज़मीन तोड़ने की कोशिश की गई, खासकर गद्य में. नतीजा यह हुआ कि हिंदी गद्य लेखन में एकरूपता और एकरसता आती चली गई. इसने सृजनात्मक साहित्य का बड़ा नुकसान किया. पाठक तो विमुख हुए ही, लेखकों की रचना शक्ति में कमी आती गई. लेखकों के लिए ज़रूरी होता है पाठकों का प्यार, जिसमें ऐसी ऊर्जा, ऐसी ताकत होती है, जो लेखक को महानता की ऊंचाई पर पहुंचा देती है. आलोचकों का प्यार हासिल करने के चक्कर में हिंदी के कथा लेखकों से पाठकों के प्यार का सिरा छूटता चला गया.

> बांग्ला शब्दों का प्रयोग एक अलग तरह की प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करता है. बांधो तो नाव इस ठांव बंधु में राजेंद्र राव ने मशहूर कथाकार शिवमूर्ति के गांव की यात्रा और वहां अपने प्रवास के बारे में लिखा है. इसमें वह शिवमूर्ति के पारिवारिक जीवन से लेकर उनके लेखन तक पर टिप्पणी करते चलते हैं, लेकिन आधुनिक ग्राम्य जीवन का एक खाका भी खींचते हैं, जैसे किस तरह कच्चे मकानों की जगह ईंट गारे ने ले ली और किस तरह गांव में भी शादी-ब्याह में डीजे की धुनें गूंजने लगी हैं.

एक आलोचक ने लिखा भी है, समय से घिसकर हर विचारधारा सृजनात्मकता में अपने खाने स्वयं बना लेती है. उसका ज़रूरत से ज़्यादा कसाव-बढ़ाव रचनात्मकता की शक्ति नष्ट कर देता है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा खाद-पानी पौधे को जला-सड़ा देता है. हाल के दिनों में कई युवा लेखकों ने अपनी रचनात्मकता वैचारिक लेखन, प्रतीकात्मकता, यथार्थवादी कथात्मकता, अति यांत्रिकता आदि से मुक्त की है, लेकिन विचारधारा ने सृजनात्मक लेखन को जितना नुक़सान पहुंचाया, उसकी भरपाई इतनी जल्दी संभव नहीं. विचाराक्रांत लेखन का एक दुष्परिणाम यह रहा कि उसने हिंदी साहित्य की कई विधाओं को नेपथ्य में धकेल दिया. हिंदी में पिछले कई वर्षों में अगर देखें, तो संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, डायरी आदि बहुत कम लिखे गए. काशीनाथ सिंह और कांति कुमार जैन ने अपने लेखन से यह सन्नाटा तोड़ने की कोशिश की थी. संस्मरण लेखन को लेकर प्रचारित किया गया कि जो लेखक ख़त्म होने लगते हैं, वे संस्मरण लेखन की ओर प्रवृत्त होते हैं. इस दुष्प्रचार का दुष्परिणाम यह निकला कि संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज और यात्रा वृत्तांत जैसी विधाएं साहित्य के हाशिये पर चली गईं. महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी जैसी बेहतरीन संस्मरणात्मक किताबें लिखीं, तो शिवपूजन सहाय की किताब वे दिन वे लोग अब भी अपनी व्यंग्यात्मक और मुहावरेदार भाषा के लिए याद की जाती है.

उपेंद्रनाथ अश्क और राहुल सांकृत्यायन ने भी इस विधा को अपनी लेखनी से समृद्ध किया. रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन ने उल्लेखनीय संस्मरणात्मक लेखन किया. एक जमाना था, जब अन्य भाषाओं के लेखकों के संस्मरण हिंदी में अनूदित हुआ करते थे. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रवींद्र नाथ ठाकुर की रचना मेरा बचपन का हिंदी में अनुवाद किया. इसी तरह रिपोर्ताज हिंदी की अपेक्षाकृत नई विधा थी. रूसी साहित्यकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास इस विधा का जमकर उपयोग किया था, जिसे बाद में हिंदी के साहित्यकारों ने भी अपनाया. बंगाल के अकाल पर रांगेय राघव के लिखे रिपोर्ताज आज भी अपनी मार्मिकता के लिए हिंदी साहित्य में मील का पत्थर हैं, जो बाद में तूफानों के बीच नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए. फणीश्वरनाथ रेणु से लेकर धर्मवीर भारती तक ने कई अच्छे रिपोर्ताज लिखे. लेकिन यह विधा भी धीरे-धीरे नेपथ्य में चला गई. संचार क्रांति के दौर में पत्र-लेखन भी

समीक्ष्य कृति : उस रहगुजर की तलाश है
लेखक : राजेंद्र राव
प्रकाशक : सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : तीन सौ रुपये

लगभग ख़त्म हो गया है.

इस बीच सामयिक प्रकाशन ने दो ऐसी किताबें छापी हैं, जिनसे कुछ उम्मीद जगती है. एक है, मशहूर कथाकार राजेंद्र राव की उस रहगुजर की तलाश में और दूसरी कांति कुमार जैन की महागुरु मुक्तिबोध. राजेंद्र राव की किताब इस मायने में थोड़ी अलहदा है कि उसमें संस्मरण भी हैं, रिपोर्ताज भी और साक्षात्कार आधारित लेख भी. जबकि कांति कुमार जैन की किताब में मुक्तिबोध से जुड़े संस्मरण हैं. समीक्ष्य पुस्तक उस रहगुजर की तलाश में राजेंद्र राव के रिपोर्ताज बेहद शानदार हैं. हाटे बाज़ार नाम के अपने रिपोर्ताज में राजेंद्र राव ने कोलकाता और उसके आसपास के वेश्या जीवन पर बहुत संवेदनशील और मर्यादित ढंग से लिखा है. हाटे बाज़ार की भाषा और उसमें प्रयोग किए गए जुमले इस लेख में बहुधा चमक उठते हैं. देह के बाज़ार में वेश्या और ग्राहकों के बीच की बातचीत की भाषा इतनी मर्यादित है कि वह अपनी बात कह जाते हैं, लेकिन कहीं अश्लीलता नहीं आती. अपने इस रिपोर्ताज में राजेंद्र राव ने समाज में दहेज की कुरीति पर भी चोट की. एक जगह वह बताते हैं कि मनु देह बाज़ार में इस वजह से आई कि कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएं, तो उसकी बड़ी बहन का ब्याह हो सके. मनु बेहद सहजता से कहती है कि जब उसका ब्याह होने वाला होगा, तो उसकी छोटी बहन यहां बैठेगी और उसी सहजता से कह देती है कि उसकी छोटी बहन का ब्याह नहीं होगा, क्योंकि उससे छोटी कोई बहन नहीं है. किस तरह बीच शहर के एक मैदान में महिलाएं एवं लड़कियां अपनी देह का सौदा करने को मजबूर हैं, किस तरह ग्यारह साल की लड़कियां अपनी मजबूरियों के चलते अपनी देह का सौदा कर रही हैं, किस तरह वे पैसे के लिए पुरुषों की हवस मिटाते समय नारकीय यातना सरेआम भुगतती हैं, इस संदर्भ में एक जगह लेखक की भाषा देखिए-दो भयानक पंजे हमारी ओर बढ़ रहे थे. वे हाथों के नाग थे, जिनकी डसन का मार्फिया लेने के लिए लोग मैदान में सौदा करते हैं.

बांग्ला शब्दों का प्रयोग एक अलग तरह की प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करता है. बांधो तो नाव इस ठांव बंधु में राजेंद्र राव ने मशहूर कथाकार शिवमूर्ति के गांव की यात्रा और वहां अपने प्रवास के बारे में लिखा है. इसमें वह शिवमूर्ति के पारिवारिक जीवन से लेकर उनके लेखन तक पर टिप्पणी करते चलते हैं, लेकिन आधुनिक ग्राम्य जीवन का एक खाका भी खींचते हैं, जैसे किस तरह कच्चे मकानों की जगह ईंट गारे ने ले ली और किस तरह गांव में भी शादी-ब्याह में डीजे की धुनें गूंजने लगी हैं. जब वह रात में बाहर निकलते हैं, तो खेतों का वर्णन देखिए-पार निकल कर खेतों की मेड़ पर चलते हुए धनिए की फसल के बीच पहुंच कर मदमाती गंध का जादू देखा, जो दिलोदिमाग पर हावी हो गया, निखालिस वासना की गंध की तरह...अंधेरे में ही मसल कर देखा, बड़ी तीखी गंध उठी, वर्जित दिनों में उठने और छा जाने वाली. इंदौर की यात्रा का भी वर्णन है, जिसमें पाखी के संपादक प्रेम भारद्वाज एवं अपूर्व जोशी उनके साथ थे. एक शहर और उसके मिजाज का बेहतरीन वर्णन, लेकिन यहां आधुनिकता के बोझ तले परंपरा के दबते चले जाने की कहानी भी.

पंडित सोहन लाल द्विवेदी से मार्मिक साक्षात्कार और हंस के संपादक राजेंद्र यादव से बिंदास अंदाज में बातचीत इस किताब की पठनीयता बढ़ाते हैं. कामता नाथ और कृष्ण बिहारी पर लिखे संस्मरणों में लेखक का शहर कानपुर बार-बार आता है. एक ओर जहां कामता नाथ पर लिखे संस्मरणों में छोटे शहर के लेखकों के बीच चलने वाली राजनीति के संकेत हैं, तो कृष्ण बिहारी के बहाने वह एक बेहद प्रतिभाशाली लेखक से पाठकों को रूबरू कराते हैं. कुल मिलाकर राजेंद्र राव की यह किताब लंबे समय बाद हिंदी साहित्य में इस विधा में मौजूद सन्नाटा तोड़ती है. अंत में कहना चाहता हूं कि रिपोर्ताज और संस्मरणों के अंत में उसके लिखे जाने का वर्ष अंकित होता, तो बेहतर होता. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

पुस्तक समीक्षा

अंबेडकर को फिर से जानना

कालू लाल कुलमी

सुभाष गाताड़े जाने माने चिंतक-विचारक हैं. वे बाबा साहब से नये विचार के साथ रू-ब-रू होने की बात करते हैं. बीसवीं सदी में डॉ. अंबेडकर का सवाल कई मायने में महत्वपूर्ण हो गए हैं. अंबेडकर के पास जीवन के भोगे हुए अनुभव और अर्जित ज्ञान का गहरा बोध था. वह इतिहास की व्याख्या पूरे होशोहवास में कर रहे थे. इस वजह से यह आदमी वहां उंगली रखता है जहां उस समय कोई नहीं रख पाया था. कम्युनिस्ट आंदोलन जो पहली बार में आकर्षित कर लेता है. उसे भी इनका कोई भान नहीं था. एक ऐसा समाज जिसको एक धर्म इंसान मानने से इंकार करता है और इस देश का समाज सुधारक वर्ग उसे हल्के में लेता है. बाबा साहब को यही बात सबसे ज्यादा आहत करती है. इसीलिए वह संस्कृति के महल में सेंध मारते हैं. 20 मार्च 1927 को महाड़ के चावदार तालाब जाकर पानी पीते हैं. इस आंदोलन के महत्वपूर्ण पक्षों पर इस किताब में विस्तार से विचार किया गया है. बीसवीं सदी में डॉ.अंबेडकर का सवाल यह किताब बाबा साहब के विचारों की सैद्धांतिकी पर गंभीरता से विचार करती है. आग चावदार तालाब में लगी थी और इससे हिंदू धर्म पर खतरा पैदा हो गया. यह डॉ अंबेडकर का ऐसा हस्तक्षेप था जो पानी के लिए था. बाबासाहब ने समस्याओं का सामना करते हुए बहिष्कृत भारत नाम से अखबार निकाला. 22 अप्रैल के अंक में वे लिखते हैं कि महात्मा गांधी की तरह आज तक हम लोग भी यही मानते आए थे कि अस्पृश्यता हिंदु धर्म के ऊपर लगा कंलक है. लेकिन अब हमारी आंखें खुली हैं और हम समझ रहे हैं कि यह हमारे शरीर पर लगा कलंक है.

समीक्ष्य कृति : बीसवीं सदी में डॉ. अंबेडकर का सवाल
लेखक : सुभाष गाताड़े
प्रकाशक : दखल प्रकाशन
मूल्य : 175 रुपये

जब तक हम इसे हिंदु धर्म पर लगा कलंक समझते थे तब तक इस काम को हमने आप लोगों पर सौंपा था लेकिन अब हमें इस बात का अहसास हुआ है कि यह हमारे शरीर पर लगा कलंक है तो इसे खत्म करने के पवित्र काम को हमने खुद स्वीकारा है.

इस पुस्तक में सुभाष गाताड़े दलित पूंजीवाद पर विस्तार से विचार करते हैं और उनका कहना है कि सवर्ण पूंजीवाद की तरह दलित पूंजीवाद से दलितों का कोई भला नहीं होना है. पूंजीवाद का चरित्र वही है, मुनाफा प्राप्त करना. वह चाहे दलित हो या फिर कोई भी. दलित बुद्धिजीवी चंद्रभान प्रसाद और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग की पहल से डिक्की यानी दलित इंडिया चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया गया. इसके बारे में चंद्रभान प्रसाद कहते हैं डिक्की वेंचर कैपिटल फंड के हकीकत बनने के साथ, भारत का दलित आंदोलन एक नये भविष्य की ओर उन्मुख हुआ है.

अंबेडकर पहले नायक हैं जिन्हें अपने को अपने लोगों के बीच स्थापित होने के लिए किसी तरह के प्रचार की आवश्यकता नहीं हुई. उनके लोगों ने खुद उन्हें चुना. वे कहीं भी अपने लोगों पर अपने को थोपते नहीं हैं. इसका कारण है कि वह अपनी जिंदगी अपने समाज के लिए लगाते हैं. उनके विचारों से लोगों का जीवन बदला और उन्होंने समाज को बदला. मार्क्सवाद मजदूर से बाहर नहीं आ पाया. वह कभी जाति के प्रश्न पर विचार करता ही नहीं, क्यों? जबकि सभी जानते हैं सवर्ण वर्ग कहीं नहीं खपता तो वह मार्क्स के पास जाकर खप जाता है. वहां इसको सुरक्षित जगह मिल जाती हैं. ऐसा नहीं है कि समाज में परिवर्तन नहीं आया लेकिन दोगले लोग तो हर जगह होते हैं. इनके लिए यह ऐसी दीवार है जिसकी आड़ में वे कुछ भी कर सकते हैं. सुभाष गाताड़े पूंजीवाद की तर्ज पर दलित पूंजीवाद में दलितों के लिए कुछ नहीं देखते, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है. बाजार तो हर युग में रहा है और इसका प्रभाव समाज पर हमेशा रहा है. ऐसे में यदि आज का बाजार बहुत ज्यादा खतरनाक है तो इसको खत्म करने के तरीके भी कम खतरनाक नहीं है. वैसे आधार बदलने से अधिरचना नहीं बदलती, लेकिन यहां दोनों ही बदल रहे हैं. फिर शक्ति के स्त्रोत में भी बंटवारा हो रहा है, जिसको नकारा नहीं जा सकता. वैश्विक धरातल पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है.

भारत में वाम आंदोलन की क्या दशा रही है इस पर सुभाष जी विस्तार से विचार करते हैं. बाबा साहब के कहने के बावजूद भी वाम ने कभी जाति के प्रश्न को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया. इसकी कीमत तो चुकानी ही थी. लेकिन अभी भी वक्त है. फुले के विचारों की पड़ताल न करना वाम के लिए सबसे बड़ी गलती रही है. वह चाहे जितने दावे करता रहा हो लेकिन जाति श्रम को नहीं श्रमिकों को ही विभाजित करती रही है, जिसको किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता. लेकिन ये लोग इसको हमेशा अस्वीकार करते रहे. कामरेड आर बी मोरे जो बाबा साहब के समकालीन थे, पार्टी को लिखते हैं कि हमारे पांच करोड़ अस्पृश्य सर्वहारा की समस्या पार्टी के समक्ष खड़ी प्रमुख समस्या है. पार्टी ने कभी इस समस्या को

मार्क्सवादी-लेनिनवादी नजरिये से सही तरीके से विश्लेषित नहीं किया और जिसका नतीजा यह हुआ है कि पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा. लेकिन पार्टी ने न तो इसका जवाब दिया और न ही इस समस्या को समझने का प्रयास किया.

इस किताब को पढ़ते हुए दिमाग के बहुत से झाले साफ हो गए. भाषा और विचार दोनों ही स्तरों पर गाताड़े जी गंभीरता से काम करते हैं. भाषा कहीं भी बोझिल नहीं है. बाबा साहब के विचारों को समझने के लिए निश्चित ही पुस्तक का अहम योगदान है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कहां हैं आपके बच्चे?

एलजी ने बच्चों के लिए वियरेबल किज ऑन लॉन्च किया है. इसे बच्चे घड़ी की तरह अपनी कलाई पर पहन सकते हैं. यह खास तौर पर प्री-स्कूल और प्राइमरी स्कूल के उन छोटे बच्चों के लिए है, जिनकी हर हरकत पर उनके पैरेंट्स नज़र रखना चाहते हैं. जीपीएस और वाई-फाई के जरिये पैरेंट्स अपने स्मार्ट फोन या टैबलेट पर यह देख सकते हैं कि उस वक्त उनके बच्चे कहां पर हैं. पैरेंट्स वन स्टेप डायरेक्ट कॉल केजरिये अपने बच्चों से तुरंत बात भी कर सकते हैं. बच्चे भी किज ऑन के वन स्टेप डायरेक्ट कॉल बटन को दबाकर तुरंत पहले से फीड नंबर पर अपने पैरेंट्स से बात कर सकते हैं. इस नंबर को एंड्रॉयड 4.1 या इससे ऊपर के वर्जन वाले स्मार्ट फोन या टैबलेट से कभी भी बदला जा सकता है. अगर पैरेंट्स की कॉल बच्चा 10 सेकंड में रिसीव नहीं करता है, तो किज ऑन कॉल से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और उसमें लगे माइक्रो-फोन के जरिये वहां की आवाज़ पैरेंट्स सुन सकेंगे. इसमें एक फीचर लोकेशन रिमाइंडर का भी है, जिसके जरिये पैरेंट्स पहले से तय किए गए कई टाइम पर लोकेशन अलर्ट अपने आप पा सकते हैं. ■

एस-5 गैलेक्सी 4-जी प्रीमियम फोन

सैमसंग ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अपना एक नया हैंडसेट गैलेक्सी एस-5 4-जी बाज़ार में लॉन्च किया है. यह फोन उन्हीं जगहों में बेचा जाएगा, जहां 4-जी की सुविधा उपलब्ध है. यह फोन 2.5 जीएचजेड क्वॉड कोर स्नैप ड्रैगन 801 एसओसी से लैस है. इसमें 5.1 इंच का फुल हाई डेफिनिशन एवं सुपर एमोलेड डिस्प्ले है. यह एंड्रॉयड किटकैट पर आधारित है और डस्ट-वाटरप्रूफ है. इसका रियर कैमरा 16 एमपी का है, जिसमें एलईडी फ्लैश, बीएसआई एवं अल्ट्रा एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है. इसका फ्रंट कैमरा 2.1 एमपी का है. इसे धूल एवं पानी से बचाव के लिए आईपी-67 रेटिंग मिली हुई है. इसकी रैम 2जीबी है. 16 जीबी की इंटरनल मेमोरी के साथ इसमें माइक्रो एसडी कार्ड है. इसमें जबर्दस्त वाई-फाई है, जो डेटा बहुत तेजी से डाउनलोड करता है. इसमें हेल्थ एवं हार्ट सेंसर भी है. इसके अलावा इसमें स्मार्ट टीवी रिमोट के लिए इंफ्रारेड एलईडी है. बैट्री 2800 एमएएच की है. यह तीन रंगों में उपलब्ध होगा और इसकी क़ीमत है 53,500 रुपये. इसे खरीदने वाले को कंपनी दो महीने तक फ्री डेटा उपलब्ध कराएगी.■

कैनन का शानदार कैमरा

कैनन 1200-डी में दो लेंस किट हैं, जिनके चलते यह बेहतर रिजल्ट देता है. हालांकि, देखने में यह कैनन के अन्य कैमरों की तरह लगता है, लेकिन इसे कॉम्पेक्ट बॉडी में बनाया गया है.

फोटोग्राफी का शौक रखने वाले लोगों के लिए कैनन ने एक सस्ता एवं शानदार कैमरा कैनन 1200-डी नाम से बाज़ार में उतारा है. यदि आप फोटोग्राफी सीखने के लिए कैमरा लेना चाहते हैं, तो यह एक बेहतर विकल्प है. कैनन 1200-डी में दो लेंस किट हैं, जिनके चलते यह बेहतर रिजल्ट देता है. हालांकि, देखने में यह कैनन के अन्य कैमरों की तरह लगता है, लेकिन इसे कॉम्पेक्ट बॉडी में बनाया गया है. इसमें ज़ूम लेंस के साथ-साथ 3 इंच की एलसीडी स्क्रीन है. कैनन 1200-डी में मौजूद ऑटोफोकस बहुत आकर्षक होने के साथ-साथ काफी तेज और सब्जेक्ट को रीयल फास्ट लॉक करने में सक्षम है. एक्सट्रा ज़ूम लेंस के साथ इसकी क़ीमत लगभग 31,000 रुपये रखी गई है.■

हुआवेइ का मीडियापैड-7 यूथ-2

इसकी स्क्रीन 7 इंच की है और यह उनके लिए बढ़िया है, जो बड़ी एवं चमकदार स्क्रीन की तलाश में रहते हैं. इसका रेजोल्यूशन 1024 गुणा 600 पिक्सल है. इसमें 1.2 जीएचजेड क्वॉड कोर प्रोसेसर है और इसकी रैम 1 जीबी है.

चीनी कंपनियां लगातार अपने नए फोन एवं टैबलेट बाज़ार में उतार रही हैं. इसी कड़ी में चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी हुआवेइ ने अपना नया फेबलेट मीडियापैड-7 यूथ-2 भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी स्क्रीन 7 इंच की है और यह उनके लिए बढ़िया है, जो बड़ी एवं चमकदार स्क्रीन की तलाश में रहते हैं. इसका रेजोल्यूशन 1024 गुणा 600 पिक्सल है. इसमें 1.2 जीएचजेड क्वॉड कोर प्रोसेसर है और इसकी रैम 1 जीबी है. इसके रियर में 3 मेगापिक्सल कैमरा है, जबकि फ्रंट में वीजीए कैमरा है. इस फेबलेट की बैट्री बहुत शक्तिशाली यानी 4100 एमएएच की है. इसकी खासियत यह है कि इसमें वॉयस कॉलिंग भी है यानी आप इसमें नंबर बोलकर डायल कर सकते हैं. यह ऑनलाइन रिटेलर्स के पास उपलब्ध है. इसकी क़ीमत 10,999 रुपये है.■

7 सीटर निसान इवालिया

इवालिया बेहतर स्पेस और लेटेस्ट तकनीक से लैस है, जिसमें सात लोगों के बैठने की सुविधा है. भारतीय बाज़ार में एमपीवी कारों का बोलबाला है. इवालिया में 1.5 लीटर डीसीआई डीजल इंजन है, जो निसान की सन्नी, माइक्रा, फ्लूएंस एवं रेनॉ की अन्य कारों के इंजनों से ज़्यादा दमदार है.

निसान इंडिया ने अपनी एमपीवी (मल्टी परपज व्हीकल) इवालिया का अपडेट मॉडल भारतीय बाज़ार में उतार दिया है. नई अपडेट निसान इवालिया 6 वैरियंट्स में उपलब्ध होगी. इसके शुरुआती मॉडल एक्सई वैरियंट की क़ीमत 8.49 लाख रुपये और उसके टॉप मॉडल की क़ीमत लगभग 10.67 लाख रुपये है.

निसान ने इस कार में बेहतरीन तकनीक के साथ-साथ शानदार फीचर्स शामिल किए हैं. निसान इवालिया पेट्रोल और डीजल टर्बो इंजन पर काम करती है. नई निसान इवालिया में वी शेप्ड क्रोम ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले निसान माइक्रा में देखा जा चुका है. एमपीवी में डबल डिन ऑडियो सिस्टम है, जो सीडी, एमपी-3, यूएसबी एवं एयूएक्स कनेक्टिविटी के साथ काम करता है. इवालिया बेहतर स्पेस और लेटेस्ट तकनीक से लैस है, जिसमें सात लोगों के बैठने की सुविधा है. भारतीय बाज़ार में एमपीवी कारों का बोलबाला है. इवालिया में 1.5 लीटर डीसीआई डीजल इंजन है, जो निसान की सन्नी, माइक्रा, फ्लूएंस एवं रेनॉ की अन्य कारों के इंजनों से ज़्यादा दमदार है. इवालिया 2000 आरपीएम पर 200 एनएम टॉर्क प्रोड्यूज करने में सक्षम है. ■

पोलो का नया मॉडल

न्यू सीट फैब्रिक, सिल्वर पेंटेड सेंट्रल कंसोल जैसे फीचर्स हैं. डुअल फ्रंट एयरबैग्स स्टैंडर्ड फीचर सभी वैरियंट्स में दिया गया है. नई फॉक्सवैगन पोलो में कंपनी ने पिछले मॉडल में इस्तेमाल होने वाला 1.6 लीटर टीडीआई मील हटाकर 1.5 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया है.

फॉक्सवैगन ने भारतीय बाज़ार में पोलो का अपग्रेड वर्जन लॉन्च किया है. कंपनी ने नई पोलो 2014 के इंटीरियर एवं एक्सटीरियर में छोटे-मोटे कई बदलाव किए हैं. नई पोलो की शुरुआती क़ीमत 4.99 लाख रुपये है. फॉक्सवैगन पोलो पेट्रोल एवं डीजल यानी दोनों इंजनों के साथ उपलब्ध होगी. फॉक्सवैगन पोलो 2014 में फ्रंट बंपर, हैडलैंप्स, फोगलैंप्स, नंबर प्लेट, व्हील कवर एवं बैक बंपर नए डिजाइन के साथ पेश किए गए हैं. साथ ही बॉडी कलर और आगे के हिस्से के सभी पार्ट्स नए रंग-रूप में हैं. इंटीरियर की बात करें, तो पिछले वर्जन के मुकाबले इसमें काफी प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है. न्यू सीट फैब्रिक, सिल्वर पेंटेड सेंट्रल कंसोल जैसे फीचर्स हैं. डुअल फ्रंट एयरबैग्स स्टैंडर्ड फीचर सभी वैरियंट्स में दिया गया है. नई फॉक्सवैगन पोलो में कंपनी ने पिछले मॉडल में इस्तेमाल होने वाला 1.6 लीटर टीडीआई मील हटाकर 1.5 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया है. नया डीजल इंजन दो अलग स्टेट टोन 89 बीएचपी और 104 बीएचपी नाम से उपलब्ध है. पोलो पेट्रोल वैरियंट में 3 सिलेंडर एवं 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 16.47 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है. फॉक्सवैगन पोलो पेट्रोल वर्जन की क़ीमत 4.99 लाख रुपये से लेकर 6.07 लाख रुपये तक है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

ग़रीबी की मार झेलते खिलाड़ी

कुछ साल पहले रश्मिता भारतीय टीम में डिफेंडर के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती थीं, लेकिन अब ग़रीबी की वजह से इस युवा महिला खिलाड़ी को फुटबॉल का मैदान छोड़कर पान की दुकान में अपना भविष्य तलाशना पड़ रहा है.

रश्मिता

निशा रानी दत्ता

नवीन चौहान

भारत में खेल और खिलाड़ियों की दुर्दशा का किस्सा बहुत पुराना है. क्रिकेट को छोड़कर अधिकांश खेलों के खिलाड़ी बदहाल हैं. सरकारें खेलों और खिलाड़ियों के प्रति संवेदनशील नज़र नहीं आती हैं. हाल में एक ख़बर उड़ीसा की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी रश्मिता पात्रा की है. ख़बर यह है कि 23 वर्षीय पूर्व भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी रश्मिता अपने और परिवार के जीवनयापन के लिए ओडिशा के अउल गांव में पान की दुकान चला रही हैं. अउल, ओड़िशा के केंदरापारा ज़िले में आता है. यह जगह राजधानी भुवनेश्वर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है. उन पर अभी भी फुटबॉल का जुनून सवार है, लेकिन उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है. इसलिए उन्हें यह काम करना पड़ रहा है. उनके परिवार में पति एवं एक बच्चा भी है. न उनके पास कोई नौकरी है और न पति के पास. कुछ साल पहले रश्मिता भारतीय टीम में डिफेंडर के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती थीं, लेकिन अब ग़रीबी की वजह से इस युवा महिला खिलाड़ी को फुटबॉल का मैदान छोड़कर पान की दुकान में अपना भविष्य तलाशना पड़ रहा है. रश्मिता का कहना है कि फुटबॉल उनके खून में है, लेकिन ग़रीबी ने उनके फुटबॉल करियर को लील लिया है.

रश्मिता एक रोजनदारी मज़दूर की बेटी हैं. उन्होंने 12 साल की उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया था. कोच चित्तरंजन पात्रा एवं प्रमोद पात्रा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया. कई राज्यस्तरीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिली. वर्ष 2008 में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडेरेशन (एएफसी) की क्वालालंपुर में हुई एएफसी अंडर–16 क्वालीफायर प्रतियोगिता में वह पहली बार देश के लिए खेलीं. दो साल बाद वर्ष 2010 में उन्होंने उड़ीसा को अंडर–19 वर्ग का राष्ट्रीय चैंपियन बनाने में प्रमुख भूमिका अदा की. वर्ष 2011 में उन्हें ढाका में हुई सीनियर एएफसी क्वालीफायर प्रतियोगिता के लिए टीम में शामिल किया गया. इसके बाद बहरेन में खेली गई सीरीज में उन्होंने टीम की जीत में मदद की. रश्मिता 2012 में भिलाई में खेली गई राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने वाली उड़ीसा की टीम की सदस्य भी थीं. इतनी उपलब्धियों के बाद भी इस ग़रीब खिलाड़ी को सरकार की ओर से कोई पुरस्कार नहीं मिला. देश के लिए फुटबॉल खेलने के चलते वह हाईस्कूल की परीक्षा भी पास नहीं कर सकीं. इस वजह से उन्हें कोई सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पा रही है. जब उनकी 10वीं की परीक्षा थी, तब वह मलेशिया में चल रहे अंडर–16 क्वालीफायर प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही थीं. 2009 में परिवार की आर्थिक परेशानियों की वजह से उन्हें भुवनेश्वर स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल भी छोड़ना पड़ा. 2013 में उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई, जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी. रश्मिता के कोच रह चुके और वर्तमान में उड़ीसा टीम के कोच चित्तरंजन पात्रा का कहना है कि यह बेहद दु:खद है कि कम पढ़ाई की वजह से रश्मिता को नौकरी नहीं मिल सकती. वह एक ग़रीब परिवार की प्रतिभाशाली खिलाड़ी है. देश में इस तरह की अनेक प्रतिभाएं अक्सर कहीं खो जाती हैं, क्योंकि उन्हें निखारने का कोई बैकअप प्लान सरकार के पास नहीं है.

कुछ ऐसी ही कहानी झारखंड की तीरंदाज निशा रानी दत्ता की भी है. जमशेदपुर के पथमादा गांव निवासिनी निशा ने 2008 में साउथ एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था, साथ ही 2006 में बैंकॉक ग्रैंड प्रिक्स में ब्रांज मेडल जीता था. उन्हें साल 2007 में ताईवान में आयोजित एशियन ग्रैंड प्रिक्स में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था. इन उपलब्धियों के बावजूद 2012 में तंगहाली के चलते और परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्हें अपना चांदी का धनुष महज पचास हज़ार रुपये में बेचना पड़ा था. उन्होंने मणिपुर के एक छात्र को अपना धनुष इसलिए बेच दिया, क्योंकि वह तंगहाली में जीवन बिता रहे अपने परिवार की मदद करना चाहती थीं. निशा के पास धनुष के अलावा और कोई क़ीमती चीज नहीं थी, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल पाते. यह धनुष उन्हें मित्तल चैंपियनशिप ट्रस्ट में कोरियाई कोच ने गिफ्ट में दिया था. इस धनुष की क़ीमत तक़रीबन 5 लाख रुपये थी, लेकिन उन्होंने इसे महज 50 हज़ार रुपये में बेच दिया. निशा ने 13 वर्ष की उम्र में तीरंदाजी करना शुरू किया था. उनके पिता किसान हैं और उनके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है. कई बार पैसों की कमी की वजह से खाद एवं बीज खरीदना भी मुश्किल हो जाता था. घर में दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाते थे. करियर की शुरुआत में उन्होंने वर्ष 2005 में टाटा आर्चरी एकेडमी में प्रवेश लिया, जहां वह वर्ष 2008 तक रहीं. एकेडमी में उन्हें हर महीने स्टाइपेंड के रूप में पांच–छह सौ रुपये मिल जाते थे. वह इन रुपयों में से भी आधे बचा लेती थीं और उनसे परिवार की मदद करती थीं. 2008 में वह बंगलुरू चली गईं, जहां मित्तल चैंपियनशिप ट्रस्ट के साथ कॉन्ट्रेक्ट पर रहीं. उन्हें वहां 3000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे. इसके बाद वह वापस झारखंड आ गईं. तबसे वह अपने गांव में ही थीं और उनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं था. घर की मरम्मत के लिए उन्हें पैसों की तत्काल ज़रूरत थी. उन्होंने झारखंड सरकार से अनुरोध किया था कि पटियाला स्थित खेल संस्थान में प्रवेश लेने के लिए उनकी आर्थिक मदद करे, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी इस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया.

ऐसी ही एक कहानी बिहार की राजधानी पटना में चाय की दुकान चलाने वाले गोपाल प्रसाद यादव की है. एक समय बिहार का गौरव रहे इस तैराक को अपना आत्मसम्मान ताख पर रखकर चाय बेचनी पड़ रही है. गोपाल ने केरल के तिरुवंतपुरम में 1989 में हुई तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया था और कुछ पदक भी जीते थे. गोपाल ने दस सालों तक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बिहार का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन आज यह नौबत है कि उनके पास अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिए न तो पैसे हैं और न आय का कोई अच्छा जरिया. उनका कहना है कि बिहार में खिलाड़ियों की कोई कद्र नहीं है. मुझे देखिए, मैं किस हाल में हूं. मुझे उस वक्त बहुत शर्म महसूस होती है, जब मेरे दोस्त मेरी दुकान पर चाय पीने आते हैं. मेरे लिए पदक जीतने का क्या नतीजा हुआ? मैं अपने तीन बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सका. तैराकी एक महंगा खेल है, मैं गंगा में ही प्रैक्टिस करता था. मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं क्लब ज्वाइन कर सकूं. गंगा का पानी प्रदूषित होने की वजह से मैं लंबे समय तक अभ्यास भी नहीं कर पाता था. कई बार तो मेरे पेट में गंदा पानी चला जाता था, जो शरीर के लिए नुक़सानदायक होता था.

गोपाल ने रिक्शा चलाने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया. उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि लोग उन्हें रिक्शा चलाने की सलाह देने लगे थे. वह सम्मान के साथ जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नेशनल तैराक टी स्टाल खोल लिया. गोपाल ने स्वीमिंग क्लबों में ट्रेनर की नौकरी पाने की भी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे. 1990 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, तब वह उनसे मिले और उन्हें अपनी कहानी बताई. लालू प्रसाद यादव ने उनकी मदद करने का वादा किया, लेकिन बाद में कहीं कुछ नहीं हुआ. आज गोपाल रोजाना चाय की दुकान से 200 से 250 रुपये कमाते हैं. उन्हें लगता है कि बिहार में खेलों और खिलाड़ियों का कोई भविष्य नहीं है. नीतीश कुमार ने भी अपने कार्यकाल में बिहार में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कुछ नहीं किया. इस वजह से आज भी बिहार के बहुत कम खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पा रहे हैं. जो खिलाड़ी कोशिश भी करते हैं, उन्हें अपना भविष्य गोपाल की तरह दिखाई पड़ता है, तो वे भी अपने क़दम पीछे खींच लेते हैं.

झारखंड की पूर्व हॉकी खिलाड़ी नौरी मुंडू भी तंगहाली में जीवन व्यतीत कर रही हैं. उन्हें 19 बार राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई और कई पुरस्कार भी मिले. आजकल वह एक निजी स्कूल में टीचर हैं, जहां उन्हें वेतन पांच हज़ार रुपये मिलते हैं. इसके अलावा वह पारिवारिक व्यवसाय में भी हाथ बटाती हैं. नौरी का कहना है कि उन्होंने आगे बढ़ने की पुरज़ोर कोशिश की, लेकिन धनाभाव ने उनका रास्ता रोक लिया. सरकार की मदद के बिना आगे खेल पाना संभव नहीं था. मध्य प्रदेश की 15 वर्षीय सीता साहू ने वर्ष 2011 में एथेंस में हुए स्पेशल ओलंपिक में 200 और 1600 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीते थे. आज पिता की बीमारी की वजह से उन्हें पानी पूरी बेचना पड़ रहा है. सरकार ने उनके पदक जीतने पर पुरस्कार की घोषणा भी की थी, लेकिन जब 2013 में मीडिया ने इस मामले को उठाया, तब जाकर सरकार ने केवल एक लाख रुपये दिए.

सीता साहू

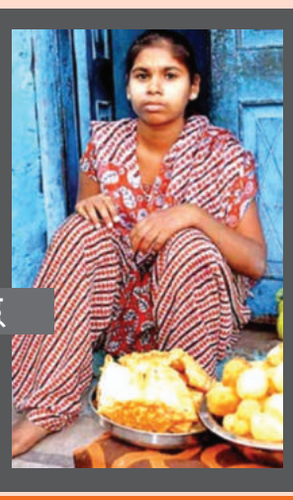

नौरी मुंडू

झारखंड की पूर्व हॉकी खिलाड़ी नौरी मुंडू भी तंगहाली में जीवन व्यतीत कर रही हैं. उन्हें 19 बार राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई और कई पुरस्कार भी मिले. आजकल वह एक निजी स्कूल में टीचर हैं, जहां उन्हें वेतन पांच हज़ार रुपये मिलते हैं. इसके अलावा वह पारिवारिक व्यवसाय में भी हाथ बटाती हैं. नौरी का कहना है कि उन्होंने आगे बढ़ने की पुरज़ोर कोशिश की, लेकिन धनाभाव ने उनका रास्ता रोक लिया. सरकार की मदद के बिना आगे खेल पाना संभव नहीं था. मध्य प्रदेश की 15 वर्षीय सीता साहू ने वर्ष 2011 में एथेंस में हुए स्पेशल ओलंपिक में 200 और 1600 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीते थे. आज पिता की बीमारी की वजह से उन्हें पानी पूरी बेचना पड़ रहा है.

जो कोई भी खेलों को अपने करियर के रूप में अपनाता है, उसकी किशोरावस्था और जवानी अभ्यास में निकल जाती है. वह पढ़ाई में अन्य छात्रों की तुलना में कम समय दे पाता है, कई बार खेल के लिए परीक्षाएं तक छोड़नी पड़ती हैं. सचिन तेंदुलकर एवं महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी दसवीं और बारहवीं पास हैं, लेकिन आज उनके पास सब कुछ है. उनकी सफलता देखकर विश्वविद्यालयों में भी नियम बदल जाते हैं. लेकिन, ग़रीब और निचले तबके से आने वाले वे खिलाड़ी, जो सफल नहीं हो पाते, उनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है. और न ही उनके लिए कोई नियम है कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को विशेष छूट दी जाए. देश और राज्य के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले खिलाड़ियों का जीवन आसान बनाने के लिए सरकारों को ठोस क़दम उठाने की जरूरत है. मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में खिलाड़ियों को खोजने और उनके प्रशिक्षण की बात तो कही है, लेकिन उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है. बीसीसीआई जैसे देश के धनाढ्य खेल बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना शुरू की है. यह काम सरकार को करना चाहिए. खिलाड़ियों के लिए भी सैनिकों की तरह पेंशन का प्रावधान होना चाहिए. जब एक सांसद या विधायक सदन में पहुंच कर पेंशन का हक़दार हो जाता है, तो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी पेंशन के हक़दार क्यों नहीं हो सकते? खेल मूलत: राज्य सूची का विषय है. यदि राज्य सरकारें उस पर बेहतर कार्य नहीं कर रही हैं, तो उसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाना चाहिए, जिससे राज्य और केंद्र सरकार मिलकर खेलों और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए काम कर सकें, ताकि देश सेवा करने वाले खिलाड़ियों का जीवन खुशहाल हो सके. ■

navinonline2003@gmail.com

मणिपुर में रिलीज होगी मेरी कॉम

ओलंपिक विनर बॉक्सर मेरी कॉम के जीवन पर आधारित प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म मेरी कॉम क्या मणिपुर में रिलीज हो पाएगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि मेरी कॉम मूलत: मणिपुर की रहने वाली हैं. पिछले कुछ सालों से उग्रवादियों की धमकियों की वजह से मणिपुर में हिंदी फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं. ऐसे में, निर्माताओं की पूरी कोशिश है कि यह फिल्म मणिपुर में ज़रूर रिलीज हो. मेरी कॉम के प्रोडक्शन से जुड़े अजीत अधारे का कहना है कि मणिपुर मेरी कॉम का होम टाउन है और फिल्म में वहां की कहानी है. इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह फिल्म वहां ज़रूर रिलीज हो. फिल्म को खुद मेरी कॉम भी सपोर्ट कर रही हैं. इस फिल्म की शूटिंग से पहले प्रियंका ने मेरी कॉम के साथ उनकी लाइफ और शेड्यूल को समझने के लिए काफी वक्त भी साथ बिताया. हाल में इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया है. इसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दर्शकों का जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिला. ऐसे में, प्रियंका के प्रशंसकों को पूरी उम्मीद है कि वह एक बार फिर जोरदार परफॉर्मेंस देने वाली हैं.■

बिपाशा के घर बजेगी शहनाई

लंबे समय तक जॉन अब्राहम के साथ रिलेशन में रहने के बाद बिपाशा बसु का ब्रेकअप हो गया. उसके बाद बिपाशा की दोस्ती हरमन बावेजा के साथ हुई और अब जल्द ही बिपाशा उनकी दुल्हन बनने वाली हैं. ख़बर है कि अभिनेता हरमन बावेजा अपनी प्रेमिका बिपाशा के साथ जल्द ही ब्याह रचाने वाले हैं. कहा यह भी जा रहा है कि दोनों गुपचुप एक-दूसरे को अंगूठी पहना कर सगाई की रस्म पूरी चुके हैं, इसलिए अब शादी में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा.

कुछ दिनों पहले हरमन को बिपाशा के पिता के बथर्डे सेलिब्रेशन में बिप्स एवं उनके परिवार के साथ देखा गया था. वैसे, बिपाशा के प्रवक्ता ने इस बात से इंकार किया है कि वह शादी करने वाली हैं, लेकिन बॉलीवुड में यह परंपरा पुरानी है कि सितारे शादी वाले दिन तक शादी से इंकार करते रहते हैं. अब यह देखना होगा कि हरमन-बिपाशा के प्रशंसकों का इंतज़ार कब ख़त्म होता है.■

आमिर बनेंगे खलनायक

फिल्म धूम-3 में निगेटिव किरदार को बख़ूबी निभाने वाले मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को लेकर अफवाह है कि वह एक बार फिर खलनायक के किरदार में नज़र आएंगे. उनकी अगली फिल्म को लेकर भी अटकलों का बाज़ार गर्म है. हो सकता है, आमिर खान निर्देशक शंकर की फिल्म रोबोट के सीक्वल में खलनायक की भूमिका में नज़र आएं. रजनीकांत एवं ऐश्वर्या राय स्टारर इस फिल्म के सीक्वल की शूटिंग इस साल के अंत में शुरू होगी. फिल्म से जुड़े एक शख़्स का कहना है कि आमिर को इस फिल्म के लिए साइन करने को लेकर बातचीत चल रही है. रोबोट के सीक्वल में रजनीकांत एक बार फिर लीड रोल में नज़र आएंगे. फिलहाल फिल्म की कास्टिंग को लेकर बातचीत चल रही है. शंकर द्वारा आमिर को इस फिल्म के लिए साइन करने की यह दूसरी कोशिश है. शंकर ने सबसे पहले रोबोट के रोल के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया था. शाहरुख के इंकार के बाद शंकर ने आमिर को अप्रोच किया, लेकिन आमिर के भी इंकार करने के बाद आख़िरकार शंकर ने रजनीकांत के साथ फिल्म बनाई थी. इस बार भी शंकर आमिर को साइन करना चाहते हैं. देखते हैं, उनकी मेहनत कितना रंग लाती है. ■

फिल्म से जुड़े एक शख़्स का कहना है कि आमिर को इस फिल्म के लिए साइन करने को लेकर बातचीत चल रही है. रोबोट के सीक्वल में रजनीकांत एक बार फिर लीड रोल में नज़र आएंगे.

अजय का एनिमेटेड अवतार

सिंघम की अपार सफलता के बाद अब सिंघम रिटर्न्स लांच होने जा रही है. सिंघम के पहले भाग की तरह इसे सफल बनाने के लिए अजय देवगन ने नई स्ट्रेटजी बनाई है. वह अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के मौक़े पर एक ऐनिमेटेड अवतार में नज़र आएंगे. रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन एवं करीना कपूर हैं. यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी. इसमें भी अजय पिछली फिल्म की तरह बाजीराव सिंघम की भूमिका में नज़र आएंगे. निर्देशक रोहित शेट्टी ने बताया कि प्रमोशन का तरीका सबसे अलग होगा. वैसे भी फिल्म में अजय एवं करीना बड़ा कमाल करने वाले हैं. रोहित एवं अजय साथ में कई हिट फिल्में कर चुके हैं, जिनमें गोलमाल सीरीज की फिल्में भी शामिल हैं. जब इस फिल्म के बारे में रोहित ने प्लान किया था, तो उन्होंने अजय देवगन के अलावा किसी अन्य के बारे में सोचा तक नहीं. वहीं करीना को रोहित के साथ कोई फिल्म करनी ही थी, इसलिए उन्होंने करीना को लेने का प्लान बनाया. अब देखना यह है कि सिंघम रिटर्न्स सिंघम की सफलता को दोहरा पाती है अथवा नहीं और अजय-करीना की जोड़ी एक बार फिर लोगों को कितनी पसंद आती है.■

फेसबुक का चमकता सितारा

हर दिल अजीज कोलंबियाई पॉप सिंगर शकीरा सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की सबसे ज़्यादा पॉपुलर हस्ती बन गई हैं. उनके फेसबुक पेज को 10 करोड़ लोगों ने लाइक किया है. यह उपलब्धि पाकर उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि वह लोगों के प्यार से बेहद खुश हैं. शकीरा का मानना है कि उनकी पहचान इस वजह से बनी और कायम रही, क्योंकि वह अपने प्रशंसकों से लगातार जुड़ी रहीं. इस वजह से उनकी लोकप्रियता में दिन दोगुनी-रात चौगुनी बढ़त होती रही. इस क्षण को स्पेशल बनाने के लिए शकीरा ने एक वीडियो भी अपलोड किया है और अपने प्रशंसकों को थैंक्स कहा है. शकीरा ने सोशल मीडिया की तारीफ़ करते हुए कहा कि यह प्रशंसकों के साथ कम्युनिकेट करने का एक बेहतर माध्यम है. यहां सेलिब्रिटी एवं प्रशंसक, दोनों ही अपने विचारों और उपलब्धियों को आसानी से शेयर कर सकते हैं. शकीरा के बाद सबसे ज़्यादा फैन फॉलोविंग रिहाना और एमिनेम की है. फेसबुक पर रिहाना के 9.10 करोड़ और एमिनेम के 8.9 करोड़ फॉलोवर हैं. शकीरा ट्वीटर पर 12वीं सबसे ज़्यादा फॉलोवर वाली सेलिब्रिटी हैं, ट्वीटर पर उनके 2.6 करोड़ फॉलोवर हैं. ■

सैफ को हिंदी फिल्में पसंद नहीं

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि छोटे नवाब यानी सैफ अली खान हिंदी फिल्में नहीं देखते. उन्हें हिंदी फिल्में पसंद नहीं हैं. हिंदी फिल्मों के दम पर अपना करियर बनाने वाले सैफ को आख़िर हिंदी फिल्में देखना पसंद क्यों नहीं है? इस बारे में सैफ का कहना है कि पहले हिंदी सिनेमा बेहद ड्रामेटिक था और मुझे इतना ज़्यादा ड्रामा पसंद नहीं है. रियल लाइफ में रील लाइफ जैसा कुछ भी नहीं होता. वह कहते हैं, मैं हिंदी फिल्म का हीरो हूं, इसलिए भी हिंदी फिल्में नहीं देखता, क्योंकि आपको थोड़ा-सा ही समय शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल से मिलता है और उसमें आप काम से बाहर की चीजें सोच रहे होते हैं. मैं अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ा चेंज चाहता हूं. ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हिंदी फिल्मों के साथ ही खाऊं, सांस लूं और पूरा वक्त बिताऊं.■

फोटोग्राफरों से परेशान बिग बी

अमिताभ बच्चन इन दिनों काफी परेशान हैं, जिसका दुखड़ा उन्होंने अपने ब्लॉग पर रोया है. वह इन दिनों दो कारणों से काफी परेशान हैं. पहली तकलीफ़ फिल्म शमिताभ में उन्हें अपने लुक से है. दूसरी परेशानी प्रेस फोटोग्राफरों से है, जो दिन-रात उन पर नज़र रखते हैं. ऐसे में, उन्हें अपना नया लुक छिपाए रखने में दिक्कतें आ रही हैं. इन सबसे तंग आकर अमिताभ ने खुद ही ट्वीटर पर अपना नया लुक शेयर कर दिया है. वह सफेद बाल और दाढ़ी में नज़र आ रहे हैं. फोटो के साथ बिग बी ने कैप्शन में अपने इस लुक की तुलना मोजेस के लुक से की है. मोजेस मिस्र के राजकुमार थे, जो बाद में धर्मगुरु बन गए थे. उनका जिक्र बाइबिल और कुरान, दोनों में किया गया है. अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, आज की तारीख में जब लाखों मोबाइल कैमरे आसपास मौजूद हैं, किसी फिल्म या खास अवसर के लिए अपना लुक छिपाए रखना बेहद मुश्किल है. फिल्म पा में भी अपने लुक को बिग बी ने छिपाने की काफी कोशिश की थी. वह चेहरे पर तौलिया लपेट कर सेट पर पहुंचते थे, फिर भी वह लुक लीक हो गया था. दरअसल, पिछले महीने ही सोशल मीडिया पर बिग बी का नया लुक लीक हो गया था. फिल्म शमिताभ अमिताभ बच्चन और फिल्म निर्माता आर बाल्की की तीसरी फिल्म है. फिल्म में अमिताभ बच्चन केकिरदार का नाम शमिताभ है. ■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

04 अगस्त–10 अगस्त 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

कांग्रेस को संजीवनी की तलाश

कांग्रेस बेहद कठिन दौर से गुजर रही है. न सिर्फ़ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश में पार्टी की स्थिति ख़राब है. कांग्रेस आलाकमान ने राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी में एक कुशल राजनेता की छवि अभी तक कांग्रेसी नेता नहीं देख पाए हैं. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली क़रारी शिकस्त के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक समझदारी पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में ग़ैर भाजपा राजनीति एक बार फिर करवट लेने लगी है. कांग्रेस अपने पुराने सहयोगियों मसलन, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को किसी भी तरह अपने से दूर होते नहीं देखना चाहती है. सपा और बसपा नेताओं की भी यही मंशा है, लेकिन वह कांग्रेस को बचाने के लिए अपने हितों की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है. चाहे सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव हों या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती, दोनों की सोच इस मामले में बिल्कुल साफ़ है कि अब राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है. नतीजतन आने वाले दिनों में भाजपा, मोदी और सांप्रदायिकता का भय दिखाकर अल्पसंख्यकों को अपने-अपने पाले में खिंचना सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा. भाजपा के उभार से सबसे बड़ा ख़तरा कांग्रेस को है. उसकी राष्ट्रीय पार्टी की पहचान भी दो अंकों में सिमट गई है. इसलिए कांग्रेस साम, दाम, दंड और भेद किसी भी तरह से भाजपा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सपा और बसपा का साथ चाहती है. वहीं मुलायम और माया राजनीतिक बयार की अनदेखी कर पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े होने के पक्ष में नहीं हैं. उन्हें (मुलायम और माया को) पता है कि उनकी जिस कमज़ोर नब्ज (भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई का डर दिखाना) को पकड़कर कांग्रेस ने अपने लिए समर्थन हासिल किया था. वही ख़तरा भाजपा भी उनके ख़िलाफ़ खड़ा कर सकती है. मुलायम सिंह तो कह भी चुके हैं कि केंद्र सरकार के सौ हाथ होते हैं. यही वजह है नेताजी और बहनजी भाजपा से राजनीतिक संबंध बिगाड़ने के पक्ष में भी नहीं हैं. यही वजह है कि कई बार सपा और बसपा अपनी प्रबल विरोधी भाजपा के सुर में सुर मिलाते दिखाई पड़ रहे हैं.

लोकसभा में तो भाजपा सरकार को सपा और बसपा की ज़रूरत नहीं है,लेकिन राज्यसभा में जब मौक़ा आता है, तो बसपा और सपा को भाजपा सरकार का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं होता है. ट्राई संशोधन बिल का राज्यसभा में समर्थन कर बसपा ने यह जता भी दिया. कांग्रेस के विरोध के बावजूद बसपा ने प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव बनाए जाने के लिए पूर्व आईएएस नृपेन्द्र मिश्रा के पक्ष में लाए गए बिल को समर्थन दे दिया. वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की मुख़ालफ़त कर रही है, लेकिन दिल्ली में उसे भाजपा के साथ खड़े होने में कोई एतराज़ नहीं होता है. ठीक वैसे ही जैसे वह कांग्रेस के केंद्र की सत्ता में रहते किया करती थी. यानी नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है. ट्राई बिल पर सपा द्वारा मोदी सरकार का समर्थन करना यह बताने के लिए काफ़ी है कि सपा नेतृत्व मोदी सरकार में बसपा के नंबर बढ़ने नहीं देना चाहता है. वैसे,अखिलेश सरकार की यह सोच कि केंद्र से बिगाड़ कर न रखी जाए, यह प्रदेश के विकास के लिए भी फ़ायदे का सौदा साबित हो रही है. मोदी सरकार बिना भेदभाव के यूपी सरकार की मदद कर रही है. भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से लेकर लोकसभा तक में भाजपा सांसदों की तरफ से नेताजी मुलायम सिंह को पूरा सम्मान मिल रहा है. यही वजह थी कि लोकसभा में जब बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के हुड़दंग के कारण (तीन मौक़े मिलने के बाद भी) मुलायम अपनी बात नहीं रख पाए, तो उन्होंने तल्ख़ लहज़े में यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को बचाते-बचाते हम हार गए. यह उनके मन का गुबार था,जिसे वह लंबे समय से अपने दिल में दबाए हुए थे. अंत में जब नेताजी को बोलने का मौक़ा मिला, तो उन्होंने कांग्रेस से साफ़ कह दिया कि आप हमारा साथ देगें, तभी हम आपका साथ देगें. इतना ही नहीं, नेताजी के सांसद और भतीजे धर्मेंद्र यादव ने तो

लोकसभा में तो भाजपा सरकार को सपा और बसपा की ज़रूरत नहीं है,लेकिन राज्यसभा में जब मौक़ा आता है, तो बसपा और सपा को भाजपा सरकार का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं होता है. ट्राई संशोधन बिल का राज्यसभा में समर्थन कर बसपा ने यह जता भी दिया. कांग्रेस के विरोध के बावजूद बसपा ने प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव बनाए जाने के लिए पूर्व आईएएस नृपेन्द्र मिश्रा के पक्ष में लाए गए बिल को समर्थन दे दिया.

नाराज़ होकर यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के 44 सदस्य हैं और आगे से कोई बोलकर दिखा दे.

कांग्रेस के प्रति मुलायम का रुख़ तीखा ज़रूर हो गया है, लेकिन वह इस बात का भी ध्यान रखे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी किसी भी दशा में भाजपा के साथ खड़ी नज़र नहीं आएं, इसलिए वह बहस के दौरान कहने से चूके नहीं कि आम बजट के साथ देश में बुरे दिनों की शुरूआत हो गई है. मुलायम का लक्ष्य साफ़ है कि वह भाजपा का साथ देकर मुस्लिम वोटरों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं. वहीं भाजपा का बेतुका विरोध करके इन 5-6 प्रतिशत वोटरों को नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं, जिनकी निष्ठा किसी विशेष पार्टी के साथ जुड़ी नहीं रहती है. उन्हें उम्मीद है कि देर-सबेर भाजपा सरकार की नाक़ामी से क्षुब्ध होकर ऐसे वोटर समाजवादी पार्टी के पाले मे आ सकते हैं. यह वे वोटर हैं, जिन्होंने मोदी की हिंदूवादी छवि को देख कर नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके विकास के दावों को सुनकर वोट किया था और ऐसा न होने पर वह (वोटर) पाला बदलने में देर नहीं करेंगे. सपा प्रमुख जानते हैं कि सिर्फ़ मुस्लिम वोटों के सहारे ज़्यादा लंबे समय तक सियासत नहीं की जा सकती है. ठीक वैसे ही जैसे दलितों के सहारे बहनजी बसपा का बेड़ा पार नहीं कर सकती हैं.

बसपा नेत्री दलित वोट बैंक के चक्कर में यह नहीं देख पाईं कि नई आर्थिक नीति के विस्तार, बाज़ार के फैलाव, उपभोक्तावादी समूह का विकास और रुपये की आवाजाही, जो पिछले एक दशक में बढ़ी थी, उसके चलते यूपी के ग्रामीण इलाक़े में रहे वाले लोग भी सुविधाभोगी हो गए थे. अच्छे जीवन की चाह और क्रय शक्ति बढ़ने का ही नतीजा था कि घर-घर में टीवी और अन्य संचार के माध्यम पहुंच गए और वे ग्रामीण, जो राजनीति से अलग-थलग थे, उसमें रूचि लेने लगे. यह बात मोदी को समझने में देर नहीं लगी. इसी के चलते वह बाज़ी मार ले गए. अब दलित फेसबुक का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं. मीडिया के माध्यम से यह समझने की कोशिश भी करते हैं कि कौन उनका सचमुच भला करना चाहता है. इसके अलावा, माया की हार का एक कारण यह भी रहा कि उन्होंने अपना प्रचार अभियान काफ़ी देर से शुरू किया था, जबकि भाजपा ने शुरू से ही जातीय समीकरण पर पूरा ध्यान दिया था. पटेल,कुर्मी और कुशवाहा जैसी पिछड़ी जातियों के साथ-साथ भाजपा ने भुर्जी,निषाद,तेली और चौरसिया जैसी अति पिछड़ी जातियों के अलावा, अति दलित वोटरों का हिंदूकरण कर बाज़ी मार ली.

इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के फार्मूले का दरक़िनार करके एकला चलो की रणनीति से तौबा करने के मूड में नज़र आ रही है. दो दशक से राज्य में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को अब लगने लगा है कि हताश नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उसे सपा और बसपा में से एक को साधकर चलना ही पड़ेगा. कांग्रेस की ज़मीनी हक़ीक़त इतनी बुरी है कि पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर ने तो सोनिया गांधी तक से गुहार लगा दी है कि वह यूपी में कांग्रेस को पुर्नजीवित करने के लिए मदद करें. माथुर बिहार में लालू और नीतीश कुमार के हाथ मिलाने से काफ़ी प्रभावित दिख रहे हैं, जिन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की आड़ में एक दशक के बाद हाथ मिला लिया है, जबकि सब जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति करियर को लालू के जंगलराज के ख़िलाफ़ धार देकर ही चमकाया था. बसपा के साथ मिलकर कांग्रेस पहले चुनाव लड़ भी चुकी है, लेकिन प्रदीप माथुर बसपा नहीं समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने की वक़ालत कर रहे हैं. उनकी नजरों में कांग्रेस के लिए माया से अधिक मुलायम भरोसे के लायक हैं. माथुर इस सच्चाई को भी जानते हैं कि भले ही समाजवादी पार्टी लोकसभा में पांच सीटों पर सिमट गई हो, लेकिन मुस्लिमों के भरोसे पर सपा आज भी नंबर वन है. लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट थोड़े बिखर गए थे,लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है. मुलसमानों की आंख खुल गई है. वह सपा का ही साथ देगें. माथुर को लगता है कि सपा के मुस्लिम और कांग्रेस के दलित तथा अन्य बिरादरियों के कुछ वोटर एकजुट हो जाएं, तो वर्ष 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकती है.

समाजवादी पार्टी से गठजोड़ को लेकर माथुर इसलिए भी विश्वास में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सपा को भी सत्ता विरोधी लहर के कारण 2017 में हार का डर सताने लगा है. अभी से सपा के कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की सुगबुगाहट सुनाई पड़ने लगी है कि प्रदेश में अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी. बात कांग्रेस आलाकमान की करें, तो उसे सपा से नज़दीकी बढ़ाने में शायद ही कोई गुरेज़ हो. वैसे भी कांग्रेस को लोकसभा में एक विश्वसनीय साथी की दरकार है. कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनाव हार चुके हैं, जो जीत कर आए हैं उनमें इतनी योग्यता नहीं है कि वह मोदी सरकार की घेराबंदी कर पाएं. कांग्रेसी लोकसभा में भाजपा को घेरने में भी पिछड़ रहे हैं. लोकसभा में कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे,कैप्टन अमरिंदर सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे अपनी नैया पार करनी पड़ रही है. यह नेता इतने अनुभवी नहीं हैं, जो सभी मोर्चों पर कांग्रेस का झंडा बुलंद कर सकें. प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेन्द्र मिश्रा के मुद्दे को लेकर जिस तरह कांग्रेस की फ़जीहत हुई, उससे कांग्रेस आलाकमान की नींद हराम हो गई है. कांग्रेस का बसपा और सपा ही नहीं, बल्कि अन्य दलों में से भी किसी ने साथ नहीं दिया. कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता मुलायम के संपर्क में हैं. वहीं कांग्रेस को लगता है कि मुलायम की सांप्रदायिकता से लड़ने वाली कट्टर छवि के सहारे विपक्ष को एकजुट किया जा सकता है. मुलायम को अपने क़रीब रखने के लिए कांग्रेस को इस बात की भी चिंता नहीं है कि बेनी प्रसाद वर्मा जैसे उसके कुछ नेता नाराज़ हो जाएंगे. मरणासन्न कांग्रेस ने तो बस सपा से संजीवनी मिलने की चाहत पाल रखी है.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह तय माना जा रहा है कि 12 विधान सभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजों के बाद यूपी की राजनीति में नए गठजोड़ बनेंगे. समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली क़रारी हार से चिंतित तो है, लेकिन उसे यह भी लगता है कि उपचुनाव के नतीजे सपा के पिचके हुए गुब्बारे में फिर से हवा भर देंगे. वहीं बसपा की हालत और भी पलती हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता यह मान चुका है कि बसपा के सितारे डूब रहे हैं और सपा की डूबती नैया को थोड़ा सहारा देकर पार लगाया जा सकता है, जो सपा ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए भी मुफ़ीद रहेगा. सपा को अगर जीत की राह में कोई रोड़ा नजर आ रहा है, तो वह अमित शाह ही हैं जो अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन कर और भी ताक़तवर हो गए हैं. फ़िलहाल यूपी भाजपा शाह के इशारे पर चल ही रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

बिजली समस्या को लेकर अखिलेश सरकार गंभीर

रवि प्रकाश

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बिजली के मोर्चे पर घिरी रहती है. क़ानून व्यवस्था के बाद यह दूसरा ऐसा मुद्दा है, जिसे विपक्षी खूब हवा देते हैं. जनता से सीधा जुड़ाव होने के कारण बिजली की समस्या के चलते वोट बैंक भी प्रभावित होता है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव से पहले यूपी को बिजली समस्या से पूरी हद तक नहीं तो अधिक से अधिक मुक्त कर दिया जाए. इसी के चलते कई विद्युत परियोजनाओं में सुधार किया जा रहा है. अखिलेश सरकार ने अहम फ़ैसला लेते हुए हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना की संशोधित लागत 3168.36 करोड़ रुपये को मंज़ूरी प्रदान कर दी है. परियोजना की पूर्व अनुमोदित लागत 2956.25 करोड़ रुपये के सापेक्ष बढ़ी अतिरिक्त लागत 212.11 करोड़ रुपये के 30 प्रतिशत समतुल्य अंश–63.63 करोड़ रुपये हेतु अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी. इसी तरह अखिलेश सरकार ने राजकीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधीन पनकी तापीय विस्तार परियोजना 1660 मेगावाट को लगाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत 4712.31 करोड़ रुपये का 80 प्रतिशत संस्थागत वित्तीय संस्थाओं से ऋण द्वारा एवं 20 प्रतिशत शासकीय अंश पूंजी से वित्त पोषित किए जाने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया. 80 प्रतिशत वित्त पोषण हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृत के लिए शुल्क रहित शासकीय गारंटी प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है.

उधर, पारीछा तापीय परियोजना 2210 मेगावाट इकाई के कोयला संचालन तंत्र में एक अतिरिक्त वैगन टिप्लर की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है. इसके पैकेज की वर्तमान अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपये को अनुमोदन प्रदान किया गया है. मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि इस पैकेज के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध एक पृथक योजना बनाकर वित्तीय संस्थान से 80 प्रतिशत वित्त पोषित किया जाएगा एवं शेष 20 प्रतिशत शासकीय अंश पूंजी से प्रदान किया जाएगा. वहीं जनपद इलाहाबाद स्थित मेजा तापीय विद्युत परियोजना के अंतर्गत 2.660 मेगावाट (स्टेज– दो) की 2 अतिरिक्त इकाइयों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति एवं इस परियोजना हेतु फिज़ीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अंशदान 150 लाख रुपये के अग्रिम भुगतान के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है. ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के संयुक्त उपक्रम मेजा ऊर्जा निगम प्रा.लि. के तहत 2660 मेगावाट मेजा तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना इलाहाबाद में की जा रही है. इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है. चूंकि इस परियोजना के तहत 660 मेगावाट की 4 इकाइयों हेतु भूमि उपलब्ध है. अतः 660 मेगावाट की 2 इकाइयों के बजाय 4 इकाइयां स्थापित करने पर प्रति मेगावाट लागत काफ़ी कम हो जाएगी. ■

महिला उत्पीड़न का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा

संदीप कश्यप

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ती आपराधिक घटनाओं से हो रही किरकिरी के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक अहम कदम उठाते हुए महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई ज़ल्द से ज़ल्द कराए जाने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने दो टूक कह दिया है कि ऐसे लंबित मुक़दमों की न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए, ताकि अपराधियों के बीच गंभीरता के साथ यह संदेश जाए कि महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है. ऐसे मामलों के दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. इसके साथ–साथ अखिलेश ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई कर दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने चेतावनी भरे लहज़े में कहा कि इस संबंध में शिथिलता बरतने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर दोहराया है कि यूपी में अपराध की घटनाओं को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में हालात यूपी से कहीं ज्यादा ख़राब हैं. सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी आरोप लगाया है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन और संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान है. किन्तु मर्यादा तोड़कर की गई कोई भी कार्यवाही उचित नहीं ठहराई जा सकती है. इन दिनों उत्तर प्रदेश में कुछ दलों और संगठनों ने समाजवादी सरकार की मुखालफत को अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए जितना संकल्पित हैं. दूसरे दल उनके विकास एजेंडा को विफल करने की साज़िशों में उतने ही सक्रिय हैं. जनता इन चालों को बखूबी समझती है और वह उनका क़रारा जवाब देना भी जानती है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की शालीनता और विनम्रता की प्रशंसा तो विपक्षी नेता भी करते हैं. मुख्यमंत्री अत्यंत संवेदनशील नेता हैं. चाहे बदायूं कांड हो या मोहनलालगंज कांड, मुख्यमंत्री ने घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही की और अधिकारियों को सक्रिय एवं सतर्क किया. पीड़ितों की मदद की और दोषियों को गिरफ़्तार कराया.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की शालीनता और विनम्रता की प्रशंसा तो विपक्षी नेता भी करते हैं. मुख्यमंत्री अत्यंत संवेदनशील नेता हैं. चाहे बदायूं कांड हो या मोहनलालगंज कांड, मुख्यमंत्री ने घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही की और अधिकारियों को सक्रिय एवं सतर्क किया. पीड़ितों की मदद की और दोषियों को गिरफ्तार कराया. मुख्यमंत्री बराबर इस बात पर ज़ोर देते हैं कि दोषियों को किसी हालत में बख्शा न जाए और किसी निर्दोष को व्यर्थ सताया नहीं जाना चाहिए. सपा प्रवक्ता कहते हैं कि विडबंना है कि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और आपराधिक घटनाओं के प्रति उनके कठोर रुख़ के बावजूद राजधानी में कुछ लोग अपने प्रदर्शनों से ऐसा संकेत देते हैं कि जैसे पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत हैं. समाजवादी सरकार ने किसी मामले में कहीं ढिलाई बरती होती तो इन प्रदर्शनों का कोई औचित्य होता, लेकिन ये तो बिना किसी ठोस कारण के विरोध करते हैं.

समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल भी मुलायम से सुर में सुर मिलाते हुए कहते हैं कि प्रदेश में विकास की गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए कुछ सांप्रदायिक तत्व भी इन दिनों फिर सक्रिय हो गए हैं. वे व्यर्थ विवाद पैदा करना चाहते हैं. उन्हें आम जनता की सुख शांति एवं सुरक्षा पसंद नही. विश्व हिन्दू परिषद के एक नेता ने जिन शब्दों में अल्पसंख्यक वर्ग को धमकी दी है, उससे यही लगता है कि वे दूसरा गोधरा रचने की साज़िश में लग गए हैं. अपनी भड़ास निकालते वक्त वे यह भी भूल गए कि यहां क़ानून का राज चलता है. यहां समाज को तोड़ने वाली ताक़तों का कोई भविष्य नहीं है, जो लोग सांप्रदायिक विषवमन कर रहे हैं. वे इस देश की एकता अखंडता और सामाजिक सद्भाव के दुश्मन हैं. उनको जनता ने कभी महत्व नहीं दिया है और न ही उनका कोई भविष्य है. ■

अपनी अलग पहचान बनाएंगे महामहिम

दर्शन शर्मा

राज्यपाल बीएल जोशी के इस्तीफ़ा देने के बाद उत्तर प्रदेश को राम नाइक के रूप में 28 वां राज्यपाल मिल गया है. महाराष्ट्र भाजपा की राजनीति से उभर कर आए राम नाइक अटल बिहारी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. अपनी बढ़ती उम्र की वजह से उन्होंने पिछले वर्ष सक्रिय राजनीति से सन्यास लेने के बाद राज्यपाल का ओहदा संभालने से पूर्व भाजपा में भी सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया था. यूपी राजभवन पहुंचने वाले नाइक तीसरे ऐसे नेता हैं, जो भाजपा की विचारधारा से जुड़े हैं. इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की पिछली सरकार में, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके समय सूरजभान और विष्णुकांत शास्त्री राज्यपाल के रूप में राजभवन की शोभा बढ़ा चुके हैं. सूरजभान 20 अप्रैल 1998 से लेकर 23 नवंबर 2000 तक और विष्णुकांत शास्त्री 24 नवंबर 2000 से 2 जुलाई 2004 तक राज्यपाल रहे थे.

राम नाइक के राजभवन पहुंचते ही उत्तर प्रदेश भाजपा नेताओं में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया है. हालांकि, यह और बात है कि नवनियुक्त राज्यपाल जो भाषा बोल रहे हैं,उसमें राजभवन और अखिलेश सरकार के बीच टकराव का पुट कहीं नहीं दिखता है. भाजपा नेताओं को सबसे पहला झटका तो नाइक ने यह कहकर ही दे दिया कि जौहर विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के पूर्व राज्यपाल कुरैशी के फ़ैसले को वह बदलेंगे नहीं. जब नाइक से कहा गया कि भाजपा नेता तो कह रहे थे कि नए राज्यपाल नाइक इस फ़ैसले को बदल देंगे, तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि जिसे राज्यपाल कुरैशी के फ़ैसले से एतराज़ है, वह अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं. उसी तरह नाइक ने लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के चर्चित कथित गैंगरेप और हत्याकांड मामले में भी कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया, जबकि भाजपा इस हत्याकांड के सहारे समाजवादी सरकार को क़ानून व्यवस्था के मसले पर घेरने का पूरा प्रयास कर रही है. नाइक उत्तर प्रदेश को मुलायम की महत्वाकांक्षा के अनुरूप उत्तम प्रदेश बनाने का भी सपना देख रहे हैं.

राम नाइक ने 22 जुलाई 2014 को शपथ ग्रहण की. उनके शपथ ग्रहण से एक दिन पहले यूपी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. अजीज कुरैशी ने राजभवन से विदाई ली. क़रीब एक महीने तक डॉ. अजीज कुरैशी ने यूपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला. कुरैशी का यह कार्यकाल बेशक छोटा था, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण था. कांग्रेसी विचारधारा के डॉ.अजीज की कार्यशैली पूरी तरह से समाजवादी चोला ओढ़े दिखी. वह कांग्रेस से अधिक समाजवादी सरकार के क़रीब दिखे.

ग़ौरतलब है कि राम नाइक ने 22 जुलाई 2014 को शपथ ग्रहण की. उनके शपथ ग्रहण से एक दिन पहले यूपी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. अजीज कुरैशी ने राजभवन से विदाई ली. क़रीब एक महीने तक डॉ. अजीज कुरैशी ने यूपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला. कुरैशी का यह बेशक कार्यकाल छोटा था, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा. कांग्रेसी विचारधारा के माने जाने वाले डॉ. अजीज कुरैशी की कार्यशैली पूरी तरह से समाजवादी चोला ओढ़े दिखी. वह कांग्रेस से अधिक समाजवादी सरकार के क़रीब दिखे. कांग्रेस की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पूर्व राज्यपालों मसलन, टीवी राजेश्वर और बीएल जोशी ने जो काम पिछले दस वर्षों में नहीं किया उसे कुरैशी साहब ने एक झटके में कर दिखाया. बात आज़म ख़ान की ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की हो या अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसलों की, कुरैशी साहब ने पूरी तत्परता के साथ काम किया. प्रदेश की बिगड़ी क़ानून व्यवस्था को जनता के बीच मुद्दा बनाने को हाथ–पैर मार रही कांग्रेस को यह कहते हुए महामहिम झटका दे गए कि चाहे आर्मी या दुनिया भर की पुलिस लगा दी जाए या फिर भगवान ही धरती पर आ जाएं, उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं पूरी तरह से नहीं रोकी जा सकती हैं. महामहिम कुरैशी का यह बयान क़ानून व्यवस्था को लेकर कठघरे में खड़ी अखिलेश सरकार के लिए वैसा ही साबित हुआ जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो. कुरैशी के बयान से कांग्रेसी अवाक रह गए, वहीं भाजपा के नीचे से भी ज़मीन खिसक गई. जौहर विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिए जाने के बाद डॉ. करैशी का यह दूसरा कदम था, जिससे भाजपा हिल गई. रेप के मसले पर महामहिम के बयान की हवा निकालने के लिए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आगे आना पड़ा और उन्होंने राज्यपाल कुरैशी को बर्ख़ास्त करने की मांग कर डाली.

क़रीब एक महीने तक यूपी का कार्यभार संभालने के बाद कुरैशी तो उत्तराखंड वापस चले गए हैं, लेकिन भाजपा में इस बात का मंथन ज़रूर होने लगा है कि किस भाजपा नेता के इशारे पर कुरैशी को यूपी का भार सौंपा गया था. प्रदेश भाजपा नेता इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सामने भी रखेंगे, ताकि भविष्य में इस नेता के चलते भाजपा को राजनीतिक नुक़सान नहीं उठाना पड़े. जिस बिगड़ी क़ानून व्यवस्था को भाजपा लगातार अखिलेश सरकार के ख़िलाफ़ हथियार बना रही थी, उसकी हवा कुरैशी ने पूरी तरह निकाल कर रख दी. ऐसा नहीं है कि कुरैशी को यूपी का राज्यपाल बनाए जाने से भाजपा के लिए सब कुछ बुरा ही हुआ हो. राज्यपाल कुरैशी ने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र सरकारी कार्यालयों मे लगाए जाने फरमान सुनाया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किए गए विश्वास की बात भी बार–बार दोहराते हुए कहा कि वह विश्वास टूटने नहीं देंगे. बहरहाल, यूपी में डॉ. अजीज कुरैशी का अध्याय बंद और राम नाइक का शुरू हो गया है. नाइक अब भले ही अपने आप को किसी पार्टी विशेष के साथ जोड़ कर नहीं देखना चाहते हों, लेकिन भाजपा और संघ ऐसा नहीं चाहेगा. ऐसे में राम नाइक के सामने कई चुनौतियां आएंगी. एक तरफ़ उन्हें संविधान की रक्षा करनी होगी, वहीं भाजपा के प्रति उन्हें कुछ न कुछ सॉफ्ट कार्नर लेकर चलना होगा. ख़ैर यह समय ही बताएगा कि भविष्य में राज्यपाल राम नाइक का कौन का रूप जनता को देखने को मिलेगा. ■

नौकरशाहों में दिल्ली जाने की होड़ मची है

संजय सक्सेना

एक समय था, जब भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)में यूपी कैडर पाना तमाम नौकरशाहों की हसरत हुआ करती थी. यहां काम करके वह अपने आप को धन्य समझते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीति की चाल इतनी बेढंगी हो गई है कि अब नौकरशाहों को यूपी में काम करना ज़रा भी रास नहीं आता है. आज की तारीख़ में नौकरशाहों को केंद्र की सेवाएं काफ़ी रास आ रही हैं. यही वजह है यूपी के डेढ़ दर्जन नौकरशाहों (प्रमुख सचिव,सचिव और आयुक्तों) के बीच केंद्र सरकार में जगह बनाने की होड़ मची हुई है. दिल्ली में मोदी सरकार के गठन के बाद यह दौड़ और भी तेज़ हो गई है. हालांकि, यूपी छोड़कर जाने को बेताब नौकरशाह खुलकर तो नहीं कहते हैं, लेकिन ऑफ द रिकार्ड वह यह बताने में ज़रा भी संकोच नहीं करते हैं कि यूपी में अब हालात इज्जत से काम करने लायक नहीं रह गए हैं. ब्यूरोक्रेट्स पर दबाव रहता है कि वह राजनेताओं को खुश करें और जब कोई मामला फंसता है, तो नौकरशाहों की गर्दन नाप दी जाती है. नेता बचकर निकल जाते हैं. नौकरशाहों की मानें तो, एक समय था जब राजनेता अपनी बात पर अडिग रहते थे. नेता जो लिखित आदेश देते थे, उससे मुकरने का सवाल ही नहीं होता था. इसके अलावा, पुराने समय के नेता मौखिक आदेश को भी लिखित आदेश की तरह अहमियत देकर अपने ऊपर सारी अच्छाई–बुराई ओढ़ लेते थे. आज के दौर के नेता लिखित आदेश देने से कतराते हैं और मौखिक आदेश पर अपने आप को फंसता देख सब कुछ भूल जाते हैं. यही वजह है कि मंत्रियों और नेताओं के अनाप–शनाप आदेशों को मानते–मानते कई नौकरशाह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, तो कुछ जाने वाले हैं. जबकि नेताओं का बाल बांका नहीं होता है. नौकरशाहों से जब पूछा गया कि राजनेताओं के सही–ग़लत सभी फ़ैसले मानना उनकी मजबूरी नहीं है ? तो आईएएस अधिकारियों का कहना था, जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता है. इसलिए हैरान–परेशान नौकरशाह दिल्ली की राह पकड़ रहे हैं.

केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आया है. नौकरशाहों को लगता है कि मोदी सरकार में उनके लिए ईमानदारी से काम करने की ज़्यादा संभावनाएं हैं. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने को बेताब अफसरों की सूची में वर्ष 1984 बैच के आईएएस कुमार अरविंद सिंह देव से लेकर राहुल भटनागर तक हैं. कुमार जहां प्रमुख सचिव परिवहन की कुर्सी संभाले हैं, वहीं भटनागर प्रमुख सचिव वित्त हैं. प्रमुख सचिव कर एवं निबंधन बीरेश कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन अनंत कुमार सिंह के साथ ही हाल ही में परिवहन आयुक्त के पद से हटाए गए रजनीश गुप्ता भी दिल्ली जाने की तैयारी में हैं. आईएएस नीतिश्वर कुमार, समीर वर्मा, एनजी रवि, राकेश गर्ग, प्रवीण

कुमार, बीएल मीणा, अनामिका सिंह, राजेश कुमार रविंद्र कुमार संयुक्ता समद में से भी कुछ दिल्ली पहुंच गए हैं, तो कई नौकरशाहों को दिल्ली से बुलावे का इंतज़ार है. वाणिज्य कर आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, परिवहन निगम के एमडी मुकेश मेश्राम,पर्यटन सचिव अमृत अभिजात, व्यवसायिक शिक्षा एवं खेल सचिव भुवनेश कुमार, आशीष कुमार गोले, संजय प्रसाद, संतोष कुमार यादव का भी यूपी से मन भर गया है. इसी प्रकार समग्र ग्राम विकास के प्रमुख सचिव और मायावती सरकार में पंचम तल पर तैनात रहे एसपी गोयल भी शीघ्र ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रवाना होने वाले हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पद पर नियुक्ति के लिए भी नौकरशाहों में दौड़ तेज़ हो गई है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दो प्रमुख सचिवों में से एक राकेश गर्ग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने के बाद उनकी जगह की भरपाई करने के लिए पंचम तल पर गहन मंथन चल रहा है. राकेश की जगह सीएम के प्रमुख सचिव बनने की दौड़ में प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव परिवहन कुमार अरविंद सिंह देव और प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार का नाम सबसे आगे है. पंचम तल पर मौजूद आईएएस अनीता सिंह भी प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं.

आईएएस की तरह ही आईपीएस बीके सिंह,आलोक कुमार,दलजीत चौधरी,जी के गोस्वामी का भी अब उत्तर प्रदेश में मन नहीं लग रहा है. क़रीब 80 आईएएस और आईपीएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जा चुके हैं और डेढ़ दर्जन के क़रीब जाने को तैयार बैठे हैं. एक तरफ़ तो उत्तर प्रदेश शासन के डेढ दर्जन से ज़्यादा आईएएस और पीसीएम अधिकारी आगे की सेवा के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को बेताब हैं, तो सिक्के के दूसरे पहलू पर ग़ौर करें, तो पता चलता है कि अखिलेश सरकार भी इस भगदड़ से हैरान हैं. इसलिए कुछ काम के अधिकारियों को प्रदेश सरकार नहीं छोड़ रही है, तो कुछ अधिकारियों का केंद्र सरकार से बुलावा नहीं आ रहा है.

ऐसे में सवाल उठता है कि 592 सदस्यीय यूपी काडर के इतने सारे अफसर आख़िर क्यों केंद्र जाने का मन बना रहे हैं? क्या सिर्फ़ यूपी में ब्यूरोक्रेसी के लिए काम के हालात बेहतर नहीं होना, इसकी वजह है या इसके पीछे और कोई कारण है. यह विषय भी सोचने का है. दरअसल, जो आईएएस और आईपीएस अफसर दिल्ली जाना चाहते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं, जो माया सरकार में उनकी नाक का बाल हुआ करते थे, लेकिन इस सरकार ने उन्हें कोने में डाल दिया है. माया के ख़ास आईएएस अधिकारी नेतराम और विजय शंकर पांडेय अखिलेश राज में अपनी अनदेखी से काफ़ी दुखी हैं.

अखिलेश राज में जो अधिकारी दिल्ली जाने को बेताब हो रहे हैं, उसमें से कुछ अफसर ऐसे हैं, जो सपा राज में शुरू–शुरू में खूब चमके थे, लेकिन जब सरकार पर आलोचनाओं के तीर चले तो सरकार के रणनीतिकारों ने इन अधिकारियों को ढाल की तरह आगे करके अपनी गर्दन बचा ली. इससे नौकरशाही में ग़लत संदेश गया. उत्तर कुछ आईएएस अफसर ऐसे भी हैं, जिन्हें पहले ही इस बात का अहसास हो गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सत्ता में आएंगे. यह अहसास होते ही इन अधिकारियों ने भाजपा नेताओं के माध्यम से दिल्ली में अपनी गोटियां बैठाना शुरू कर दी थी. अखिलेश सरकार के कामकाज से नाराज़ चल रहे इन अफसरों को भले ही लखनऊ से अधिक दिल्ली पसंद आ रहा हो, लेकिन मोदी सरकार की तरफ़ से क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण दिल्ली जाने की उनकी मुराद पूरी नहीं हो रही है. अपनी मुरादें पूरी करने के लिए कई अधिकारी तो छुट्टी पर चले गए हैं, ताकि वह दिल्ली में अपनी सेटिंग कर सकें. हालांकि, इसका नुक़सान अखिलेश सरकार को उठाना पड़ रहा है. अफसरों की कमी के कारण सरकार का काम प्रभावित हो रहा है.

ख़ैर, इस सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि अफसरों की इस दयनीय स्थिति के लिए अधिकारी ही ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं. आज के दौर में यह चलन सा हो गया है कि सभी अधिकारी सत्तारूढ़ दल की नज़दीकी हासिल करना चाहते है. इसके लिए कुछ भी कर गुजरने में उन्हें परहेज़ नहीं रहता है. इन अधिकारियों को सत्ता की नज़दीकी हासिल हो जाए तो पार्टी के प्रति यह दलीय नेताओं से भी ज़्यादा वफ़ादार बनकर कार्यकर्ता की तरह काम करने लगते हैं. मुरादाबाद के एसएसपी को ही ले लीजिए. वह सपा सरकार के प्रति अपनी वफ़ादारी निभाने में यहां तक कहने से नहीं चूके कि मुरादाबाद में भाजपा नेता सांप्रदायिकता फैला रहे हैं. इसी तरह की बयानबाज़ी कई अधिकारियों ने मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भी की थी. चापलूस किस्म के आईएएस अधिकारियों के कारण ही ईमानदार नौकरशाहों की अनदेखी हो रही है.

बात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की करें, तो उनकी लिस्ट में कोई आईएएस वफ़ादार है नहीं है. युवा सीएम सिर्फ़ और सिर्फ़ पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता मुलायम सिंह यादव के वफ़ादार आईएएस अधिकारियों से ही अपना काम चला रहे हैं. इन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि कौन अधिकारी दागी है और कौन नकारा. आईएएस राकेश बहादुर सिंह ने मुलायम राज में नोएडा प्लॉट घोटाले में काफ़ी बदनामी झेली थी. कोर्ट तक से उन्हें फटकार लगी, लेकिन अखिलेश ने उन्हें महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी देने से गुरेज़ नहीं किया. कारण राकेश सपा प्रमुख मुलायम की गुडलिस्ट में हैं. इसी तरह मुलायम के क़रीबी राजीव कुमार प्रमुख सचिव नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण पद पर क़ाबिज हैं. दरअसल, मुलायम सिंह यादव की कृपा से ही उन्हें यह पद मिला हुआ है, जबकि सीबीआई की जांच उनके ख़िलाफ़ भी चल रही है. ■

क़ानून-व्यवस्था के मोर्चे पर अखिलेश सरकार नाकाम

दर्शन शर्मा

कहते हैं जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत में आई बसपा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी थी, और जनता ने उसे रसातल में पहुंचा दिया. ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो को किसी कांशीराम जैसे राजनीतिक गुरु की फिर आवश्यकता आ पड़ी है. लेकिन बसपा प्रमुख मायावती को ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा है. अब सत्ता सुख ले रही सपा के सामने भी बसपा सरकार की भ्रष्टाचार जैसी समस्या बनी क़ानून व्यवस्था सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी है. लोकसभा चुनाव में सिमटी सपा सहम-सहम कर चल रही है. विरोधी दल लगातार हमलावर हैं. सपा के तरकश के सारे शक्तिशाली तीर चुक गए हैं. संसद में मुलायम सिंह अकेले लड़ रहे हैं. वह अपने को बचाएं या उत्तर प्रदेश में आकर अपने बेटे की सरकार बचाएं, यह उनके लिए एक बड़ा प्रश्न है. सरकार में शामिल मंत्री भी कानून-व्यवस्था की बुरी हालत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हैं. सबके अपने अपने बयान हैं. दिल दहलाने वाली घटनाएं यूपी के गांवों से लेकर शहरों तक में आए दिन घट रही हैं. महिलाएं घर से निकलने में डरने लगी हैं. यहां तक कि लड़कियों का स्कूल जाना भी दूभर हो गया है. वे सुबह निकलती हैं, तो शाम को आने तक उनकी घर वाले बाट जोहते हैं. बेटियों को बचाने में सरकार खुद बेदम दिख रही है. अदब के शहर लखनऊ में भी अब महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है. फिर भी सपा सुप्रीमो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं कि यूपी में क़ानून व्यवस्था ठीक नहीं है. वे ऑल इज वेल कह रहे हैं, लेकिन विरोधी दल के लोग प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कभी विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो कहीं मुलायम सिंह के अटपटे बयानों को लेकर उनकी बुद्धि-शुद्धि के लिए भाजपा की महिला कार्यकर्ता हवन करते देखे जा रहे हैं.

सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार और जनता के ख़िलाफ़ सुनियोजित दुष्प्रचार किया जा रहा है, जहां क़ानून व्यवस्था को लेकर भाजपा भ्रामक प्रचार कर रही है, वहीं सत्ताच्युत बसपा खीझ मिटा रही है. सपा सरकार को बर्ख़ास्त करना सिर्फ़ उनका रटा रटाया सूत्र है. भाजपा तो लोकसभा चुनाव की जीत के मद में चूर है, वहीं कांग्रेस को कुछ समझ में नही आ रहा है. वह भी भाजपा और बसपा के साथ-साथ चलती दिख रही है. वे कहते हैं कि सपा सुप्रीमो के बयानों को ग़लत ढंग से प्रचारित किया गया हैं. उनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर विवेकशील और संतुलित विचार रखने वाले जननेता के रूप में शुमार होता है. वे महिलाओं को सम्मान देते हैं. दुष्कर्म की शिकार महिलाओं को त्वरित न्याय मिले इसके वह पक्षधर हैं. उनके किसी बयान का आशय कदापि न तो किसी अपराध को कमतर बताना है और न ही नारी जगत के प्रति अवमानना दिखाना है. 20 करोड़ वाले सूबे में सपा सरकार को जनता ने विशाल बहुमत देकर सत्ता सौंपी है. सरकार प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगी है. किसानों, नौजवानों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के कल्याण के सारे प्रयास हो रहे हैं. कुछ तत्व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर प्रशासन के लिए चुनौती बने हैं. मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना है, क्योंकि विकास की गतिविधियां तभी सफल होंगी, जब शासन-प्रशासन चुस्त-दुरुस्त रहेगा. अपराधियों पर सरकार सख्त है. सरकार के अनुसार, उनकी जगह जेल में है. मुख्यमंत्री आपराधिक वारदातों को स्वयं संज्ञान में ले रहे हैं. जनता जागरूक है और साज़िशकर्ताओं के मंसूबों को परखती है, जो सरकार को बदनाम करने पर उतारू हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. निर्मल खत्री कहते हैं कि प्रदेश में बढ़ते बलात्कार चिंता का विषय है. उनके अनुसार, मुलायम सिंह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश में जुर्म कम हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मनोनीत महामहिम राज्यपाल अजीज कुरैशी का यह कहना कि उत्तर प्रदेश में चाहे भगवान उतर आए तो भी रेप नहीं रोक सकते.

सियासी जानकारों की मानें, तो मायावती के शासन में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं की काफ़ी आलोचना किया करते थे. इसी कारण जब 2012 में सपा सत्तारूढ़ हुई, तो लोगों को हालात में कुछ सुधार की आशा बंधी थी, परंतु सपा के सत्ता में आने के बाद ऐसे हालात पर काबू नहीं पाया जा सका है. सपा के विरोधी कहते हैं कि प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है. लूटपाट, डकैती तथा महिलाओं के विरूद्ध अपराध ज़ोरों पर है. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 2012 के मुक़ाबले 2013 में बलात्कार के मामलों में 55 प्रतिशत वृद्धि हुई है. 2012 में जहां बलात्कार के 1936 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं 2013 में ऐसे मामले बढ़कर 3050 हो गए. देश में महिलाओं की कुल जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है. राज्य में 2013 में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के कुल 32546 मामले दर्ज किए गए थे, जो देश में महिलाओं के विरूद्ध कुल अपराधों का 10.6 प्रतिशत है. वर्ष 2013 के दौरान पूरे देश में बलात्कार के 33 हजार 707 मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए. शायद इन्हीं आंकड़ों को देखकर सपा प्रमुख को गुस्सा आता है कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में घटनाएं कम हो रही है, लेकिन विरोधी दल हैं कि मानते नहीं. विरोधियों के कुप्रचार से सपा सुप्रीमो इन दिनों तिलमिलाए हुए हैं. प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की घटनाओं को काबू में करने के लिए सपा सरकार प्रयासरत है. प्रदेश के मुख्य सचिव खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं. वे ज़िले -ज़िले जाकर डीएम और एसपी से इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं.

भाजपा, बसपा और कांग्रेस के पास एक अस्त्र ही सरकार के ख़िलाफ़ काम कर रहा है. वह है प्रदेश की बिगड़ी क़ानून व्यवस्था. विपक्षी पार्टियां मुलायम सिंह के बयानों को भी मुद्दा बनाते हैं. 10 अप्रैल 2014 को मुलायम ने कहा था कि लड़के तो लड़के हैं, ग़लती हो जाती है. लड़कियां पहले दोस्ती करती हैं और जब मतभेद हो जाता है और दोस्ती टूट जाती है, तब लड़कियां उसे रेप का नाम दे देती हैं. लड़कों से ग़लती हो जाती है, तो क्या उन्हें रेप केस में फांसी पर चढ़ा देंगे. 19 जुलाई 2014 में अखिलेश सरकार का पक्ष लेते हुए उन्होंने बयान दे डाला कि प्रदेश की जनसंख्या 21 करोड़ है, परंतु यहां बलात्कारों की संख्या सबसे कम है.

वहीं इस मामले में भाजपा नेता निरंजन ज्योति का कहना है कि उत्तर प्रदेश की क़ानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है. चोरी, बलात्कार और हत्या के मामले बढ़ रहे है. उन्होंने सरकार पर पुलिस और अपराधियों के बीच सांठ-गांठ का आरोप लगाया है.

लब्बोलुआब यह है उत्तर प्रदेश राजनीति का बड़ा अखाड़ा है. राजनीति की हर विधा यहां उपलब्ध है. साम,दाम,दंड और भेद की नीति में भी निपुण हैं यहां के राजनेता. सभी कांटे से कांटा निकालने में इन्हीं नीतियों का सहारा लेते रहे हैं. तिल का ताड़ बनाने में हर कोई माहिर है. सपा सरकार की एक छोटी सी भूल को भी तूल देने में वह पीछे नहीं हैं. विरोधी क़ानून-व्यवस्था का ब्रह्मस्त्र सपा पर फेंक देते हैं. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जैसे बसपा भ्रष्टाचार पर हारी थी, ठीक उसी तर्ज पर सपा को बिगड़ी क़ानून व्यवस्था पर परास्त करने की भाजपा और दूसरे दल रणनीति बना रहे हैं. सपा चक्रव्यूह में फंसती जा रही है. अगर सरकार समय रहते नहीं चेती तो उसके सामने विरोधी बड़ा चक्रव्यूह बनाकर खड़ा कर सकते हैं. एक जमाने में जब किसी के पास मोबाइल नहीं था, तब सिर्फ़ पुलिस में ही वायरलेस होता था. आज हर हाथ में वायरलेस है. ऐसी स्थिति में अच्छी क़ानून व्यवस्था क़ायम रख पाना सरकार के बूते के बाहर है. अब इसकी रणनीति बदलनी चाहिए. अगर अपराधी डाल-डाल रहे, तो पुलिस को पात-पात दिखना चाहिए. थानों में बेहिचक एफआईआर दर्ज हों, नंबरों का खेल खत्म हो, हर एफआईआर पर त्वरित कार्रवाई हो. जिससे अपराधी दब सकें. पुरानी व्यवस्था हटाकर आधुनिक प्रणाली हर थाने में लागू हो. इसके लिए प्रबुद्ध नौजवानों की आवश्यकता है, जो हर मोर्चे पर हाइटेक अपराधियों से निपटने में सक्षम हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

> यह दर्दनाक हादसा सुनते ही जनता का गुस्सा सांतवें आसमान पर चढ़ गया, तो तमाम दलों के नेताओं ने समाजवादी सरकार को कोसना शुरू कर दिया. नवनियुक्त राज्यपाल राम नाइक ने अफ़सोस जताते हुए माना कि यूपी में क़ानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या है और उसके सुधार पर वह ध्यान देंगे. उधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गुनहगारों की ज़ल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की घोषणा तुरंत ही कर दी.

सीबीआई यानी हर मर्ज़ की दवा

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की सभी जांच और खुफिया एजेंसियों पर विश्वसनीयता का संकट मंडरा रहा है. बात चाहे राजनेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात हो या फिर केंद्र एवं राज्य सरकार की तमाम योजनाओं में बंदरबांट का मसला. राज्य सरकार के मातहत काम करने वाली जांच एजेंसियां भारी दबाव के कारण अधिकांश मामलों में निष्पक्ष तरीक़े से अपने काम को अंज़ाम तक नहीं पहुंचा पाती हैं. राज्य स्तर की एजेंसियों की यह कमज़ोरी देश की करोड़ों की आबादी वाली जनता के लिए अभिशाप बन गई है. उन्हें इस बात का दर्द हमेशा सताता रहता है कि प्रति वर्ष करोड़ों रुपये ख़र्च करने के बाद भी उनके नतीजे शून्य रहते हैं. एक समय था, जब पुलिस की जांच से कोई संतुष्ट नहीं होता था, तो सीआईडी जांच की मांग करता था, लेकिन धीरे-धीरे सीआईडी ने अपनी साख खो दी और अब तो यह कहा जाने लगा है कि सीआईडी के पास जांच जाने का मतलब अपराधी का बेख़ौफ़ हो जाना. इसलिए तमाम भ्रष्ट नेता और नौकरशाह जब फंसते हैं, तो सीआईडी जांच उन्हें काफ़ी रास आती है. यहां वर्षों तक जांच चलती है और कोई नतीजा नहीं निकलता है. वैसे उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त एनके महरोत्रा को इसका श्रेय ज़रूर दिया जा सकता है, जिन्होंने तमाम दबावों के बाद भी कई भ्रष्ट राजनेताओं को जेल की हवा खाने को मजबूर कर दिया.

यूपी के भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की लंबी-चौड़ी लिस्ट मौजूद है, जिनका तब तक बाल भी बांका नहीं हो पाया. जब तक उनके काले-कारनामों को उजागर करने का जिम्मा सीबीआई को नहीं सौंपा गया. एनआएचएम, मनरेगा, मिड-डे मील,नोएडा प्लाट, आय से अधिक संपत्ति आदि तमाम घोटालों में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, मुलायम सिंह यादव और मंत्रियों में नसीमुद्दीन सिद्दिकी, बादशाह सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा,रामवीर उपाध्याय आदि तो नौकरशाहों में नीरा यादव, अखंड प्रताप सिंह, प्रदीप शुक्ला आदि दर्जन भर नौकरशाहों पर सिर्फ़ सीबीआई के चलते ही शिकंजा कसा जा सका.

पूर्व नौकरशाह नीरा यादव को 1997 में आईएएस एसोसिएशन ने भ्रष्टतम आईएएस चुना था. वह पहली मुख्य सचिव थीं,जिन्हें 2005 में कोर्ट ने मुख्य सचिव के पद से हटाने को कहा था. फ्लैक्स घोटाले में 4 साल और नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले में तीन साल की सज़ा उन्हें सुनाई गई. नीरा यादव के कारनामों की जांच सीबीआई ने की थी. इसी प्रकार एक और भ्रष्ट नौकरशाह अखंड प्रताप सिंह का भी नाम आईएएस एसोसिऐशन की भ्रष्ट अधिकारियों की सूची में शुमार था. आय से अधिक संपत्ति के मामले में वह जेल जा चुके हैं. मुख्य सचिव रहते अखंड पर बीज घोटाले के भी आरोप लगे थे. 1981 बैच के आईएएस टॉपर यूपी के प्रदीप शुक्ला

एनआरएचएम घोटाले के मुख्य आरोपियों में हैं. उन्हें निलंबित भी किया था. सीबीआई मामले की जांच कर रही है. जेल जाने के बाद इस समय वह जमानत पर बाहर हैं. 1971 बैच के आईएएस बजलीत सिंह लाली पर प्रसार भारती के सीईओ रहते भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. मामले की सीबीआई जांच भी हुई. अदालत ने नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले में आईएएस राजीव कुमार को भी तीन साल की सज़ा सुनाई थी. हाईकोर्ट के आदेश से सज़ा स्थगित चल रही हैं. अखिलेश का विश्वासपात्र होने के कारण इस समय उनके पास नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव का महत्वपूर्ण पद है. 1983 बैच के आईएएस संजीव शरण पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रहते होटलों के लिए ज़मीन आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है. हाईकोर्ट ने उनके पश्चिमी यूपी में तैनाती पर रोक लगा रखी है. इसी प्रकार आईएएस राकेश बहादुर पर भी हज़ारों करोड़ के नोएडा ज़मीन घोटाले में आरोप लगे थे. मायावती सरकार ने राकेश को निलंबित कर दिया था. नोएडा का चेयरमैन बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराज़गी भी व्यक्त की थी. अखिलेश सरकार में राकेश का भी ओहदा बढ़ा है और वह प्रमुख सचिव गृह हैं. उसी तरह आईएएस महेश गुप्ता को सूचना विभाग में भर्ती घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट किया था. आईएएस सदाकांत,ललित वर्मा, के धनलक्ष्मी के खिलाफ भी सीबीआई की जांच चल रही है.

बात आपराधिक वारदातों की करें, तो राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या और कथित गैंगरेप की बात हो या फिर बदांयू में दो बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला सभी मामलों में पीड़ित पक्ष पुलिस की थ्योरी से इत्तेफाक़ नहीं रखने के चलते सीआईडी की बजाय सीबीआई जांच की मांग पर ज़ोर दे रहे हैं. बदांयू कांड की जांच तो सीबीआई ने शुरू भी कर दी है, लेकिन लखनऊ के मोहनलालगंज में एक महिला के साथ कथित बलात्कार और हत्या का मामला तमाम विरोधाभास के बाद भी सीबीआई को सुपुर्द नहीं किया गया है. मोहनलालगंज में महिला के साथ हुई वारदात में पुलिसिया खुलासे से असंतुष्ट लोग इस कांड की जांच भी सीबीआई से कराने को कह रहे हैं. सीबीआई की जांच के नतीजों का प्रतिशत सच के काफ़ी क़रीब होता है. चाहे आरुषि मर्डर मिस्ट्री हो या फिर मधुमिता हत्याकांड अथवा डीएसपी जियाउल हक़ केस तमाम बार यूपी पुलिस के दावे से उलट सीबीआई ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है.

नोएडा के आरुषि हत्याकांड की ही बात करें, तो यह साफ हो जाता है कि किस तरह यूपी पुलिस ने कुछ घरेलू नौकरों पर सारे अपराध का ठीकरा फोड़ दिया था. यह साफ़ लग रहा था कि पुलिस दबाव में काम कर रही है. जांच अधिकारियों की मंशा पर भी सवाल उठने लगे थे, लेकिन जब मामला सीबीआई को सुपुर्द किया गया, तो यह बात आइने की तरह साफ़ हो गई कि इस मामले में आरुषि के पिता डॉ राजेश तलवार के रसूख को देखते हुए उन्हें बचाने के लिए सारा ठीकरा नौकरों के सिर फोड़ दिया गया था. सीबीआई की जांच के बाद राजेश तलवार और उनकी पत्नी को सज़ा हो गई है और वह जेल में हैं. अपने समय के चर्चित कवियत्री मधुमिता हत्याकांड में पुलिस ने हत्या के आरोपी तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को बचाने की जी तोड़ कोशिश की. पहले मधुमिता और एक अन्य युवक के रिश्तों की कहानी गढ़ी गई. बाद में रंजिश का मामला लाया गया. मामला सीबीआई के पास गया और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी तथा उनकी पत्नी सहित कई लोगों को जेल जाना पड़ा. अमरमणि उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. बदायूं में नरैनी से बसपा विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के घर में काम करने वाली युवती के साथ सामूहिक दुराचार के मामले में विधायक को बचाने के लिए पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी. पुलिस ने पीड़ित युवती को ही चोर बता कर उसे जेल भेज दिया था. कानपुर में कक्षा दस की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस आरोपियों को बचाने की लिए शर्मनाक स्तर तक चली गई. पुलिस ने मासूम के चरित्र पर ही अंगुली उठा दी थी. इसके लिए महिला डॉक्टर से झूठा बयान भी दिलाया गया. कुंडा में सीओ जियाउल हक़ की हत्या के मामले में भी पुलिस की भूमिका शर्मनाक रही. सीओ को मौक़े पर छोड़कर भाग निकले पुलिसकर्मियों को बचाने की भरसक कोशिश होती रही. बाद में पुलिस ने माना कि सीओ को उनके साथियों ने अकेला छोड़ दिया था. उसी तरह बुलंदशहर में एक नाबालिग से दुराचार के मामले में पुलिस ने पीड़ित को ही हवालात में बंद कर दिया और उसके परिवार के लोगों पर मुकदमा दर्ज न कराने का दबाव बनाया. बिजनौर के अफजलगढ़ थाने में दुष्कर्म पीड़िता की मदद करने की बजाय पुलिस ने उसे ही पीट दिया. आरोपियों से मिलीभगत कर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और पीड़ित महिला से मुक़दमा वापस लेने का दबाव बनाया. मना करने पर उसके केस को ही झूठा करार देने की कोशिश शुरू कर दी.

इसी तरह के तमाम उदाहरण हैं, जब यूपी पुलिस ने सनसनीखेज मामलों में फर्जी खुलासा करने की कोशिश की या फिर पीड़ित पर ही तोहमत जड़ दी. ऐसे मामलों में सामने आया कि पुलिस ने किसी न किसी रसूखदार को बचाने के लिए उसके जघन्य अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश की थी. पुलिस की ये कोशिशें पहुंच वालों की जी हुजूरी में और अपनी कुर्सी बचाने के प्रयासों में रही. हालांकि पुलिस को मुंह की खानी पड़ी. मोहनलालगंज मामले में भी पुलिस की स्किप्ट पर सवाल उठ रहे हैं, तो उसके पीछे सवालों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ में दोहराया गया निर्भया कांड

संजय सक्सेना

क़ानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी सरकार पर कई कलंक लग चुके हैं. बात चाहे मुलायम सरकार की हो या फिर मौजूदा अखिलेश सरकार की, समाजवादी राज में अपराधियों के हौसले काफ़ी बुलंद हो जाते हैं. भले ही आंकड़ों की बाज़ीगरी करके समाजवादी नेता यूपी में अपराध कम होने का ढिंढोरा पीटते रहते हों, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है यूपी में न केवल छोटे-छोटे अपराध बढ़ रहे हैं, बल्कि महिलाओं की आबरू भी यहां महफूज़ नहीं रह गई है. सूबे में कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, जब अख़बारों के पन्ने बलात्कार की घटनाओं से रंगे न रहते हों. महिलाओं की आबरू के लुटेरे न तो दुधमुंही बच्ची को छोड़ रहे हैं और न ही 70 साल की वृद्ध महिला को. वजह साफ़ है कि राज्य में वहशियों को क़ानून का डर दूर-दूर तक नहीं दिखाई देता है. सपा के विरोधी अक्सर आरोप लगाते रहते हैं कि सपा गुंडों और बदमाशों की पार्टी है. यह बात अगर सही नहीं है, तो इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता है. सपा शासन में पुलिस समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पर कदम ताल करती है. राज्य में अपराध का ग्राफ जितना भी बढ़े, पुलिस के छोटे-बड़े अधिकारियों पर इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है. ख़ाकी वर्दी वालों को पता है कि उनके ऊपर जब तक खादी का हाथ रहेगा कोई उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता है. इसी तरह की सोच क़ानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले दबंगों की भी है,जिसके चलते क़ानून के रखवाले अपनी ज़िम्मेदारी गंभीरता से नहीं निभाते हैं. यही वजह है कि अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं.

हालात यह है कि उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों यहां तक कि राजधानी लखनऊ तक में लड़कियों को अब अपने घर से निकलने में डर लगने लगा है. इसे अफ़सोसजनक ही कहा जाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली में दो वर्ष पूर्व हुए निर्भया कांड के बाद बलात्कार के क़ानून में किए गए बदलाव का भी असर नहीं दिखाई दे रहा है. अगर ऐसा न होता तो यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवती के साथ उसी इलाक़े में दुस्साहसिक कांड न होता, जहां से कुछ दूरी पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को चंद घंटों के बाद आना था. लोग उस समय हैरान रह गए, जब उन्हें पता चला कि जिस समय लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आगमन को लेकर पुलिस के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद होने का दावा कर रहे थे, ठीक उसी समय इस थाना क्षेत्र में चंद कदम की दूरी पर बलसिंह खेड़ा गांव के बाहर स्थित प्राथमिक विद्यालय में 25 वर्षीय युवती का निर्वस्त्र शव पड़ा मिला. युवती के साथ पहले सामूहिक बलात्कार हुआ. उसके बाद उसे डंडों से पीटा और नाजुक अंगों को बुरी तरह से चोट पहुंचाई गई. रातभर तड़पने के बाद युवती ने दम तोड़ दिया. स्कूल परिसर में झाड़ियों से लेकर सीमेंट की बैंच,हैंडपंप और चबूतरे तक करीब 50 मीटर के दायरे में खून ही खून फैला हुआ था,जिससे लग रहा था मौत से पहले युवती ज़िंदगी के लिए काफ़ी तड़पी होगी. युवती ने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे और पढ़ी-लिखी लग रही थी. 17 जुलाई की सुबह स्कूल के एक शिक्षामित्र ने सबसे पहले पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस तमाम पहलुओं पर ग़ौर कर रही है. कोई कहता है कि युवती का शव और घटनास्थल के चश्मदीद जो कुछ बता रहे हैं, उसके मुताबिक़ तो ऐसा घिनौना कृत्य करने में शैतान को भी शर्म आ जाए. पुलिस बलात्कार और हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और उसके पश्चात ब्रेकअप के बाद पनपे गुस्से को भी घटना से जोड़कर देख रही है. घटना के राजफाश के लिए डीजीपी एएल बनर्जी ने कई टीमें बनाई हैं.

यह दर्दनाक हादसा सुनते ही जनता का गुस्सा सांतवें आसमान पर चढ़ गया, तो तमाम दलों के नेताओं ने समाजवादी सरकार को कोसना शुरू कर दिया. नवनियुक्त राज्यपाल राम नाइक ने अफ़सोस जताते हुए माना कि यूपी में क़ानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या है और उसके सुधार पर वह ध्यान देंगे. उधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गुनहगारों की ज़ल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की घोषणा तुरंत ही कर दी. भाजपा नेताओं ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रदर्शन भी किया. ज़्यादा हाय-तौबा न हो, उसके लिए आनन-फानन में एसएसपी प्रवीण कुमार ने इंस्पेक्टर कमरूद्दीन ख़ान और एसआई मुन्नी लाल को निलंबित कर दिया, लेकिन मामला ठंडा होता दिख नहीं रहा है. कई महिला संगठन भी विरोध में सामने आ गए हैं.

बहरहाल, ऐसा लगता है कि यूपी में लड़कियों का विश्वास सिर्फ़ क़ानून व्यवस्था से ही नहीं, बल्कि सरकार, पुलिस, समाज, दोस्तों और नाते-रिश्तेदारों से भी उठता जा रहा है. बात चाहे बदायूं की हो या फिर लखनऊ के मोहनलालगंज की, ये सभी घटनाएं यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. प्रदेश में सामूहिक बलात्कार कभी न थमने वाला एक सिलसिला बन गया है. यहां कब, कहां और कौन सी वारदात हुई उसे विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है. सब जानते हैं कि यूपी में महिलाओं के साथ लगातार घिनौनी वारदातें हो रही हैं. ज़्यादा पीछे न भी जाया जाए, तो पिछले कुछ माह के दौरान ही महिलाओं के साथ दर्जनों बलात्कार और उसके बाद हत्या की वारदातें हो चुकी हैं. महिलाओं के साथ बढ़ती वारदातें कहीं न कहीं यह भी दर्शाती हैं कि हमारा सिस्टम और सरकार पूरी तरह से नाकारा साबित हो रही हैं. ख़ासकर, तब जब सरकार के मंत्री यह कहें कि सभी लड़कियों के पीछे पुलिस तो नहीं लगाई जा सकती है और उनके मातहत काम करने वाले डीजीपी साहब इसे रूटीन की घटना बताते हों तो हालात की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. यह बात सुनने में तो सही लगती है, लेकिन ऐसी बातों से हक़ीक़त पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है. दरअसल,कई बार देखने में आया है कि पुलिस अपराधियों की मददगार बन जाती है. थाने में कोई युवती रिपोर्ट लिखाने जाए, तो उससे तमाम उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं. छेड़छाड़ की घटनाओं को तो मामूली बताकर पुलिस पल्ला झाड़ लेती है. उसे इस बात का अहसास नहीं रहता कि शुरुआत में ही अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए जाएं, तो बड़ी वारदातों को पूरी तरह से रोका भले ही न जा सके, लेकिन कम तो किया ही जा सकता है.

महिलाओं के साथ बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में महिला समाजसेवियों की नाराज़गी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है. भारतीय महिला फेडरेशन की प्रदेश महासचिव आशा मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में क़ानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. त्वरित कार्रवाई न होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. ख़ैर अब जो पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे उनके ख़िलाफ़ ज़ल्द आंदोलन किया जाएगा. लखनऊ विश्वविद्यालय की वीसी रह चुकीं रूपरेखा वर्मा को इस बात का मलाल है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस के पास कोई योजना नहीं है. उनके अनुसार, कई मामलों में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

04 अगस्त–10 अगस्त 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

पेज 20

बिहार झारखंड

तख्त और ताज के लिए होने लगे दावे

वही ताज है, वही तख्त है, वही ज़हर है, वही जाम है,
ये वही ख़ुदा की ज़मीन है, बता कौन इसका निज़ाम है

मसला चूंकि तख्त और ताज का है, इसलिए बिहार में अभी लाख टके का सवाल यही है कि आख़िर बिहार का अगला निज़ाम कौन होगा? ख़ासकर भाजपा में यह क़वायद ज़ोर पकड़ चुकी है. भाजपा कार्यसमिति की बैठक में राधामोहन सिंह ने सुशील कुमार मोदी का नाम उछालकर एक तरह से पहला किक लगा दिया है. इस शॉट को रोकने के लिए भाजपा के कई दिग्गज लग गए हैं. दस सीटों पर होने वाला चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में ज़ाहिर है कि ये नतीजे काफ़ी हद तक यह तय कर देंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा?

सरोज सिंह

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को आगामी विधानसभा चुनाव में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की पहल के साथ ही भाजपा के अंदर राजनीति भी गर्म होने लगी है. केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह की इस पहल को लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अंदरख़ाने में नाराज़गी का इज़हार भी करना शुरू कर दिया है. अपने आक्रोश का इज़हार करने के लिए भाजपा के कई नेता कार्यसमिति की बैठक के पहले दिन ही निकल गए, जबकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने दूसरे दिन की बैठक में शिरकत तक नहीं की.

दरअसल, बीते 19 जुलाई को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में अगले सीएम के तौर पर सुशील कुमार मोदी के नाम पर चर्चा होने से उनके विरोधी खेमे और स्वयं को इस पद के दावेदार मानने वाले नेताओं ने सुशील मोदी की उम्मीदों पर क़रारा प्रहार किया.

ऐसे नेताओं से बातचीत करने पर वे खुल कर तो कुछ भी कहने से परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके बातचीत का जो अंदाज़ है, उसे देखकर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से चार सौ दिन पूर्व इस तरह की बयानबाज़ी से वे ख़ुश नहीं हैं.

बैठक के पहले दिन यानी उदघाटन सत्र में तो सब कुछ सहज तरीक़े से चला और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव रामलाल ने 172 से अधिक सीटों का लक्ष्य लेकर कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में उतरने का आह्वान किया. इस मौक़े पर उन्होंने नया नारा दिया– मांगे बिहार,भाजपा सरकार

भावी मुख्यमंत्री का मसला भोजनावकाश के बाद उठा. चुनावी चर्चा करते हुए अकस्मात केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच जो चुनावी गठबंधन हो रहा है, उससे मुक़ाबला करने के लिए सुशील कुमार मोदी को विधानसभा चुनाव की कमान दी जा सकती है. उन्होंने यह कह कर सुशील मोदी का वजन कुछ और बढ़ा दिया कि वह योग्य एवं अनुभवी नेता हैं और बतौर उपमुख्यमंत्री उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया.

राधामोहन सिंह तो अपनी बात तो कह गए, लेकिन उसके बाद कार्यकर्ताओं में फुसफुसाहट तेज़ हो गई. मंच पर अगली पंक्ति में बैठे वरिष्ठ नेताओं के चेहरे फक्क पड़ गए. मंचासीन नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सीपी ठाकुर, शाहनवाज़ हुसैन, राजीव प्रताप रुडी, अश्विनी कुमार चौबे, रामेश्वर चौरसिया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव शामिल थे. हालांकि, राजीव प्रताप रुडी शाम में ही बैठक से बाहर आ गए.

बाद में कृषि मंत्री ने दिखावे के लिए ही सही बात को संभालने का प्रयास भी किया. उन्होंने कहा कि सुशील मोदी के बारे में उन्होंने जो कहा वह मेरी व्यक्तिगत राय थी, लेकिन पार्टी सूत्रों के के मुताबिक़, मोदी के नाम की चर्चा बतौर भावी मुख्यमंत्री उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर की थी. चूंकि वह केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, लिहाज़ा मोदी के नाम का बीजारोपण करने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था. दरअसल, भाजपा नेतृत्व ऐसा कर पार्टी के अंदर सुशील मोदी की पकड़ का अंदाज़ा लेना चाहता था और अन्य दावेदारों की नब्ज़ को टटोलना भी उनका मक़सद रहा होगा, ऐसा लोगों का मानना है.

जब दूसरे दिन की बैठक में इस मसले पर कार्यकर्ता अंदर–बाहर चर्चा करते रहे, तो एक ख़ास रणनीति के तहत लोगों का गुस्सा कम करने के लिहाज़ से पार्टी के पूर्व बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड उचित समय पर फ़ैसला करेगा कि किसके नेतृत्व में भाजपा बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी.

बहरहाल, भाजपा केंद्रीय नेता अब चाहे जो भी सफाई दें, लेकिन बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली लौट कर वापस नहीं आती. कार्यसमिति की बैठक के दूसरे दिन सीपी ठाकुर, शाहनवाज़ हुसैन, राजीव प्रताप रुडी, अश्विनी कुमार चौबे और रामेश्वर चौरसिया नहीं आए. हालांकि, नंदकिशोर यादव मौजूद तो थे, लेकिन उनके चेहरे से वह चिरपरिचित मुस्कुराहट ग़ायब थी. शायद वह यही सोच रहे थे कि आख़िर मोदी में ऐसा क्या है, जो उनमें नहीं है.

बिहार के भावी मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव का समय आने दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए सुशील कुमार मोदी समेत पार्टी में कई नेता उपलब्ध हैं. बताया जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद ख़ुद भी इस पद की चाहत रखते है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि अभी चुनाव की तैयारी महत्वपूर्ण है. बात जहां तक भावी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की है, तो केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में सही समय पर फ़ैसला करेगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सीपी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कई सुपात्र मौजूद हैं और उसकी घोषणा केंद्रीय समिति करेगी; हालांकि उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ़ था कि वह सुशील मोदी के नाम को उछाले जाने से ख़ुश नहीं हैं. बैठक से ग़ायब होने का सबब जब शाहनवाज़ हुसैन से पूछा गया, तो फोन पर हंसते हुए वे गुनगुनाने लगे – हम तो हैं राही प्यार के हमसे इस वक़्त कुछ न पूछिए.दो दिवसीय बैठक में कार्यकर्ताओं को पांच मूलमंत्र देकर विदा किया गया. ये मंत्र हैं – संघर्ष जनता के लिए, संघर्ष राज्य के लिए, सुशासन विकास के लिए, सरकार जनकल्याण के लिए और सेवा अंत्योदय के लिए, लेकिन यहां सवाल यह है कि मंत्रोच्चार के लिए पुरोहित कौन होगा? वैसे तो राधामोहन सिंह ने अपनी मुरली से सुशील कुमार मोदी के नाम की धुन निकाल ही दी है. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में नाजुक समय में मोदी ने उन्हें जो मदद दी थी, उसके एवज़ में उन्होंने मोदी को खुलकर प्रोजेक्ट किया. सुशील मोदी के क़रीबी माने जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने कहा कि विधानसभा चुनाव की बाग़डोर किसे सौंपी जानी है, इसका फ़ैसला केंद्रीय समिति करेगी. राधामोहन सिंह ने सुशील मोदी को बतौर मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से पेश किया है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रदेश कार्यसमिति की अहम बैठक में क्या कोई वरिष्ठ नेता अपनी निजी राय रख सकता है? जानकारों के मुताबिक़, सुशील मोदी का नाम उछालकर एक तरह से प्रयोग किया गया है, ताकि विरोध की तीव्रता का आकलन किया जा सके. फ़िलहाल, जो बातें सामने आई हैं, उससे सुशील मोदी समर्थक काफ़ी ख़ुश हैं. वैसे इसमें कोई शक नहीं कि सुशील कुमार मोदी की बिहार भाजपा में एक अच्छी छवि है. बतौर उपमुख्यमंत्री भी उनके कार्यों की सराहना की गई, इसे लेकर वह भाजपा में एक स्वीकार्य नेता ज़रूर कहे जा सकते हैं. इस बीच भाजपा में जारी इस घमासान से जदयू को भाजपा पर हमला करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है. जदयू नेता छोटू सिंह कहते हैं कि सीएम के लिए वैकेंसी कहां है, जो सुशील मोदी या कोई अन्य भाजपाई नेता हाथ पैर मार रहे हैं. छोटू सिंह के अनुसार, भाजपाई अब दिन में भी सपने देखने लगे हैं और दिन में सपने देखने वालों का क्या हश्र होता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है. उसी तरह राजद के मीडिया प्रभारी प्रगति मेहता कहते हैं कि भाजपा के नेता अभी भी ज़ोश में हैं, इसलिए वे होश खो रहे हैं और बहकी–बहकी बातें कर रहे हैं. सुशील मोदी या किसी अन्य भाजपा नेता का सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता. बिहार की जनता बेहद समझदार है और सांप्रदायिक ताक़तों के हाथों में सूबे की कमान कभी नहीं सौंप सकती है.

बहरहाल, नाम उछालने की चाहे जो भी वजह हो, फ़िलहाल मोदी खेमे में उत्साह नज़र आ रहा है, जबकि भाजपा में उनके विरोधी खेमे के लोग बैकफुट पर आ गए हैं. अभी यह खेमा कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है. शायद उन्हें विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे का इंतज़ार है.■

– साथ में अबनींद्र नाथ ठाकुर

एक नज़र

98वें अंक का विमोचन

पटना के आईएमए हॉल में माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में केवल सच हिन्दी मासिक पत्रिका का नौवां स्थापना वर्ष मनाया गया. साथ ही 98वें विशेष अंक का विमोचन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया. उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि आज भी लघु एवं मध्यम पत्र-पत्रिका सामंतवादी विचारों की वजह से उपेक्षित हैं. समाज के इन तबकों तक आज भी मीडिया नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से जागरूकता के अभाव में इनको सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित कार्यक्रमों की जानकारी नहीं मिल पाती है. 9वें स्थापना वर्ष के अवसर पर लगभग 500 से अधिक पत्रकारों के जत्थे द्वारा एक जूलूस भी निकाला गया. इस अवसर पर सहकारिता मंत्री जयकुमार सिंह, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश सिंह, राजेश्वर राज कारकाट विधायक, संपादक ब्रजेश मिश्र व प्रबंध संपादक शैलेश कुमार तिवारी भी उपस्थित रहे.

– चित्रा भारती

चिकित्सा शिविर आयोजित

पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र के नक्सलप्रभवित क्षेत्र के परसौनी कपूर गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में रोटरी क्लब एवं रेड क्रॉस सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय मुफ्त चिकित्सा शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में एक हजार पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें मुफ्त में दवाइयां दी गईं. मौके पर पंचायत के पूर्व मुखिया संजय कुमार सिंह, वर्तमान मुखिया पति सुबोध कुमार सिंह, रामबाबू प्रसाद, मुकेश कुमार आदि लगभग दो दर्जन लोगो ने रक्तदान किया. मौके पर सिविल सर्जन डॉ. मीरा वर्मा, रेड क्रॉस के अध्यक्ष श्री प्रकाश चौधरी, अरुण कुमार यादव, दिलीप कुमार, डॉ. लालबाबू प्रसाद, रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनीष कुमार, सचिव विभूति नारायण सिंह, रोहित कुमार साह, अभिमन्यू कुमार, मुन्ना कुमार, ओएसडी अमरेन्द्र कुमार, पकड़ीदयाल एसडीओ शैलेश कुमार, बीएमपी विजय कुमार, बीडीओ सुनीता कुमारी, सीओ ललित कुमार झा, प्रभारी डॉ. प्रेम सागर प्रसाद, सीआरपीएफ के असीस्टेंट कमांडेट संजीत पांडेय, डॉ. चन्द्र सुभाष, डॉ. ओमप्रकाश, डॉ. रमेश कुमार, डॉ. मनीर अंसारी, डॉ. संजीत कुमार, डॉ. पीके वर्मा, डॉ. अजीत कुमार, डॉ. मुन्ना कुमार, डॉ. मोन्दिता जायसवाल, डॉ. सिकिन्दर, डॉ. डेजी सिन्हा, डॉ. रितेश कुमार, डॉ. मोहन प्रसाद, थानाध्यक्ष किशोरी चौधरी, दरोगा सोनफी पासवान सहित जिले व अनुमंडल स्तर के अधिकारी मौजूद थे.

विकलांगता जांच शिविर आयोजित

प्रत्येक महीने की भांति इस माह में भी सदर अस्पताल परिसर में विकलांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया जहां सैकड़ों मरीजों की विकलांगता की जांच की गई एवं प्रमाण पत्र वितरण किया गया. सदर अस्पताल के चिकित्सक व जिले के सुप्रसिद्ध व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. कुमार सौरभ ने बताया कि लगभग ढाई सौ मरीजों की विकलांगता की जांच की गई. उन्होंने बताया कि चालीस प्रतिशत से अधिक विकलांग वाले मरीजों को यहां से बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है. साथ ही अनेक विकलांगों की जांच कर उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया है. वहीं ईएनटी में लगभग एक सौ पचास मरीजों की जांच की गई और उन्हे प्रमाण पत्र दिया गया. आंख, नाक, कान एवं गले की जांच कर रहे चिकित्सक व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. गगन देव प्रसाद एवं डॉ. आलोक कुमार ने जांच करते हुए बताया कि प्रमाण पत्र मिलने से विकलांगों के भविष्य में रोजगार के अनेक अवसर मिलते है एवं उन्हें काफी छूट मिलती है. मौके पर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेषक डॉ. विवेक कुमार भी उपस्थित थे.

– इन्तेजारुल हक

पित की थैली की बिमारी ईलाज और बचाव

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ. सरयु प्रसाद शर्मा
फिजिशियन, चर्च रोड गया

पित की थौली की बिमारी मगध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाया जा रहा है। यह बिमारी उस स्थिति में और घातक सिद्ध होती है जब कि आप इसके इलाज में कोताही बरत रहे होते हैं। यदि आपको निम्न लक्षण महसूस हो तो आप तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें और सही ईलाज करवायें यह मूलतः दो कारणों से होता है। पित की थोली में सूजन तथा पित की थैली में पत्थर। का होना। अधिकतर मरीजों को पित की थैली में पत्थर ही होता है। इसके लक्षणों में उल्टी आना भुख नहीं लगना, गैस फार्म (ढकार आना) इस बिमारी के उपचार के लिए दवाएं भी उपलब्ध है लेकिन समय के साथ ये दवायें भी कम असरदार हो जाती है। इस बिमारी से पूर्णत सही होने के लिए ऑपरेशन सबसे जरूरी माना गया है। इस बिमारी के उपचार के लिए सिलिप्लेक्स, यूरिस्लीव, तथा एरीजोल डी आदि दवाएं मरीजों को चिकित्सकों की सलाह पर दे सकते हैं।

URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp. Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

प्रस्तुति: चित्रा भारती

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

बेगूसराय

कावर झील के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह

सुरेश चौहान/संदीप कुमार

सरकार एवं किसानों के बीच उठे नये विवादों ने विश्व के ख्याति प्राप्त पक्षी विशेषज्ञ डॉ. सलीम अली के सपनों के पक्षी विहार एवं कावर झील के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है. विवाद को सुलझाने में मंझौल अनुमंडल पदाधिकारी की सुस्ती के कारण पिछले कई वर्षों से कावर झील के विकास का कार्य पूर्णरूपेण ठप पड़ा है, जबकि इसके विकास के लिए लाखों रुपये का सरकारी अनुदान [illegible] कारण सरकारी योजनानुसार कावर झील न तो वास्तव में पक्षी विहार ही बन पाया और न ही कृषि योग्य क्षेत्र ही.

प्रशासनिक स्तर पर भूमि का सर्वेक्षण कार्य जारी है. [illegible] योजनानुसार कावर झील के विकास का कार्य अवरुद्ध है. [illegible] सरकारी [illegible] समृद्ध [illegible] कार्य शी[illegible] को पक्षी [illegible] जमीन के [illegible] कम जमीन [illegible] को इसके [illegible] कृषि का[illegible]

कावर झील का विवाद काफी पुराना है. अंग्रेजों के शासनकाल में [illegible] कावर झील [illegible] किसान [illegible] मामला [illegible] मल्लाह [illegible] इंग्लैंड के [illegible] काउंसिल [illegible] हुए निर्णय [illegible] पर किसान [illegible] अधिकार [illegible] किसान उक्त जमीन पर खेती करेंगे और जल रहने पर मछली पकड़ने का अधिकार मल्लाह को प्राप्त होगा. उक्त निर्णयानुसार लगभग आठ हजार भूखंड में फैली कावर झील का विवाद समाप्त हो गया और मल्लाह तथा किसान दोनों इस निर्णय का पालन 1954 तक करते रहे.

[illegible] सिंह ने [illegible] अंतर्गत [illegible] लगभग [illegible] निर्माण [illegible]तिरिक्त [illegible] इस [illegible] नहर के [illegible] हुआ [illegible] पाया है. इस झील के किनारे स्थित ऊपरी भूखंडों पर खेती भी होती रही और नहर से किसानों को सिंचाई में काफी मदद भी मिलने लगी. धीरे-धीरे पक्षियों ने इसे ठंड के महीनों में अपना आश्रयस्थल बना लिया. 1972 में जब बेगूसराय को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ तब से जिला प्रशासन ने इस झील के विकास के नाम पर लाखों रुपये व्यय किये. पक्षी विशेषज्ञ डॉ. सलीम अली की शोध स्थली के रूप में कावर झील को ख्याति मिली. डॉ. सलीम अली ने पक्षियों के पैरों में छल्ले बांधकर यह अन्वेषण किया कि ठंड के मौसम में विश्व के दूसरे देशों से भी पक्षी यहां शीतकालीन भ्रमण पर आते हैं, खासकर साइबेरिया से सर्वाधिक.

डॉ. सलीम ने पाया कि इस पक्षी आश्रयस्थली में एक सौ से अधिक प्रकार के पक्षी निवास करते हैं तथा लगभग सौ से अधिक प्रकार के वनस्पति पौधे पाये जाते हैं. सरकार ने इस पूरे कावर झील क्षेत्र में पक्षियों के शिकार पर रोक लगा दी. जिससे मल्लाहों की जीविका प्रभावित हुई. बाद में धीरे-धीरे बूढ़ी गंडक नदी की जल धारा का रुख बदलने लगा. फलतः नहर के मुहाने पर सिल्ट जमा हो गया और कावर झील में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी. इसी बीच 1987 में आयी भीषण बाढ़ ने इस झील से जल निकासी के सभी स्वाभाविक (प्राकृतिक) स्रोतों को खेल दिया जिससे जल निकासी होने लगी और किसानों ने पुनः खेती का कार्य प्रारंभ कर दिया. संयोगवश 1992 में इस जल संग्रहण क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम हुई. कावर झील के अधिकांश भाग का जल सुख गया. किसानों को खेती करने लायक जमीन उपलब्ध हो गयी. कावर झील के जिस भाग में जल सूख चुका है या जल निकासी हो चुकी है. इस जमीन पर गेहूं, दलहन, तिलहन (खासकर सरसों) एवं गन्ने की खेती होने लगी.

कावर झील क्षेत्र एवं इसके आसपास टाल क्षेत्र की मिट्टी कैलकेरियस है जो काफी उपजाऊ होती है तथा इसकी फसल (मछली भी) काफी स्वादिष्ट होती है. जिले का एकमात्र यह क्षेत्र है जहां जल निकासी के बाद भूमिहीनों ने शांतिपूर्ण ढंग से इस पर कब्जा किया जिसमें हरिजन, पिछड़ी जाति एवं महुआ जाति सहित अन्य खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं. उपजाऊ मिट्टी होने के कारण प्रति एकड़ लगभग 70 मन गल्ला पैदा किया जा रहा है.

लेकिन कावर झील के चारों ओर के दो दर्जन से अधिक गांव के लोग आज तक आश्वस्त नहीं हो पाये हैं कि उक्त जमीन पर इनका कब्जा कायम रहेगा या इस पर पक्षी विहार विकसित किया जायेगा. इस संशय की स्थिति समाप्त करने के लिये अखिल भारतीय किसान संघ ने सुझाव दिया कि 110 फीट 7 इंच की ऊंचाई से लेकर 115 फीट की ऊंचाई तक का केन्द्रीय एरिया यानी लगभग दो हजार पांच सौ एकड़ भूमि को घेरकर पक्षी विहार बना दिया जाये और बाकी जमीन का विकास कृषि विहार के लिये किया जाये. इससे किसानों एवं मल्लाहों की जीविका भी नहीं छिन पायेगी और पक्षी विहार सह पर्यटक स्थल के रूप में इसे विकसित करने की सरकारी संकल्प के मार्ग की बाधाएं भी समाप्त हो जायेगी.

feedback@chauthiduniya.com

चंपारण

अरबपतियों को मिला राशन कार्ड

लूट की योजना बनकर रह गई है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

इन्तेजारुल हक

गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले जरूरतमंदों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चंपारण में पूरी तरह से लूट की योजना बनकर रह गयी है. इस योजना को जमीन पर उतारने व वास्तविक जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार व इसके आलाधिकारी भले ही कागज पर अनेक दावे कर लें और अपनी पीठ खुद थपथपा लें किन्तु जमीनी सच्चाई कुछ अलग बयान करती है. यह योजना यहां पूरी तरह से भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसकर रह गयी है और विभागीय नियमों व सरकारी आदेशों की खुलेआम धज्जिया उड़ाते हुए गरीबों को इस महत्वकांक्षी योजना से वंचित कर दिया गया है तथा करोड़पतियों, नामी-गिरामी व्यवसायियों,चिकित्सकों व कालेजों के प्राध्यापकों को राशन कार्ड निर्गत कर एक और बड़ा घोटाला करने का प्रयास किया गया है.

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल नगर इसका ज्वलन्त उदाहरण है. यहां करीब 35सौ लोगों को राशन कार्ड निर्गत किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को राशन कार्ड दिया गया है जो अरबपति हैं. नामी-गिरामी व्यवसायियों, कालेजों के प्राध्यापकों व कई मशहूर चिकित्सकों के साथ-साथ कई पेट्रोल पंप के मालिक भी लाभार्थियों की सूची में शामिल हैं और राशन कार्ड पा चुके हैं. रक्सौल नगर में स्थापित पेट्रोल पंप के मालिक नागेश्वर केडिया, प्रसिद्ध व्यवसायी गोपी राम धनौदियाति, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. खुर्शीद आलम, डॉ उमेश प्रसाद, अभिनव पांडेय व केसीटीसी कालेज के प्राध्यापक प्रो. चन्द्रमा सिंह समेत सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड मिला हुआ है। चौथी दुनिया ने जब इस योजना की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया तो कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसे जांच के बाद चौंकाने वाले अनेक तथ्यों का खुलासा हुआ है और इस योजना में भ्रष्टाचार की जड़ कितनी मजबूत है यह भी स्पष्ट हो गया है.हालाकि कुछ लोग इसके लिए समाजिक,आर्थिक व जातीय जनगणना में हुई खानापूर्ति को मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं कि बंद कमरे में जनगणना हुई है जिसकारण इस तरह की गड़बड़ी हुई है. जबकि दूसरी तरफ कुछ जानकार अधिकारियों की मनमानी व इनकी भ्रष्ट शैली पर सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि एक बड़ी साजिश के तहत गरीबों का अनाज छीनने का प्रयास किया गया है जिसकी किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करा दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. हैरत की बात तो यह है कि इनमें कई करोड़पति लाभार्थियों ने दूरभाष पर इसकी शिकायत भी अधिकारियों के यहां दर्ज करायी तो जवाब मिला कि आप को इससे क्या प्रोबलम है? राशन कार्ड मिला है तो इसका इस्तेमाल करें. यहां बतातें चलें कि इस योजना के तहत प्रत्येक कार्डधारी को 5 किलो आनाज जिसमें तीन किलो गेहुं एक रुपये की दर से व दो किलो चावल दो रूपये की दर से देने का प्रावधान है और यह योजना पूरी तरह से गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों के लिए है. ऐसे हालात में इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे और शिकायतों की शीघ्र जांच हो इसके लिए सरकारी व गैरसरकारी स्तर पर ठोस पहल की आवश्यकता है. यही स्थिति मोतिहारी नगर, सदर, बंजरिया, पहाड़पुर, कल्याण पुर, ढाका, बनकटवा, चिरैया, मधुबन, पताही, फेनहारा व सुगौली, छौड़ादानो, आदापुर, बनकटवा, अरेराज, संग्रामपुर, रामगढ़वा, रक्सौलकेसरिया, कोटवा व बंजरिया आदि प्रखंडों की है जहां गरीबों का नाम इस योजना से अलग कर दिया गया है और करोड़पति लोगों का नाम शामिल किया गया है. जानकार बताते हैं कि यहां भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और अमीरों को लाभ पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई है. यहां आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की मनमानी भी जानकार चरम पर बताते हैं और कहते हैं कि खुलेआम नियमों की यहां धज्जिया उड़ायी जाती है जिसका विरोध भी जमकर होता है और लोग कहीं-कहीं सड़क जाम करने से लेकर प्रखण्ड मुख्यालयों पर धरना भी देते हैं. बावजूद इसके अधिकारियों की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं होती और अनजान बनकर सबकुछ देखते रहते हैं. दूसरी तरफ सरिस्वा नदी बचाओ आंदोलन के मुख्य कार्यकर्ता व प्रसिद्ध सेवी प्रो. अनील कुमार सिन्हा, बाब संस्था के संस्थापक अध्यक्ष साजिद रेजा, प्रसिद्ध चिकित्सक व राजद के वरीष्ठ नेता डॉ. शमीम अहमद आदि बताते हैं कि इस योजना में मची लूट पर शिकंजा कसने के लिए बिहार की जदयू सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए तथा मामले की जांच करदोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. वे बताते हैं कि समय रहते इस योजना पर विशेष निगरानी नही बरती गयी तो आने वाले समय में स्थिति काफी खराब होगी. इन्होंने पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह से भी इस योजना पर विशेष नजर रखने का अनुरोध किया है.

शमीम अहमद | अनील सिन्हा | साजिद रजा

हैरत की बात तो यह है कि इनमें कई करोड़पति लाभार्थियों ने दूरभाष पर इसकी शिकायत भी अधिकारियों के यहां दर्ज करायी तो जवाब मिली कि आप को इससे क्या प्रॉब्लम है? राशन कार्ड मिला है तो इसका इस्तेमाल करें. यहां बतातें चलें कि इस योजना के तहत प्रत्येक कार्डधारी को 5 किलो अनाज मिलता है.

feedback@chauthiduniya.com

Mob. : 9386745004, 9204791696 | www.iiher.org, Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH

Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

Name of Courses		Eligibility	Duration
POST GRADUATE COURSES :			
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus - Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डा. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

गया

गांवों के लिए वरदान बना आयुर्वेद कॉलेज

सुनील सौरभ

रात क्या जहां दिन में भी जाने में किसी अनजान व्यक्ति को डर लगता हो, पूरा क्षेत्र नंगी पहाड़ियों से घिरा हो और जिस क्षेत्र में दिन में भी नक्सलियों की आवाजाही हो, वैसे क्षेत्र के लाखों लोगों के स्वास्थ्य सेवा की चिंता ने एक संत को विचलित कर दिया. संत ने तब इस क्षेत्र के ग्रामीणों के स्वास्थ्य सेवा का संकल्प लिया. आधुनिक चिकित्सा पद्धति को छोड़कर संत ने प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के सहारे गया जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवा का संकल्प लिया. आज एक संत का संकल्प इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है. गया-क्यूल रेलखंड के बीच गया से करीब 25-30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है करजरा रेलवे स्टेशन. इसी के पास स्थित है राधवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी स्वामी आयुर्वेद कालेज अस्पताल. आज यह आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल गया जिले के वजीरगंज प्रखंड की तीन पंचायतों करजरा, महुएत और नवादा के करीब तीन दर्जन छोटे-बड़े गांव टोले के लगभग एक लाख की आबादी के लिए लाइफलाइन बना है. इसकी स्थापना के पूर्व यहां के ग्रामीणों को छोटी-मोटी बीमारी के लिए भी दस-पन्द्रह किलोमीटर दूर वजीरगंज या फिर गया शहर जाना लाचारी थी. गया-कियुल रेल खंड पर होने के कारण दिन भर में दो जोड़ी पैसेन्जर ट्रेन आसपास के ग्रामीणों के आवागमन का एक मात्र साधन है. ये ट्रेनें भी समय से नहीं आती हैं.

पूर्व-मध्य रेलवे का करजरा ऐसा स्टेशन है जहां कोई रेलकर्मी नहीं रहता है. करीब डेढ़ दशक पूर्व नक्सलियों ने करजरा स्टेशन भवन को उड़ा दिया था. तब से यहां कोई रेलकर्मी रहना नहीं चाहता है. इसी एक घटना से इस क्षेत्र की भयावहता को समझा जा सकता है. आयुर्वेद कॉलेज के संस्थापक रामानुजाचार्य संप्रदाय से आनेवाले रामानुजाचार्य मठ, देवघाट, विष्णुपद गया के स्वामी राघवाचार्य बताते हैं कि आज तक किसी व्यक्ति ने आयुर्वेद कॉलेज के कार्यो में कोई बाधा नही उत्पन्न की बल्कि सहयोग किया. बीसवीं सदी के अस्सी के दशक के अंत में जब स्वामी राघवाचार्य ने आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल की नींव रखी थे तो लोगों ने इसकी सफलता पर संदेह व्यक्त किया था, लेकिन स्वामी राघवाचार्य अपनी धुन और लगन मे लगे रहे. आज लोगों की सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हो रही है. आज भी इस क्षेत्र मे नक्सलियों की आवाजाही है, फिर भी आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल के कर्मी बेखौफ लोगो की चिकित्सा सेवा मे लगे रहते हैं.

गया के प्रसिद्ध रामानुजमठ के स्वामी राधवाचार्य को पूजा के लिए विष्णुपद आये जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों ने जब यह बताया कि गांव समेत आसपास के ग्रामीणों को बीमार पड़ने पर पन्द्रह-बीस किलोमीटर पैदल चलकर गया या वजीरगंज आना पड़ता है मरीज को लेकर , तब स्वामी जी ने इसे अपनी पीड़ा समझी. ग्रामीणों ने जब यह भी बताया कि कभी -कभी तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है, यह सुनकर प्रौढ़ स्वामी राधवाचार्य को काफी दु:ख हुआ और उन्होनें वहां के ग्रामीणों की सेवा के लिए एक संकल्प लिया और बीसवीं सदी के अस्सी के दशक मे लिया गया वह संकल्प आज पूरी तरह फल-फूल रहा है आयुर्वेद कॉलेज-अस्पताल के रूप में यह अस्पताल आज वहां के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है. सबसे बड़ी बात है कि करजरा के आसपास सालों भर सांप-बिच्छू का आंतक बना रहता है. आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल मे स्वामी राघवाचार्य ने ऐसी अचूक दवा ईजाद की है जो मिनटों मे सांप-बिच्छू के डंसने वाले लोगों को तुंरत ठीक कर देती है. स्वामी जी मंत्र से भी बिच्छु के शिकार बने लोगों को ठीक कर देतें हैं.

इस आयुर्वेद कॉलेज को भारत सरकार तथा बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है. यहां प्रतिवर्ष 40 छात्रों का नामांकन आयुष की पढ़ाई के लिए होता है. यहां पढ़ाई करने वाले आयुर्वेद छात्र तथा पढ़ाने वाले आयुर्वेद चिकित्सक प्रतिदिन गया से आकर पढ़ाई व इलाज के लिए आये लोगो की चिकित्सा में लग जाते हैं लेकिन इस आयुर्वेद कॉलेज मे काम करने वाले कुछ लोगों ने स्वामी राघवाचार्य के अच्छे मंसूबे को तार तार करने का प्रयास किया. परन्तु वैसे लोगों को असफलता ही हाथ लगी . कुछ लोगों की साजिश के कारण ही इस कॉलेज में तीन वर्षो तक नामांकन नहीं हो सका था. जबकि सरकार ने आयवेंद कॉलेजों की सही स्थिति का अवलोकन करने और नामांकन के लिए निर्धारित सीटों मे सरकार के हिस्से के लिए उन्नीकृष्णन अयोग का गठन किया गया और सरकार को आधे सीटों पर हक मिलने की तरफदारी की. स्वामी राघवाचार्य जी ने उच्च न्यायलय जाकर इस मामले की लड़ाई लड़ी. मुकदमे में उन्होंने बताया कि सरकार से हम किसी तरह का अनुदान नहीं लेते हैं तो ऐसे में सरकार का हक नहीं बनता है. यदि सरकार चाहती है तो कॉलेज का अधिग्रहण विधिवत कर लें, हम देने को तैयार हैं. इस मामले पर राघवाचार्य जी की जीत हुई और राज्य के सभी आयुर्वेद कॉलेजों को राहत मिली थी. आज यह आयुर्वेद कॉलेज गया जिले के सुदुरवर्ती नक्सल ग्रासित क्षेत्र के मरीजों के लिए वरदान बना है. यही कारण है कि क्षेत्र के लोग स्वामी राधवाचार्य को भगवान के रुप मे मानते है . इस आयुर्वेद कॉलेज के रहने से अब तक हजारो लोगो की जान असमय मौत के गाल मे समाने से बची है.

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

नो मैंस लैंड का कोई मां-बाप नहीं

वाल्मीकि/अमरनाथ

भारत-नेपाल सीमा पर हाल के दशक में अतिक्रमण का सिलसिला काफी बढ़ गया है. आलम है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा बॉर्डर के कई स्थानों पर तो यह निर्णय कर पाना मुश्किल हो गया है कि भारत का हिस्सा है अथवा नेपाल का. सरकारी उदसीनता का नतीजा है कि अब दोनों देशों के बीच सीमांकन पीलर को भी ध्वस्त करने का प्रयास किया जाने लगा है. दशकों पूर्व पीलर पर खोदा गया दोनो देशों के नाम तक को मिटाने से असामाजिक तत्व परहेज नही कर रहे हैं....

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत-नेपाल सीमा को लेकर समय-समय पर हर जगह चर्चाएं होती रही है. हर सरकार के कार्यकाल में सीमा क्षेत्र के विकास के लिए कार्य योजनाएं बनायी जाती रही है. सरकार के द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन भी कराया जाता रहा है. हाल के सालों में भारत-नेपाल सरकार के बीच हुए नए समझौता को अमलीजामा पहनाते हुए कई योजनाओं का कार्यान्वयन भी कराया गया है. जिसमें भारत-नेपाल सीमा के सोनबरसा में झीम नदी पर पुल निर्माण भी शामिल होना बताया जाता है. इसका मकसद दोनों ही देशों के परंपरागत व सांस्कृतिक संबंधों में मजबूती का प्रयास होना बताया जाता है. एक ओर दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों में मजबूती को लेकर प्रयास जारी है तो दुसरी ओर कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से दोनों देशों के बीच के सीमांकन को मीटा कर नया विवाद खड़ा करने की साजिश की जा रही है. बताया जाता है कि इसका कारण दोनों देशों के बीच स्थित नो मेंस लैंड पर लगातार बढ़ता अतिक्रमण है. अतिक्रमणकारियों के बढ़ते मनोबल का परिणाम है कि नेपाल के त्रिभुवन नगर, सखुआ व परसा समेत अन्य स्थानों के किसानों ने नेपाली क्षेत्र में नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है. उक्त क्षेत्र के किसान अपने खेत के मेड़ को बढ़ाते हुए उसे अब बिल्कुल ही नो मेंस लैंड के करीब पहुंचा दिया है. यही हाल भारतीय क्षेत्र के उन्दरबा, नरकटिया, बसतपुर व सोनबरसा का भी है. नतीजतन दोनों ओर से जारी अतिक्रमण के कारण अब बीच में मौजूद सीमा का पीलर ही बाकी रह गया है. हाल के साल में कुछ लोगों ने पीलर को क्षतिग्रस्त कर दोनों देशों के बीच नया विवाद खड़ा करने की साजिश की है. मोटा लोहा व सीमेंट से निर्मित पीलर को तोडने का असफल प्रयास तक किया गया है. जब सफलता नहीं मिली तब पीलर से दोनों देश के नाम को ही मिटा दिया गया है.

भारतीय क्षेत्र के सोनबरसा बॉर्डर की चर्चा करें तो कई तथ्य इसका जीवंत उदाहरण प्रतीत होते है. इस बीच नेपाल से निकलने वाली झीम, सिंगियाही व गोवा नदी को पार कर सीमा उन्दरबा जाता है. इसी रास्ते मेंभारत-नेपाल सीमा पर पीलर संख्या-322/4 मौजूद है, जिसे क्षतिग्रस्त कर विवाद खड़े करने का प्रयास किया गया है. इस स्थान पर ही नेपाली क्षेत्र में नेपाल के त्रिभुवन नगर के अल्पसंख्यकों का पुराना कब्रिस्तान भी मौजूद है. जबकि तकरीबन एक किलोमीटर अलग मौजूद झीम नदी पुल के समीप सोनबरसा बाजार है. इस स्थान पर तो अगर एसएसबी के चेक पोस्ट को हटा दिया जाए, तो दोनों ही देश की सरहद को पहचान पाना भी आसान नही है. इस स्थान पर भारतीय क्षेत्र में कई लोगों ने नो मेंस लैंड पर कच्चा-पक्का मकान तक बना लिया है. यहा लगने वाले बाजार में दोनों ही देश के हजारों लोग प्रतिदिन आवश्यक सामानों की खरीदारी भी करते हैं. दोनों देश के लोगों के बीच आपसी संबंध बेहतर है, लेकिन सीमा के साथ की जा रही छेड़छाड़ के कारण भविष्य में दोनों देशों के बीच सीमांकन को लेकर विवाद की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है.

भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा एवं असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने को लेकर तैनात एसएसबी की 20 वीं बटालियन भी पीलर की समस्या से अवगत है. एसएसबी की मानें तो भारत-नेपाल सीमा पर अतिक्रमण के साथ पीलर के क्षतिग्रस्त किए जाने की रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है. बताया जाता है कि सरकारी व विभागीय निर्देश के बिना मौजूद कर्मी नजर रखने के अलावा कुछ नही कर सकते हैं. असामाजिक तत्व एसएसबी की नजरों बचकर इस वारदात को अजाम दे रहे हैं. जवानों के गश्ती के दौरान अगर कोई पकड़ा जाएगा, तो कार्रवाई की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. वर्तमान हालात पर सीतामढ़ी के पूर्व सांसद नवल किशोर राय का कहना है कि पारगमन संधि को मजबूती के साथ जारी रखते हुए भारत सरकार को आवश्यक पहल करनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में सीमा पर किसी प्रकार का विवाद न हो. इसके लिए सीमांकन के साथ बाड़ लगा कर सीमा को सुरक्षित करना चाहिए. वही भारत-नेपाल मैत्री संबंध पर कार्य कर रहे मीडिया फॉर बॉर्डर हारमोनी के अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी का कहना है कि दोनो देशों के बीच रोटी-बेटी का संबंध रहा है. सीमा पर छोटी-मोटी बातों को लेकर कोई विवाद खड़ा नही हो इसके लिए दोनों देशों के स्थानीय लोगों की एक लोक समिति बनाने की मांग दोनों देशों के सरकार से की है.

भारत-नेपाल के पुराने संबंध में मजबूती का प्रयास के साथ ही सीमा पर जारी अतिक्रमण की समस्या को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है. अतिक्रमण एक ही तरफ से नहीं दोनों तरफ से जारी है. ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि नेपाल सरकार से समुचित वार्ता कर अतिक्रमण की होड़ पर विराम लगाने की दिशा में पहल करे. साथ ही सीमा पर मौजूद पीलरों की सुरक्षा को भी अहमयित देते हुए इसकी सुरक्षा पर ध्यान दे.

अगर ऐसा नहीं होता है, तो संभव है कि दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी का संबंध महज एक कहावत बन कर रह जायेगा. वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के सरकार को नो मेंस लैंड को अपनी जागीर मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

अक्षय बने संयोजक

अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के प्रदेष अध्यक्ष रामस्वरूप पासवान ने लोकनाथपुर निवासी अक्षय लाल पासवान को पूर्वी चंपारण जिले का संयोजक मनोनित किया है. प्रदेश अध्यक्ष रामस्वरूप ने पूर्व की कमेटी को भंग करते हुए यह मनोनयन किया है. उन्होंने बताया है कि पूर्व जिलाध्यक्ष परिषद के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहे और जिला कमेटी की बैठक नियमों के अनुकूल नहीं हुई जिस कारण संगठन को काफी नुकसान हुआ है. प्रदेश अध्यक्ष ने इसके साथ ही संयोजक को परिषद की शीघ्र बैठक बुलाने, समय निर्धारित करने व संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मनोनयन पर संगठन के लोगों ने बधाई दी है. बधाई देने वालों में सुनील पासवान, विजय कुमार पासवान, दयंती देवी, सविता देवी, उषा देवी, प्रभु पासवान, नवल किशोर पासवान, मदन पासवान, प्रवीण पासवान, राजेन्द्र पासवान, दिनेश पासवान, नागेन्द्र पासवान, प्रमोद पासवान, विक्रमा पासवान, भूषण पासवान, इन्द्रदेव पासवान, कृष्णा पासवान, शिवषंकर पासवान, रीता देवी आदि शामिल है.

– इन्तेजारुल हक

नि: शुल्क दवा वितरण

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुपरी अनुमंडल मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक नागेश्वर स्थान मंदिर परिसर में नि:शुल्क दवा वितरण षिविर का आयोजन किया गया. रेडक्रॉस सोसायटी की स्थानीय शाखा के तत्वावधान में एसडीओ सह अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के निर्देष पर आयोजन हुआ. ऋषिकेश चौधरी, धनंजय चौधरी व अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में स्वयंसेवक सेवा दे रहे है. सावन मास की सोमवारी के मौके पर आयोजित शिविर में आशुतोष चौधरी द्वारा टी शर्ट मुहैया कराया. उप शाखा के सचिव अतुल कुमार ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को शिविर का आयोजन किया जाना है.

– गोविंद

ट्राईसाइकिल वितरित

रुन्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री सामर्थ योजना के तहत 40 विकलांगों के बीच बीडीओ तारकेश्वर रजक ने ट्राइसाइकिल का वितरण किया गया. मौके पर प्रमुख संगीता देवी, मुकेश कुमार तिवारी, थानाध्यक्ष नितेंद्र कुमार, पूर्व मुखिया भारत भूषण सिंह उर्फ मुन्ना जी, पंसस सोनफी साह, लाल बहादुर सिंह, अनिल कुमार सिंह व राम सेवक राम समेत अन्य थे.

– विभा

पूर्व सीएम ने किया सम्मानित

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के लक्ष्मीपुर में आयोजित एक प्रतिभा सम्मान समारोह में शरीक हुए. एकलव्य पुलिस एकेडमी में आयोजित समारोह के मौके पर उन्होंने मैट्रिक परीक्षा के पांच टॉपर छात्रों को सम्मानित किया. कार्यक्रम के मौके पर इस बार पूर्व मुख्यमंत्री का लहजा बदला रहा. मांग को लेकर नारा लगाने वालों को साफ कहा कि अब उनके हाथ कुछ भी नहीं है. कार्यक्रम में संस्थान की सीएमडी रति रामबाबू गुप्ता, आयकर पदाधिकारी राम बाबू गुप्ता, गन्ना मंत्री डॉ. रंजू गीता, विधायक गुड्डी देवी, जदयू जिलाध्यक्ष राम जीवन प्रसाद, वरिष्ठ नेता राजेश चौधरी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे, आलोक कुमार मेहता, पूर्व सांसद नवल किशोर राय, डॉ. अर्जुन राय समेत अन्य थे. इससे पूर्व प्रसिद्ध गायिका देवी व गायक पवन सिंह ने बेहतर प्रस्तुति दी.

– अमरनाथ

इफ्तार का आयोजन

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित स्थानीय विधायक गुड्डी देवी के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया. मौके पर विधायक एवं वरिष्ठ जदयू नेता राजेश चौधरी ने कार्यकर्ताओं से आपसी एकता व सौहार्द बनाये रखने की अपील की. कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉ. अर्जुन राय, मो. इलियास, रेयाज खां, अनीसुर्रहमान, मो नजरे आलम, इम्तियाज अहमद, रामचंद्र सिंह, राम प्रवेष सिंह, राम मनोहर सिंह व कुमार संजीव समेत अन्य थे.

कन्या विवाह योजना का चेक वितरित

रुन्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित एक शिविर में कन्या विवाह योजना के तहत विशेष घटक अनुसूचित जाति के कुल 195 लाभार्थियों के बीच चेक का वितरण किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख संगीता देवी ने किया. मौके पर बीडीओ तारकेश्वर रजक, थानाध्यक्ष नितेंद्र कुमार, महिला प्रसार पदाधिकारी मीनू कुमारी, अनिल कुमार सिंह, मुकेश कुमार तिवारी व भारत भूषण सिंह समेत अन्य थे.

– विभा

लोकार्पण समारोह

भारत विकास परिषद की बेगूसराय शाखा के वरिष्ठ संरक्षक प्रोफेसर वेंकटेश प्रसाद सिंह द्वारा रचित 'स्वामी विवेकानन्द' एक जीवित वेदान्त पुस्तक का लोकार्पण ख्यातिप्राप्त चिंतक पूर्व कुलपति एवं पूर्व सांसद डॉ. रामजी सिंह ने किया. भारत विकास परिषद, बेगूसराय द्वारा भारद्राज गुरुकुल, पन्हांस के सभागार में आयोजित लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता एवं धन्यवाद ज्ञापन राज किशोर प्रसाद, मंच संचालन परिषद के स्थानीय शाखा अध्यक्ष एवं भारद्वाज गुरुकुल के निदेशक शिव प्रसाद भारद्वाज ने किया. हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं परिषद की जिला इकाई के संरक्षक डॉ नलिनी रंजन सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया. अतिथियों ने मंगलदीप प्रज्वलित कर भारत माता एवं स्वामी विवेकानन्द की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किया. पुस्तक का लोकार्पण करते हुए डॉ. रामजी सिंह ने स्वामी विवेवाकानन्द के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ज्ञान की सार्थकता को समझकर इसे अपने जीवन में उतारने वाला ही ज्ञानवान है. विवेकानन्द की जीवनी से मनुष्यता की सीख मिलती है. लोकार्पण समारोह में साहित्यकार डॉ. रोमेन शर्मा, परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. शिलेन्द्र कुमार, प्रोफेसर अमरेश शांडिल्य, प्रोफेसर मदनेश्वर नाथ दत्त, वैद्यनाथ चौधरी, डॉ. सुरेश प्रसाद राय सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे.

– सुरेश चौहान

संगठन की मजबूती की बात तो दूर, पार्टी व लालू के प्रति वफादर कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं. संगठन धीरे–धीरे अपनी ताकत खोता जा रहा है. इसका प्रमाण है यह है कि जब पहले लालू प्रसाद रांची आते थे, तो सैकड़ों समर्थकों की भीड़ उनके रांची छोड़ने तक पीछे–पीछे घूमती रहती थी, लेकिन पिछले दिनों जब लालू रांची आए और दो दिनों तक रुके. लेकिन लालू के इर्द गिर्द एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं नज़र आए. लोकसभा चुनाव के बाद झाविमो भी गठबंधन की तलाश में है.

भागलपुर

ज़हरीला पानी पीने को मजबूर

शुद्ध पेयजल आपूर्ति की योजना दम तोड़ चुकी है. हालात से लाचार लोग इन दिनों आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर हो गए हैं. पांच साल पहले जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अर्सेनिक प्रभावित इलाके की जांच की गई, जहां असाध्य रोगों से पीड़ित कई लोग मिले. तब प्रशासन के बीच हनक जगी. इसके बाद आनन-फानन में जांच कमेटी के द्वारा शुद्ध पेयजल की आपुर्ति के विल प्लांट लगाने हेतु प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा गया.

नमन कुमार चौधरी

भागलपुर जिले में लोग इन दिनों शुद्ध पेयजल की बहुत किल्लत बनी हुई है. भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों में दिन–ब–दिन पानी में आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है. जिसमें खासकर जिले से सटे नाथनगर व सुल्तानगंज प्रखंडों के कुल आठ पंचायतों की अस्सी हजार से अधिक की आबादी जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर हैं. उनके सामने शुद्ध पेयजल की घोर समस्या उत्पन्न हो गई है. जिस कारण वहां के लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए हैं. अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है. लेकिन सरकार व उनके रहनुमाओं का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है. शुद्ध पेयजल आपूर्ति की योजना दम तोड़ चुकी है. हालात से लाचार लोग इन दिनों आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर हो गए हैं. पांच साल पहले जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अर्सेनिक प्रभावित इलाके की जांच की गई, जहां असाध्य रोगों से पीड़ित कई लोग मिले. तब प्रशासन के बीच हनक जगी. इसके बाद आनन–फानन में जांच कमेटी के द्वारा शुद्ध पेयजल की आपुर्ति के विल प्लांट लगाने हेतु प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा गया. सरकार द्वारा प्लांट लगाने की स्वीकृति तो मिल गई, इसका बाद काम भी शुरू हो गया, लेकिन महकमे की सुस्त गति के कारण अब तक लोगों को पीने का साफ पानी उबलब्ध नहीं हो पाया है, कब तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी और लोगों के नसीब में साफ पानी आएगा यह बताने को कोई तैयार नहीं है.

निजी कंपनी के जिम्मे निर्माण कार्य

सुल्तानगंज स्थित जहांगीरा के समीप वाटर पम्प का निर्माण कार्य आईवीआरसीएल द्वारा किया जा रहा है. 10 जनवरी 2013 को इसकी संविदा 71.28 करोड़ में हुई थी. इसे 30 माह के अंदर पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. लेकिन वर्तमान में जिस गति से कार्य हो रहा है उससे काम के निर्धारित लक्ष्य(जून–2015) तक पूरे होने की संभावना कम ही नज़र आ रही है. सूबे की सरकार के पीएचई विभाग की निगरानी मे कार्य संपादित किए जा रहे हैं. इस संदर्भ में उक्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर चौथी दुनिया को बताया कि कार्य के पूर्ण होने में अभी डेढ़ साल से ज्यादा समय लग सकता है.

कैसे और कहां–कहां मिलेगी शुद्ध पेयजल

सुल्तानगंज के जहांगीरा स्थित निर्माणाधीन वाटर प्लांट में जल संग्रहण की क्षमता 7.3 एमएलडी होगी. गंगा के किनारे पंप हाउस का निर्माण किया जाएगा. जो कि भू–लत के नीचे निर्माण होगा. साथ ही नदी के किनारे जेटटी का भी निर्माण किया जाएगा. जिसके माध्यम से यह जल जहांगीरा तक पहुंचाया जाएगा. जहां पानी को रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध किया जाएगा. इसके बाद इसे पाईप लाईन के माध्यम से जीएसआर तक पहुंचाया जाएगा. जहांगीरा मे जल संग्रह करने के लिए ग्राउंड रिजरवायर भी बनाया जाएगा. इसके अतिरिक्त एक रिजर वायर का निर्माण नाथनगर के दोगच्छी में किया जाएगा. नाथनगर मे पांच जोनल ईएसआर का निर्माण होगा. लोगों तक शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए 110 किमी पाईप लाइन बिछाई जाएगी. रोड के किनारे स्टैंड पोस्ट का भी निर्माण होगा एवम चवालीस चौमुखी जल स्तंभ और तीन सौ दो मुखी जल स्तंभ का निर्माण सड़क किनारे किया जाएगा. नाथनगर की कुल छह पंचायत जिसमें गोसांईदासपुर, राघौपुर, रन्नुचक, रत्तीपुर, शंकरपुर तथा किसनपुर एवं सुल्तानगंज के असियाचक तथा भीरखुर्द पंचायत के लगभग 80 हजार लोगों को शुद्ध पेयजल की इस प्लांट के जरिए आपूर्ति होगी. जिसे पांच साल पहले ही अर्सेनिक प्रभावित पंचायत घोषित किया गया है.■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में भाजपा की घेराबंदी

मंगलानंद

लोकसभा चुनाव में सिमट जाने वाले सभी क्षेत्रीय दलों में बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि अब वे भाजपा को घेरने के नाम पर अपने सभी सिद्धांतों से भी समझौता करने से नहीं चूक रहे हैं. जैसे–जैसे विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो रही है, इन दलों की चिंता भी बढ़ने लगी है. लोकसभा चुनाव में अर्श से फर्श पर पहुंची पार्टियों के नेता भाजपा को घेरने की रणनीति बनाने में जुटे हैं. कल तक अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां अब गठबंधन के विकल्प तलाशने में जुटी हैं. लोकसभा चुनाव में शून्य पर आउट हो चुकी झारखंड के दो क्षेत्रीय द लों आजसू(ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन) और झाविमो(झारखंड विकास मोर्चा) के सुप्रीमो की बेचैनी इस बात को प्रमाणित करती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके समक्ष अपनी पार्टी के वजूद बचाने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है. सत्ताधारी गठबंधन यानि झामुमो(झारखंड मुक्ति मोर्चा) और कांग्रेस में खींचतान चल रही है. साथ ही कांग्रेस में नेताओं की उठापटक के बीच इन दलों के वरिष्ठ नेताओं की चिंता यह है कि बिखरे हुए संगठन को लेकर वो विधानसभा चुनाव में अपनी नैया कैसे पार लगाएंगे.

बिहार में फिलहाल जद(यू) और राजद(राष्ट्रीय जनता दल) एक हुए हैं और झारखंड में झामुमो, राजद और कांग्रेस की सरकार चल रही है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह घोषणा की है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव राजद, झामुमो और कांग्रेस मिलकर लडेंगे. 11 विधायक चुने गए थे. पुराने गठबंधन को दोहराने में सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ झामुमो का गठबंधन है. संताल परगना की राजनीति को लेकर झाविमो और झामुमो एक नहीं हो सकते.

झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन सभी राजनीतिक दलों में चुनावी सक्रियता बढ़ चुकी है. तमाम दलों में सबसे अधिक सक्रिय आजसू नजर आ रही है. आजसू प्रमुख सुदेश महतो स्वतंत्रता दिवस के पूर्व 25 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने की तैयारी कर चुके हैं. आजसू प्रमुख की बेचैनी बढ़ने के कई कारण हैं. हाल के दिनों में आजसू विधायकों के भाजपा प्रेम ने पार्टी को संकट में डाल दिया है. आजसू भाजपा के साथ गठबंधन करने के मूड में तो है लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं होने से आजसू सुप्रीमा के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही हैं. झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दमखम झारखंड के किसी भी क्षेत्रीय दल में दिखाई नहीं पड़ता है. यह बात स्पष्ट है कि राज्य की 81 सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर कोई भी दल सफलता हासिल नहीं कर सकता है. इन परिस्थितियों में विधानसभा के चुनाव में दलों का गठबंधन कौन सा आकार लेगा, इसका अनुमान लगाना फिलहाल काफी कठिन दिखता है. झारखंड में भाजपा को रोकने के लिए यहां राजनीतिक गोटियां बिछाई तो जा रही है लेकिन वो किस हद तक सफल होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. ■

लोकसभा चुनाव में शून्य पर आउट हो चुकी झारखंड के दो क्षेत्रीय द लों आजसू(ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन) और झाविमो(झारखंड विकास मोर्चा) के सुप्रीमो की बेचैनी इस बात को प्रमाणित करती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके समक्ष अपनी पार्टी के वजूद बचाने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है. सत्ताधारी गठबंधन यानि झामुमो(झारखंड मुक्ति मोर्चा) और कांग्रेस में खींचतान चल रही है. साथ ही कांग्रेस में नेताओं की उठापटक के बीच इन दलों के वरिष्ठ नेताओं की चिंता यह है कि बिखरे हुए संगठन को लेकर वो विधानसभा चुनाव में अपनी नैया कैसे पार लगाएंगे.

जद(यू) ने भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद घोषणा की है कि गैर–सांप्रदायिक शक्तियों की एकजुटता के लिये जद(यू) किसी भी गठबंधन के साथ जाने को तैयार है. झारखंड में जद(यू) और राजद की कठिनाई यह है कि झारखंड में इनका संगठन कुछ ही इलाकों तक सीमित है. विधानसभा चुनाव में जाने के लिए गठबंधन उनके लिए मजबूरी है. वैसे भी दोनों दलों की पृष्ठभूमि बिहार से जुड़ी हुई है. झारखंड प्रदेश राजद इन दिनों झारखंड में दिनो–दिन कमजोर होता जा रहा है.

संगठन की मजबूती की बात तो दूर, पार्टी व लालू के प्रति वफादर कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं. संगठन धीरे–धीरे अपनी ताकत खोता जा रहा है. इसका प्रमाण है यह है कि जब पहले लालू प्रसाद रांची आते थे, तो सैकड़ों समर्थकों की भीड़ उनके रांची छोड़ने तक पीछे–पीछे घूमती रहती थी, लेकिन पिछले दिनों जब लालू रांची आए और दो दिनों तक रुके. लेकिन लालू के इर्द गिर्द एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं नज़र आए. लोकसभा चुनाव के बाद झाविमो भी गठबंधन की तलाश में है. इस संदर्भ में कांग्रेस के साथ उसकी बातचीत होने की भी चर्चा है. कांग्रेस को साथ लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में झाविमो मैदान में उतरा था और पहली बार में ही उसने अच्छी सफलता हासिल की थी. उसके

feedback@chauthiduniya.com